R.N.I. NO.HIN/2002/8718 M.P./BHOPAL/642/2021-23

• नशा तस्करी पर बड़ी चोट • बिगड़े वनों में बढ़ी हरियाली

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

www.akshnews.com

अगले दो दशक की तैयारी

वर्ष 19, अंक-8 16 से 31 जनवरी 2021 पृष्ठ-48 मूल्य 25 रूपये

डायरियों का भ्रम जाल...!

We Deal in
Pathology & Medical
Equipments
Anu Sales Corporation
Add: Ground Floor, 17/1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
M. : 9329556524, 9329556530, E-mail : ascbhopal@gmail.com

इस अंक में

योजना

9 | पानी बंटवारे का विवाद

केन-वेतबा लिंक परियोजना के मप्र व उप्र के बीच पानी बंटवारे का विवाद सितंबर में बनाई गए केंद्रीय जल प्राधिकरण के हस्तक्षेप के बाद भी अब तक निपट नहीं पाया है। मप्र-उप्र और केंद्र में भाजपा की सरकारें हैं...

राजपथ

10-11 | मिशन मोड में भाजपा

भाजपा के बारे में एक बात ख्यात है कि वह अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को हमेशा सक्रिय रखती है। मप्र भाजपा की सक्रियता साल भर चलती रहती है। लेकिन इस बार भाजपा अजब मूड में नजर आ रही है।

विडंबना

14 | जंगलों में पहुंचा बर्ड फ्लू

कोरोना महामारी के बीच देश में बर्ड फ्लू ने अब तेजी से पैर पसारना शुरू कर दिया है। देश के 10 राज्यों में एवियन इन्फ्लूएंजा फैलने की पुष्टि हुई है। वहीं, अब बर्ड फ्लू का संक्रमण जंगलों तक भी पहुंच गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने बताया है...

मेट्रो

18 | पटरी पर इंदौर मेट्रो

मप्र में नगरीय निकाय चुनाव की हलचल के बीच मेट्रो का जिन्न फिर निकल आया है। 10 महीने से मेट्रो प्रोजेक्ट बंद पड़ा था, जिस पर अब फिर से काम शुरू हो गया है। मेट्रो ट्रेन को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने हैं। दोनों ही दल नगरीय निकाय चुनाव में इस मुद्दे को भुनाने की तैयारी...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

मप्र की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों 2019 में आयकर छापे के दौरान मिली एक हवाला डायरी चर्चा में है। डायरी की जांच के बाद सीबीडीटी की रिपोर्ट को आधार बनाकर केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 3 आईपीएस और 1 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी सहित अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया है, उससे हंगामा मचा हुआ है। सवाल उठता है कि क्या किसी डायरी को आधार बनाकर किसी को दोषी माना जा सकता है।

15

29

40

45

राजनीति

30-31 | दिशाहीन विपक्ष

सत्तापक्ष की तरह विपक्ष की भी एक प्रकृति होती है। दुख की बात है कि भारतीय राजनीति में पिछले 5-6 वर्षों के दौरान विपक्ष की इस प्रकृति में विकृति पनपती दिख रही है जिसमें विरोध नीतियों के बजाय व्यक्ति केंद्रित हो गया है। इसमें देशहित के खिलाफ मुखरता को भी लोकतंत्र की लड़ाई...

महाराष्ट्र

35 | रोजाना 6 आत्महत्या

एक तरफ देश में कृषि बिल को लेकर किसान आंदोलन चल रहा है तो वहीं महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले साल 2020 के 11 महीनों में करीब 2270 किसानों ने महाराष्ट्र में आत्महत्या की है। यानी हर दिन लगभग 6 किसानों ने आत्महत्या की है।

बिहार

38 | उलटफेर के लिए बेकरार!

बिहार में नीतीश सरकार को बने डेढ़ महीना भी नहीं हुआ कि भाजपा-जेडीयू के बीच तल्खी इस कदर बढ़ गई है कि अब राज्य में सत्ता के परिवर्तित होने की अटकलें भी बढ़ती जा रही हैं। इसका कारण है कि न तो भाजपा को नीतीश कुमार पसंद आ रहे...

6 -7 अंदर की बात
40 पड़ोस
41 विदेश
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

शराब को राजस्व या मौत और हिंसा का स्रोत कहें?

किसी शायर ने लिखा है...

मयखाने से पूछा आज इतना सन्नाटा क्यों है,
बोला, साहब लहू का दौर है शराब कौन पीता है।

दरअसल, भारतीय समाज में यह मान्यता है कि शराब सहित अन्य नशा सारी बुराईयों के जनक हैं। लेकिन विडंबना यह है कि सरकारों को नशे के कारोबार (शराब, भांग आदि के ठेकों) से बड़ा राजस्व प्राप्त होता है। मप्र में शराब से सालाना तकरीबन 12 हजार करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। इसलिए सरकार के सामने मजबूरी है कि वह चाहकर भी शराब को बैन नहीं कर पा रही है। इसका फायदा माफिया उठा रहे हैं और सरकार के समानांतर शराब का अवैध कारोबार चला रहे हैं। यही अवैध कारोबार जानलेवा साबित हो रहा है। आजकल देश में जहरीली शराब से मौतों की खबर रोजमर्रा की बात हो गई है। महाकाल की नगरी उज्जैन में जहरीली शराब पीने से 16 लोगों की मौत के बाद शासन-प्रशासन ने जिस तरह की कठोरता दिखाई थी, उससे लगा था कि मप्र में अवैध शराब को नेस्तानाबूद कर दिया जाएगा। लेकिन मुरैना में जहरीली शराब से 24 लोगों की मौत ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या शराब को राजस्व या मौत और हिंसा का स्त्रोत कहें? चूंकि ये मौतें गरीब लोगों की होती हैं इसलिए सत्ता और प्रशासन के लोगों में संवेदनशीलता कम ही नजर आती है। सरकार एक-दो जिम्मेदार लोगों को निलंबित करके कर्तव्य की इतिश्री कर लेती है। जबकि निलंबन कोई सजा नहीं है। यदि निलंबन सजा होती तो तीन महीने पहले उज्जैन में विषैली शराब से 16 मजदूरों की मौत हुई थी, गोया इसकी पुनरावृत्ति इतनी जल्दी नहीं हुई होती? अक्सर जहरीली शराब के लिए दोषी स्थानीय लोगों को ही ठहरा दिया जाता है लेकिन इस शराब के निर्माण में कहीं न कहीं शराब ठेकेदारों का भी हाथ हो सकता है। क्योंकि मुनाफे की हवस देशी शराब में जहर मिलाने का काम कर देती है। सरकारें इस ओर ध्यान नहीं देतीं। तमाम दावों और घोषणाओं के बावजूद देश में जहरीली शराब मौत का पर्याय बनी हुई है। न तो इसके अवैध निर्माण का कारोबार बंद हुआ है और न ही बिक्री पर रोक लग पाई है। नतीजतन हर साल जहरीली शराब से सैंकड़ों लोग बेमौत मारे जाते हैं। लेकिन तमाम हो-हल्ला मचने के बावजूद राज्यों के शासन-प्रशासन ने हादसों से कोई सबक नहीं लिया। शराब के कारण घर के घर बर्बाद हो रहे हैं और इसका दंश महिलाओं और बच्चों को झेलना पड़ रहा है। साफ है, शराब के सेवन का खामियाजा पूरे परिवार और समाज को भुगतना पड़ता है। शराब के अलावा युवा पीढ़ी कई तरह के नशीले ड्रग्स का भी शिकार हो रही है। लेकिन सरकारें नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने में विफल हो रही है। बिहार, गुजरात सहित जिन राज्यों में शराबबंदी है, वहां की स्थिति देखकर यह तो कहा जा सकता है कि शराबबंदी से नशाखोरी नहीं रुक सकती है। इसलिए सरकार को नशे का अवैध कारोबार करने वालों के स्रोत को नेस्तानाबूद करना होगा। मप्र में पिछले कुछ महीने से माफिया और तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। उसके बावजूद अवैध शराब का गोरखधंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल, यह गोरखधंधा सफेदपोश और प्रशासन की मिलीभगत से चल रहा है। इसलिए सरकार को इस गठजोड़ को खत्म करना होगा। वरना राजस्व के फेर में हिंसा और मौत का तांडव चलता रहेगा और सरकार शोक व्यक्त करती रहेगी।

-राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 19, अंक 8, पृष्ठ-48, 16 से 31 जनवरी, 2021

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
मुंबई :- ऋतेन्द्र माथुर, **कोलकाता:**- इंद्रकुमार,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, टी.पी. सिंह, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (विदिशा) ज्योत्सना अनूप यादव

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी-फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : 39 श्रुत्रि सिलटर निपानिया, इंदौर मोबाइल - 7000123977

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

कमलनाथ को मौका

सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव रहे अहमद पटेल के निधन के बाद पार्टी को शिद्दत से उनके उत्तराधिकारी की तलाश है। कमलनाथ के सामने अब भी खुला मैदान है और वो चाहें तो मप्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी की ही तरह अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को पछाड़कर पटेल की जगह ले सकते हैं।

● **प्रशांत शर्मा,** इंदौर (म.प्र.)

थानों में कैमरे लगना सही

प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री ने अफसरों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है, वहीं दूसरी तरफ अदालत ने प्रदेश के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है। जिन लोगों की शिकायतें हैं कि पुलिस उनकी रिपोर्ट नहीं लिखती है, इससे उन्हें संतुष्टि मिलेगी।

● **रामनारायण सिसोदिया,** भोपाल (म.प्र.)

मप्र के किसान खुश हैं

मप्र में इस समय सीमांत व छोटे किसान मिलाकर कुल 1.10 करोड़ काश्तकार हैं। इनमें से 50 लाख किसानों पर कर्ज है। लेकिन उसके बावजूद किसान खुशहाल हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से प्रदेश का किसान लाभान्वित हो, इसका बेहतर प्रबंधन शिवराज सरकार द्वारा किया गया।

● **नीतेश पुरोहित,** सीहोर (म.प्र.)

उम्मीदों का साल है 2021

साल 2021 एक नई उम्मीद के साथ शुरू हुआ है। निश्चित ही चुनौतियों का चक्रव्यूह टूटेगा। इस साल हमें कोरोना को हराकर उस पर विजय प्राप्त करनी होगी। देशभर में वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। इसके साथ ही देश की जनता में इस बात की खुशी है कि कोरोना से लड़ने के लिए अब हम भी तैयार हैं। वर्ष 2020 हताशा–निराशा, टूटन, विरोध प्रदर्शनों का ऐसा गवाह रहा है, जो शायद ही कभी और इस दौर में भी शायद ही कहीं देखने को मिला। कोविड–19 महामारी के बड़े सबक में यह भी रहा है कि दुनिया में जिसने इसकी कम परवाह की, उसे उतना ही झेलना पड़ा। भारत में कोरोना ने सिर्फ मौतें ही नहीं दी हैं, बेरोजगारी, आर्थिक संकट के साथ सामाजिक व मानसिक विकारों में भी वृद्धि की है।

● **आशा सोनी,** ग्वालियर (म.प्र.)

कांग्रेस के हालात सुधरेंगे?

पिछले लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी जिस तरह पार्टी अध्यक्ष पद छोड़कर गए थे उससे लगता था कि वह जल्दी लौटने वाले नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि अब उनके परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा। उसी बैठक के विस्तार में सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बन गईं। फिर राहुल गांधी ने डेढ़ साल पहले ऐसा क्यों कहा था? क्या उनको और उनके परिवार को उम्मीद थी कि राहुल का ऐसा बयान आते ही कांग्रेस में हाहाकार मच जाएगा। देशभर से 'राहुल लाओ देश बचाओ' की गूंज सुनाई देगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं।

● **प्रताप मंडल,** शिवपुरी (म.प्र.)

पीड़िता को मिलेगा न्याय

लव जिहाद के खिलाफ कानून में बनाकर प्रदेश की सरकार ने अच्छा कदम उठाया है। इसमें बहला–फुसलाकर, धमकी देकर जबर्दस्ती धर्मांतरण और शादी करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। इस कानून के तहत पीड़ित महिला और पैदा हुए बच्चे को भरण–पोषण का हक हासिल करने का प्रावधान किया गया है। आरोपी को ही निर्दोष होने के सबूत प्रस्तुत करना होगा। सरकार के इस कानून की कई जगहों पर सराहना हो रही है।

● **महेंद्र सोलंकी,** इंदौर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन–1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ–02, 03, एमपी नगर, भोपाल

ऑल इज नॉट वेल

महाराष्ट्र में जोड़-तोड़कर भाजपा को सत्ता से बाहर करने में सफल रहे शिवसेना-कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन में सबकुछ सामान्य न होने की खबरें अब जोर पकड़ने लगी हैं। हालांकि गठबंधन के तीनों धटक दलों का शीर्ष नेतृत्व 'ऑल इज वेल' का दावा करते रहे हैं, लेकिन सरकार की गाड़ी साफ तौर पर लड़खड़ाती दिखने लगी है। कुछ अर्सा पहले गृह विभाग में हुए तबादलों को मुख्यमंत्री ठाकरे रोकने पर मजबूर कर दिए गए थे क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी ने बगैर उनकी सलाह लिए किए गए इन तबादलों पर असंतोष जता डाला था। इसके बाद गतवर्ष जुलाई महीने में कांग्रेस कोटे के मंत्री नितिन राउत को तब बैकफुट पर आना पड़ा था जब राज्य की चार पावर कंपनियों में 16 कांग्रेस सर्मथकों को उन्होंने डायरेक्टर पद पर नियुक्त कर शिवसेना और एनसीपी को नाराज कर दिया था। बाद में इन सभी नियुक्तियों को राउत कैंसिल करने पर मजबूर हो गए थे। अब खबर है कि मुंबई कांग्रेस के नए अध्यक्ष अशोक जगताप के नारे 'मेरी मुंबई, मेरी कांग्रेस' से शिवसेना खासी नाराज है। दरअसल शिवसेना की असली ताकत मुंबई है जहां अगले वर्ष नगरपालिका के चुनाव होने है। मुंबई महानगरपालिका देश की सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा बजट वाली संस्था है। ऐसे में अशोक जगताप के इस कदम से गठबंधन में तनाव की स्थिति है।

राहुल की छवि में निखार

भले ही भाजपा का पूरा जोर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को पार्टटाइम राजनेता और फुलटाइम 'पप्पू' साबित करने में लगा रहता हो, लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय में राहुल गांधी की छवि में निखार आने के समाचार हैं। जानकारों का दावा कि राहुल भारत की विदेश नीति को लेकर खासे सजग रहते हैं। अंतरराष्ट्रीय मसलों में गहरी रूचि रखने वाले राहुल वर्तमान सरकार द्वारा विदेश नीति में किए जा रहे बदलावों पर अपनी पैनी नजर बनाए रखते हैं। विशेषकर राहुल का फोकस उन मुद्दों पर रहता है जो दशकों से चली आ रही भारत की गुट निरपेक्ष नीति का वर्तमान सरकार द्वारा पालन नहीं किए जाने से जुड़े हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी ने दिल्ली के जिमखाना क्लब में एक चाय पार्टी का आयोजन किया। इस चाय पार्टी में विदेशी राजनायिकों को आमंत्रित किया गया था। खबर है कि पूरे दो घंटे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर इन राजदूतों संग अपने विचार साझा किए। राहुल के करीबियों का दावा है कि विदेशी राजनायिकों ने राहुल गांधी के विचारों को गंभीरता से सुना, उनके साथ अपने विचार शेयर भी किए और जटिल अंतरराष्ट्रीय मामलों में राहुल की पकड़ के कायल भी हो गए।

खेल संभावना का

नीतीश कुमार भाजपा की मेहरबानी से मुख्यमंत्री बन तो जरूर गए पर वे इस पारी में ज्यादा खुश नहीं दिख रहे। अपने चहेते आरसीपी सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जो 2010 में सियासत में आने से पहले उप्र में आईएएस अफसर थे। सबसे बड़ी खूबी नीतीश के जिले का निवासी और उनकी जात का होना मानी जा रही है। इससे पहले नीतीश ने जब मुख्यमंत्री पद छोड़ा था तो महा दलित जीतनराम मांझी को उत्तराधिकारी बनाया था। जिनके साथ बाद में नीतीश की कटुता भी हुई थी। बहरहाल अब तो भाजपा ने अरुणाचल में नीतीश की पार्टी के छह विधायकों को तोड़कर साफ कर दिया कि चलेगी बड़े भाई की ही। सियासी असमंजस को राजद के श्याम रजक ने यह बयान देकर और बढ़ा दिया कि जद (एकी) के 17 विधायक राजद में आने के इच्छुक हैं। जद (एकी) ने इसे कोरी अफवाह बेशक बता दिया पर रांची जेल में बैठे लालू यादव के बारे में कही जा रही इस बात में कोई संदेह नहीं कि उन्होंने पार्टी नेताओं को नीतीश पर कोई वार नहीं करने की हिदायत दी है। राजनीति में नई संभावना को कभी भी नकारा नहीं जा सकता है। अब देखना यह है कि बिहार की राजनीति में नई संभावना का यह खेल क्या गुल खिलाता है।

अभी से बनने लगा गठबंधन

उप्र में चुनाव अगले साल होने हैं पर उससे एक साल पहले ही राज्य में राजनीतिक ध्रुवीकरण शुरू हो गया है। बड़ी पार्टियां हालांकि अभी चुपचाप तमाशा देख रही हैं पर छोटी पार्टियों ने पोजिशनिंग शुरू कर दी है। राज्य की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वह अकेले लड़ेगी। हालांकि चुनाव के समय उसका कोई तालमेल हो सकता है। अजित सिंह की राष्ट्रीय लोकदल या इस जैसी किसी दूसरी छोटी क्षेत्रीय पार्टी के साथ सपा का तालमेल हो सकता है। शिवपाल सिंह यादव की पार्टी का सपा में विलय भी संभव है। बहुजन समाज पार्टी इस बार अकेले लड़ेगी और अभी तक की स्थितियों से लग रहा है कि कांग्रेस भी अकेले ही लड़ेगी। चुनाव से एक साल पहले सबसे पहला गठबंधन बनाने का ऐलान भाजपा की पुरानी सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने की है। इसके नेता ओमप्रकाश राजभर ने भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात की। दोनों ने अगला चुनाव मिलकर लड़ने का ऐलान किया है।

प्रयास विफल होंगे!

असम में चार महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले विपक्षी एकता की कोई कोशिश सिरे नहीं चढ़ रही है। भाजपा के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ने के कांग्रेस के प्रयासों को सिर्फ एक पार्टी का समर्थन मिला है। बदरूद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ ने कांग्रेस के प्रयासों का समर्थन किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी अब उनसे दूरी बनाने लगी है। कांग्रेस को ऐसी फीडबैक मिली है कि अजमल की पार्टी के साथ गठबंधन बनाने पर भाजपा से आमने-सामने के मुकाबले में भाजपा को ध्रुवीकरण कराने में आसानी हो जाएगी। भाजपा अजमल के खिलाफ आसानी से बहुसंख्यक हिंदू वोटों को गोलबंद कर सकती है। इस चिंता में कांग्रेस ने अजमल से दूरी बनाई है। कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र सिंह ने कहा है कि स्थानीय नेताओं की फीडबैक ली जा रही है और उस आधार पर पार्टी आलाकमान फैसला करेगा। तरुण गोगोई जब जीवित थे तब उन्होंने सभी विपक्षी पार्टियों को साथ लाने का प्रयास किया था।

मंत्रीजी को दी सीख

राजनीति का रंग कुछ ऐसा होता है कि यह जिस पर चढ़ता है वह अपने आपको सर्वग्य मान लेता है। उसकी यही सर्वग्यता कभी-कभी भारी पड़ जाती है। मप्र की राजनीति में इन दिनों एक मंत्रीजी इसी सर्वग्यता के रोग से ग्रसित हैं। अपनी पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में शामिल होने के बाद से ही मंत्रीजी प्रदेश के सबसे कमाऊ विभाग के मालिक बने हुए हैं। आलम यह है कि मंत्रीजी शासन, प्रशासन और पार्टी संगठन की जुगलबंदी को दरकिनार कर अपनी मनमानी में जुटे हुए हैं। यानी मंत्रीजी के विभाग से पार्टी के लिए जो फंड जाता है वे उस पर भी कुंडली मारकर बैठ गए हैं। मंत्रीजी की इस नीयत से संघ, संगठन, सरकार और विभागीय अफसर भी परेशान हैं। दरअसल, माननीय को लक्ष्मीजी की कृपा पाने का चस्का इस कदर लगा है कि वे मंत्री पद की मर्यादा का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। हद तो यह है कि वे लक्ष्मीजी की कृपा पाने के लिए कनिष्ठ अफसरों के सामने भी मुंह फाड़ लेते हैं। मंत्रीजी की इस करतूत से विभाग की बदनामी हो रही है। विगत दिनों लक्ष्मीजी की कृपा बढ़ाने के लिए मंत्रीजी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की तो विभाग के बड़े साहब ने उन्हें सीख देते हुए कहा कि माननीय, **आप मर्यादा में रहें।** कनिष्ठ अधिकारियों से बात करने से लक्ष्मीजी की कृपा बरसे या न बरसे आपकी साख जरूर गिरेगी। बताते हैं साहब की बात सुनकर मंत्रीजी को भी अपनी गलती का अहसास हो गया है।

दामाद जी की दादागिरी

गायक अरविंदर सिंह का यह गीत तो आपने सुना ही होगा... 'सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में, मैं पी गया मिला के जवानी शराब में।' कुछ ऐसा ही कारनामा विगत दिनों एक आईएएस अधिकारी ने किया। दरअसल, कई जिलों की कलेक्टरी कर चुके साहब इन दिनों राजधानी में सुशोभित हैं। एक तो ब्यूरोक्रेट्स उस पर साहब सरकारी दामाद भी हैं। ऐसे में साहब के रुतबे का अंदाजा सहज में लगाया जा सकता है। अब रुतबेदार साहब अगर शराब पीकर बहक जाते हैं तो इसमें उनका कसूर क्या है? दरअसल, विगत दिनों साहब एक रेस्टोरेंट में जाम से जाम टकराने पहुंचे। साहब ने एक-दो जाम तो हिसाब से पिए, लेकिन उसके बाद वे इस कदर बहके कि उन्हें होश नहीं रहा कि वे कितना पी गए। फिर क्या था? रसूखदार साहब को नशा इस कदर चढ़ा कि वे दादागिरी पर उतर गए। सरकारी दामाद के बहकने की खबर सुन उन्हें सही सलामत घर पहुंचाने के लिए पुलिस के कई अधिकारी तत्काल पहुंच गए। लेकिन नशे में डूबे साहब ने सबको ऐसी-ऐसी खरी-खोटी सुनाई कि सबके होश उड़ गए। मामला आउट ऑफ कंट्रोल होता देख मंत्रीजी के पीए मौके पर पहुंचे और साहब को जैसे-तैसे मनाकर घर पहुंचाया। सुबह जब साहब को होश आया तो रात का वाकया सुनकर वे चकित हो गए और आव देखा न ताव तत्काल 15 दिन की छुट्टी पर चले गए। सबसे अच्छी बात यह रही कि दामाद जी की दादागिरी की बात कुछ कानों तक ही पहुंच पाई।

पोस्टिंग का इंतजार

विगत दिनों मप्र पुलिस के वरिष्ठ अफसरों को पदोन्नत किया गया। पदोन्नति मिलते ही अफसर हर्षित हुए लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी मायूसी बढ़ने लगी। दरअसल, जिन अफसरों को पदोन्नत किया गया है, उन्हें नई पदस्थापना अभी तक नहीं मिली है। ऐसे में ये अफसर न इधर के रहे, न उधर के। यानी इन्हें किसी भी मीटिंग में आमंत्रित नहीं किया जाता है। अपने कार्यालय में बिना काम के कुर्सी तोड़ रहे इन अफसरों में निराशा का भाव बढ़ने लगा है। कुछ अफसर तो इस कदर मायूस हैं कि वे कहने लगे हैं कि भाई, ऐसी पदोन्नति किस काम की। न तो कोई हमें बैठकों में बुलाता है और न ही कोई हमारी सुनता है। गौरतलब है कि मप्र पुलिस में उच्च पदों पर तय संख्या से अधिक अफसर हैं। ऐसे में कुछ अफसरों के पास काम का भार है तो कुछ बेकाम हैं। ऐसे में नए-नए पदोन्नत हुए अफसर नई पदस्थापना की आस लगाए हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक हमें कोई पदस्थापना नहीं मिलती है हम किसी मूर्ति से कम नहीं हैं। हमारी हैसियत तो तभी होगी, जब हम किसी जिम्मेदारी भरी कुर्सी पर विराजमान होंगे। अब देखना यह है कि उच्च पदों पर पदोन्नत हुए अफसरों को कब तक नई पदस्थापना मिलती है।

मामा ने उड़ाए छक्के

मप्र की राजनीति के सर्वमान्य मामा ने इन दिनों अच्छे-अच्छों की नींद उड़ाकर रख दी है। आलम यह है कि मामा का फॉर्म देखकर अच्छे-अच्छे खिलाड़ी दुबक गए हैं। मामा माफिया, अपराधियों, तस्करों और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जिस तरह आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, उससे प्रदेशभर में हलचल मची हुई है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के नौकरशाह हैरान-परेशान हैं। क्योंकि माफिया, अपराधियों, तस्करों और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई में थोड़ी भी कोताही मिलने पर मामा नौकरशाहों को टारगेट कर रहे हैं। मामा के फॉर्म ने अफसरों की लाइन लेंथ बिगाड़ दी है। अफसर जिस भी लेंथ पर बॉल डाल रहे हैं, मामा छक्के उड़ा रहे हैं। उस पर मामा यह कहकर अफसरों की खिल्ली उड़ा रहे हैं कि मैं जब भी अफसरों को फटकार लगाता हूं, पब्लिक हंसती है। उधर, कई अफसर यह दावा कर रहे हैं कि मामा नौकरशाहों के खिलाफ कितना भी दहाड़ें, लेकिन उनका कार्यकाल उनके लिए स्वर्णकाल रहता है। हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा हो जाता है। इसलिए अगर मामा अफसरों को मंच से फटकारते भी हैं तो अफसर बुरा नहीं मानते।

नहीं बनी बात

प्रदेश में हजारों अधिकारी-कर्मचारी पदोन्नति की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन उनकी आस पर बार-बार पानी फिर जाता है। दरअसल, पदोन्नति में आरक्षण का मामला सुलझ नहीं पाने के कारण अधिकारी-कर्मचारी बिना पदोन्नति के ही रिटायर हो रहे हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण के मामले को राज्यों के पाले में डाल दिया है। यानी राज्यों को निर्णय लेना है कि वे अपने यहां पदोन्नति में आरक्षण लागू करते हैं या नहीं। इसको लेकर मप्र में विगत दिनों पदोन्नति में आरक्षण के लिए बनाई गई समिति की बैठक हुई। लेकिन बैठक में सहमति नहीं बन पाई। इससे एक बार फिर पदोन्नति की आस लगाए बैठे अफसरों की मंशा पर पानी फिर गया है। कई अफसरों को उम्मीद थी कि इस अंतिम बैठक में पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था पर कोई न कोई निर्णय ले लिया जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ऐसे में जूनियर अधिकारी फिलहाल सीनियर नहीं बन पाएंगे। कई अधिकारी पदोन्नति की आस लिए ही रिटायर हो जाएंगे।

नीतीश कुमार का आदेश अब उनकी अपनी सरकार में नहीं चलता है। उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले सावधानीपूर्वक सोचना चाहिए था। अब वे भाजपा के जाल में फंस गए हैं। उन पर भाजपा का नियंत्रण हो गया है।

● **राबड़ी देवी**

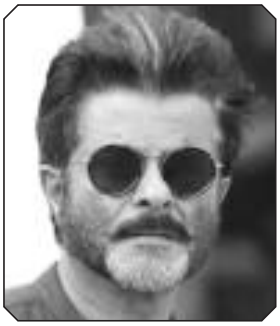

मैंने अपने फिल्मी कैरियर में कई फिल्में सिर्फ पैसों के लिए की हैं। दरअसल, उस समय मेरे परिवार को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, तो मुझसे जो हुआ मैंने किया और मुझे स्वीकार करने में भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मैं और मेरा परिवार आज बेहद खुश हैं कि वो बुरा वक्त अब पीछे छूट गया है। परिवार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं।

● **अनिल कपूर**

सिडनी टेस्ट में टीम इंडिया के पराक्रम के आगे ऑस्ट्रेलियाई टीम की बोलती बंद हो गई। खेल के पांचवे दिन ऑस्ट्रेलिया को विश्वास था कि वह टेस्ट मैच जीत जाएगी, लेकिन हनुमा विहारी और आर अश्विन ने दिखा दिया कि भारत का पराक्रम क्या है। अगर टीम में फिटनेस प्रोब्लम नहीं रहता तो भारत यह टेस्ट जीतकर बढ़त बना लेता।

● **सुनील गावस्कर**

हम उप्र में आए हैं, हम यहां के स्कूलों को देख रहे हैं। यहां के अस्पतालों को देख रहे हैं। ऐसी बदतर हालत में हैं कि अस्पतालों में बच्चे तो पैदा हो रहे हैं, लेकिन कुत्तों के बच्चे पैदा हो रहे हैं। भाजपा सरकार को शर्म आनी चाहिए।

● **सोमनाथ भारती**

लव जिहाद के खिलाफ धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश को लेकर अफवाह उड़ाई जा रही है। यह कानून प्यार करने वालों के खिलाफ नहीं है, बल्कि जो लोग धोखा खा रहे हैं यह कानून उनके लिए बहुत अच्छा है। बहुत से लोगों को इस कानून से परेशानी भी हुई है, लेकिन लोगों को यह समझना चाहिए कि कानून सिर्फ उनके लिए बने हैं, जिनको दिक्कत है। जो इंटरकास्ट मैरिज होती या हो रही है, उन पर यह लागू नहीं हुआ है। ये सिर्फ उन्हीं पर लागू है, जिन्होंने प्यार या शादी के नाम पर धोखा खाया है। जो इंटरकास्ट मैरिज के नाम पर धोखा खाते हैं या कोई और फ्रॉड उनके साथ होता है, इस तरह के कानून से उन्हें सहायता मिलेगी।

● **कंगना रनौत**

वाक्युद्ध

केंद्र सरकार किसानों को साधन संपन्न बनाना चाहती है। इसके लिए नया कृषि बिल लाया गया है। लेकिन कांग्रेस सहित कई पार्टियां किसानों को बरगला रही हैं। दरअसल, विपक्ष यह नहीं चाहता है कि भारत का किसान बदहाली से बाहर निकले। लेकिन सरकार किसानों को हर हाल में संपन्न बनाने में लगी हुई है।

● **नरेंद्र सिंह तोमर**

नया कृषि बिल किसानों के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात है। अगर बिल वाकई किसान हितैषी होता तो किसान इस तरह ठंडी में सड़क पर परेशान नहीं होते। किसान अगर बिल का विरोध कर रहे हैं तो सरकार को उसे हर हाल में रद्द करना चाहिए। कांग्रेस किसानों के साथ है और उनका किसी भी स्थिति में अहित नहीं होने देगी।

● **रणदीप सुरजेवाला**

पानी बंटवारे का विवाद

2008 से चल रही कवायद पड़ी थी ठंडे बस्ते में

केन-वेतबा लिंक परियोजना का खाका 2008 में तैयार किया गया था। लेकिन कुछ मंजूरियों के कारण मामला अटका रहा। फिर वर्ष 2012 में इस परियोजना पर चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि परियोजना पर समयबद्ध तरीके से अमल किया जाए। वर्ष 2016 में कुछ पर्यावरणीय मंजूरियां प्राप्त होने के साथ ही सरकार ने केन-बेतवा लिंक परियोजना पर अमल करना शुरू किया। केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना के संदर्भ में एक अन्य मुख्य आपत्ति थी। पन्ना टाइगर रिजर्व के 5500 हैक्टेयर से ज्यादा हिस्से का योजना क्षेत्र में आना। लेकिन नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने सशर्त इस पर अपनी सहमति दे दी है। वर्ष 2017 में फिर से परियोजना को लेकर चर्चा शुरू हुई। लेकिन परियोजना से उप्र और मप्र को पानी बांटने का विवाद फंस गया। परियोजना की समझौता शर्त के मुताबिक उप्र को रबी सीजन के लिए 700 एमसीएम पानी दिया जाना है, लेकिन उप्र सरकार इस सीजन के लिए 930 एमसीएम पानी की मांग कर दी, जिसके बाद मामला फंस गया था। लेकिन अब पानी बंटवारे के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के गठन से मामले का हल निकलने की संभावना बन गई है।

केन-वेतबा लिंक परियोजना के मप्र व उप्र के बीच पानी बंटवारे का विवाद सितंबर में बनाई गए केंद्रीय जल प्राधिकरण के हस्तक्षेप के बाद भी अब तक निपट नहीं पाया है। मप्र-उप्र और केंद्र में भाजपा की सरकारें हैं, लेकिन जल बंटवारे पर मप्र के हित पर कुठाराघात होने से मप्र अपनी बात पुरजोर तरीके से रख रहा है। मप्र 700 एमसीएम पानी नॉन मानसून में उप्र को देने के लिए तैयार है, लेकिन उप्र 750 एमसीएम पानी के लिए जिद कर रहा है। नॉन मानसून में उप्र को 50 एमसीएम अतिरिक्त पानी देने पर रंगवान बांध, अंतरिम जलग्रहण क्षेत्र और बरियारपुर स्टोरेज में लगभग 200 एमसीएम जल उत्तरप्रदेश को अतिरिक्त रूप से प्राप्त होगा। जिसको लेकर मप्र आपत्ति कर रहा है। इधर, इस मुद्दे पर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दोनों राज्यों को पानी बंटवारे पर 15 दिन में सहमति बनाने की नसीहत दी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि मप्र के हितों का ध्यान रखा जाएगा।

बीते दिनों केंद्रीय जल संसाधन मंत्री के साथ बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने कहा कि मप्र हमेशा से दूसरे राज्यों के हितों की परवाह करता रहा है, परंतु प्रदेश का अहित न हो इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। केन-बेतवा परियोजना से मप्र-उप्र को 700 एमसीएम पानी देने के लिए सहमत है। शीघ्र ही केंद्रीय मंत्री शेखावत के नेतृत्व में उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बातचीत कर योजना के गतिरोध को दूर किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री चौहान ने जल आवंटन को लेकर मप्र का पक्ष मजबूती से रखा। बैठक में ईस्टर्न राजस्थान नहर परियोजना सह पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना में मप्र एवं राजस्थान के बीच जल उपयोग को लेकर भी बातचीत हुई। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने निर्देश दिए कि 15 जनवरी से आगामी 15 दिनों में दोनों पक्ष निरंतर बातचीत कर हल निकालें। इस परियोजना की डीपीआर में प्रस्तावित बांध एवं बैराजों के लिए 50 प्रतिशत जल निर्भरता पर जल उपयोग की गणना की गई है। मप्र का कहना है कि इसे 75 प्रतिशत जल निर्भरता पर आंकलन के आधार पर पुनरीक्षित किया जाए।

मप्र की दौधन बांध पर 6590 एमसीएम जल उपलब्धता के आधार पर बांध से उप्र के लिए 700 एमसीएम जल सभी प्रयोजनों के लिए लिंक केनाल सहित नॉन मानसून के दौरान आवंटित करने पर सहमति है। लिंक केनाल द्वारा उप्र को प्रदत्त जल को शामिल करते हुए उप्र को आवंटित 1700 एमसीएम जल की एकाउंटिग बरियारपुर पिकअप वीयर पर की जाए। शेष संपूर्ण जल 2733 एमसीएम के उपयोग करने के लिए मप्र स्वतंत्र रहेगा।

परियोजना अंतर्गत उप्र गैर मानसून अवधि में दौधन बांध से नवंबर से मई माह तक 935 एमसीएम पानी चाहता है। वहीं राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने सुझाव दिया है कि परियोजना से नॉन मानसून मौसम में दौधन बांध पर उप्र को 750 एमसीएम तथा मप्र को 1834 एमसीएम जल दें। अभिकरण द्वारा दौधन बांध पर जल उपलब्धता 6188 एमसीएम मानी गई है। परियोजना के अंतर्गत समस्त तकनीकी एवं जल योजना डिजाइन केंद्रीय जल आयोग द्वारा दौधन बांध पर 6590 एमसीएम जल उपलब्धता के आधार पर की गई है एवं समस्त अनुमोदन इसी आधार पर किए गए है। यदि दौधन बांध पर जल उपलब्धता 6590 एमसीएम के स्थान पर 6188 एमसीएम मानी जाती है, उस स्थिति में भविष्य में मप्र को लगभग 400 एमसीएम जल की हानि होगी, साथ ही यदि 750 एमसीएम जल दौधन बांध से नॉन मानसून सीजन में उप्र को उपलब्ध कराया जाता है, उस स्थिति में रंगवान बांध, अंतरिम जलग्रहण क्षेत्र और बरियारपुर स्टोरेज में लगभग 200 एमसीएम जल उप्र को अतिरिक्त रूप से प्राप्त होगा।

राष्ट्रीय नदी विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) द्वारा प्रस्तावित 30 नदी जोड़ो परियोजनाओं में से एक केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना भी है। जिसमें मप्र एवं उप्र का बुंदेलखंड क्षेत्र शामिल है। मप्र में छतरपुर व पन्ना जिलों के सीमा पर केन नदी पर मौजूदा गंगऊ बैराज के अपस्ट्रीम में 2.5 किमी की दूरी पर डोढ़न गांव के पास एक 73.2 मीटर ऊंचा ग्रेटर गंगऊ बांध प्रस्तावित है। 212 किमी लंबी कांक्रीटयुक्त नहर के द्वारा केन नदी का पानी उप्र के झांसी जिले में बेतवा नदी पर स्थित बरुआ सागर में डाला जाना प्रस्तावित है। नदीजोड़ योजना के कार्य दल के अनुसार केन-बेतवा नदी जोड़ योजना में दो बिजली परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 72 मेगावाट होगी। संपर्क नहर के मार्ग में पड़ने वाले 6.45 लाख हैक्टेयर (1.55 लाख हैक्टेयर उप्र में एवं 4.90 लाख हैक्टेयर मप्र में) जमीन की सिंचाई के लिए 31960 लाख घन मीटर पानी इस्तेमाल होगा। इससे घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग के लिए 120 लाख घन मीटर पानी प्रदान किया जाएगा।

● **जितेंद्र तिवारी**

जिस तरह दूध का जला मट्ठा फूंक-फूंककर पीता है, उसी तर्ज पर 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथों मात खाई भाजपा अभी से मिशन 2023 की तैयारी में जुट गई है। भाजपा को मिशन मोड में देखकर कांग्रेस भी तैयारी कर रही है। दोनों पार्टियां आगामी नगरीय निकाय चुनाव को 2023 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मानते हुए चुनावी तैयारी कर रही हैं।

मिशन मोड में भाजपा

भाजपा के बारे में एक बात ख्यात है कि वह अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को हमेशा सक्रिय रखती है। मप्र भाजपा की सक्रियता साल भर चलती रहती है। लेकिन इस बार भाजपा अजब मूड में नजर आ रही है। दरअसल, 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से हारने के बाद भाजपा ने सबक लेते हुए अभी से 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आलाकमान ने अबकी बार 200 के पार का लक्ष्य निर्धारित कर चुनावी रणनीति बनाने के लिए शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा के साथ ही शिव प्रकाश को जिम्मेदारी सौंपी है। भाजपा की यह त्रिमूर्ति अभी से आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाकर संगठन को काम पर लगाएंगे। वहीं प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, सह प्रभारी पंकजा मुंडे व विश्वेश्वर टुडे मॉनीटरिंग करेंगे। उधर, भाजपा की तैयारियों को देखते हुए कांग्रेस ने भी चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के साथ ही प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक, सह प्रभारी सुधांशु त्रिपाठी, संजय कपूर, सीपी मित्तल और कुलदीप इंदौरा ने सक्रियता बढ़ा दी है।

गौरतलब है कि 2003, 2008 और 2013 में कांग्रेस को 75 सीटों के नीचे समेटने वाली भाजपा 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से पिछड़ गई। कांग्रेस को 114 और भाजपा को 109 सीटें मिली। इस कारण 15 साल बाद मप्र में कांग्रेस की सरकार बनी। जबकि भाजपा का वोट प्रतिशत (41.6 प्रतिशत) और कांग्रेस (41.5 प्रतिशत) से अधिक था। हालांकि 15 माह बाद ही कांग्रेस की सरकार गिर गई और एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बन गई है। अब भाजपा की रणनीति यह है कि वह 2023 में कांग्रेस का सूपड़ा साफ करना चाह रही है। इसके लिए अभी से रणनीतिक जमावट की जा रही है।

भाजपा सूत्रों का कहना है कि पार्टी अभी से मिशन 2023 की तैयारी में इसलिए जुटी हुई है कि आलाकमान ने आगामी विधानसभा चुनाव में 200 से अधिक सीटें जितने का लक्ष्य निर्धारित किया है। गौरतलब है कि 2018 में भी भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अबकी बार 200 के पार का नारा दिया था। मप्र विधानसभा चुनाव तक भाजपा की तरफ से इस नारे को खूब हवा दी गई और दावा किया गया कि भाजपा इस बार सीटों की आंकड़ा 200 पार करेगी। 28 नवबंर 2018 को हुई बंपर वोटिंग के बाद लगा कि भाजपा का दावा हकीकत में बदल सकता है, लेकिन भाजपा 109 पर सिमटकर रह गई। दरअसल, भाजपा ने यह लक्ष्य इसलिए निर्धारित किया है कि क्योंकि मप्र विधानसभा की 230 सीटों में से 207 ऐसी सीटें हैं जिनको भाजपा कभी ना कभी जीत चुकी है।

भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी कहते हैं कि 2018 में भाजपा ने इसी आधार पर 200 पार का नारा दिया था, लेकिन पार्टी बहुमत के आंकड़े (116) को भी नहीं छू पाई। इसके पीछे वजह थी रणनीतिक कमजोरी और अतिविश्वास। इसलिए भाजपा आलाकमान ने इस बार 3 साल पहले से ही चुनावी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है।

मप्र में भले ही अभी विधानसभा चुनाव में 3 साल का समय बाकी हो लेकिन सियासी दलों की नजर में मप्र अभी से अहम हो गया है।

मंत्रियों की हार से सबक

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी चौथी पारी में रेटिंग प्रणाली लाने के पीछे वजह यह है कि वह चाहते हैं कि उन्हीं की तरह मंत्री भी मंत्रालय से लेकर जनता के बीच सक्रिय रहें। संघ के एक स्वयंसेवक कहते हैं कि शिवराज की रेटिंग प्रणाली से विकास को तो गति मिलेगी ही, साथ ही 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा मजबूत स्थिति में रहेगी। वह कहते हैं कि 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार की सबसे बड़ी वजह रही है 13 मंत्रियों की हार। वह कहते हैं कि शिवराज की तीसरी पारी में मंत्रियों की कार्यप्रणाली संतोषजनक नहीं रही थी। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के मंत्रिमंडल में उन्हें मिलाकर कुल 32 मंत्री थे। जिनमें से 27 ने चुनाव लड़ा था। वे अपनी 14 सीट बचाने में सफल रहे। भाजपा के लिए सदमे की बात यह हुई थी कि उसके 13 मंत्री तक अपनी सीट नहीं बचा सके हैं। अगर ये मंत्री अपनी सीट जीत जाते तो विधानसभा का नजारा अलग ही होता।

भाजपा और कांग्रेस ने मिशन 2023 के लिए अभी से जमावट तेज कर दी है। हाल ही में भाजपा और कांग्रेस में हुई राजनीतिक नियुक्तियों और सियासी जमावट ने जता दिया है कि मप्र भाजपा और कांग्रेस के लिए कितना महत्वपूर्ण है। भाजपा ने मिशन 2023 की जिम्मेदारी अपने तीन नेताओं शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और शिव प्रकाश को सौंपी है। ये तीनों रणनीति बनाकर समन्वय के साथ आलाकमान द्वारा दिए गए लक्ष्य का पाने के लिए कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री जहां शासन और प्रशासन के सहारे विकास की गंगा बहाकर जनता को भाजपा के पक्ष में करेंगे, वहीं वीडी शर्मा संगठन को चुस्त-दुरुस्त कर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करवाएंगे। साथ ही हर विधानसभा क्षेत्र में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेंगे।

उधर, मप्र में अब सत्ता और संगठन के समन्वय के सारे सूत्र राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश के हाथ होंगे। दरअसल, भाजपा ने राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश का केंद्र यानी हेड क्वार्टर भोपाल कर दिया है। साथ ही शिव प्रकाश को मप्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, प. बंगाल और महाराष्ट्र का प्रभार दिया गया है। शिव प्रकाश हर महीने भोपाल में उपस्थित रहेंगे, साथ ही यह किसी भी राज्य में दौरे के लिए जाएं, लेकिन फिर वापस भोपाल ही आएंगे। इससे मप्र में सत्ता-संगठन का केंद्र शिव प्रकाश हो जाएंगे। पार्टी के एक पदाधिकारी कहते हैं कि भाजपा संगठन और गृहमंत्री अमित शाह को मप्र में समन्वय की जरूरत महसूस हो रही थी। इस नजरिए से भी यह बदलाव किए गए हैं।

2023 में 200 के पार के लक्ष्य को पाने के लिए भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी अगले 3 साल के लिए पॉलिटिकल रोडमैप तैयार करेगी। इसके जरिए भाजपा प्रदेश के कमजोर इलाकों पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाने का काम करेगी। यानी भाजपा विपक्षी कांग्रेस के मजबूत माने जाने वाले किलों में सेंध लगाने की तैयार कर रही है। इसी सिलसिले में गत दिनों सीहोर में भाजपा के 2 दिन चले प्रशिक्षण वर्ग के बाद प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने कहा कि पार्टी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए

पॉलिटिकल रोडमैप बनाना जरूरी है। पार्टी अब कमजोर बूथ के लिए हर बूथ मजबूत अभियान चलाएगी। इसमें राजनीतिक गतिविधियों के जरिए लोगों को संगठित करने का काम किया जाएगा। साथ ही भाजपा के नेता और कार्यकर्ता किसान आंदोलन के कारण बन रही भ्रम की स्थितियों को दूर करने के लिए संवाद कार्यक्रमों को और गति देंगे। भाजपा किसान संवाद के जरिए किसानों के घर पहुंचकर किसान कानून के फायदे गिनाने का काम करेगी। नगर निकाय चुनाव में जीत के लिए अभी से रूपरेखा तैयार होगी प्रभारी और सह प्रभारी कार्यकर्ताओं से संवाद बनाने का काम करेंगे और इसके लिए जिलों का प्रवास होगा।

पॉलिटिकल रोडमैप के लिए शुरुआती 4 महीने के कार्यक्रम तैयार होंगे। दो दिन तक जिला अध्यक्ष के साथ बैठक करने के बाद प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने साफ तौर पर जता दिया है कि भाजपा मिशन 2023 को पूरा करने के लिए अभी से कमजोर क्षेत्र पर फोकस कर खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करेगी और जहां पर कांग्रेस मजबूत है वहां पर भाजपा को खड़ा करने का काम किया जाएगा।

भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी कहते हैं कि 2018 के चुनाव से सबक लेते हुए भाजपा ने इस बार नई रणनीति तैयार की है। मोदी और अमित शाह की नजर अब मप्र पर है। यही कारण है कि पार्टी में हाल ही में हुए बदलावों से साफ संकेत मिल गए हैं कि भाजपा 2023 और उसके बाद होने वाले 2024 के आम चुनाव को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। वह कहते हैं कि यही कारण है कि भाजपा में भी अब दिल्ली का दखल तेजी के साथ बढ़ गया है। पार्टी ने हाल ही में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश को मप्र का प्रभार सौंपा है। इसके अलावा पार्टी ने मुरलीधर राव को प्रदेश का प्रभारी बनाया है। राव के साथ ही पंकजा मुंडे और विश्वेश्वर को सह प्रभारी नियुक्त किया है। पार्टी के प्रभारी और सह प्रभारी अब जिलों का प्रवास कर कमजोर कड़ी मजबूत बनाएंगे। प्रदेश महामंत्री हरिशंकर खटीक का कहना है देश का केंद्र बिंदु मप्र को मानते हुए पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है।

मप्र में 2018 के चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस के मुकाबले कम सीटें हासिल कर सत्ता गंवा दी थी। लेकिन सिंधिया के दल बदलने के कारण भाजपा की डेढ़ साल बाद ही सत्ता में वापसी हो गई। अब पार्टी 2023 के चुनाव में कोई गलती नहीं करना चाहती है। यही कारण है कि अभी से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी जमावट शुरू हो गई है, ताकि ऐन चुनाव के मौके पर विपक्ष की चालों का मजबूती के साथ जवाब दिया जा सके।

● **कुमार राजेन्द्र**

मोर्चे पर अभी से मंत्री-विधायक

दरअसल, मप्र की राजनीति में 2018 का विधानसभा चुनाव ऐसी खुमारी दे गया है कि भाजपा-कांग्रेस के बीच घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 2 सालों से सत्ता का संग्राम अब जाकर थमा ही है कि दोनों पार्टियों को 2023 के विधानसभा चुनाव का टेंशन सताने लगा है। दोनों पार्टियों के विधायक अपनी स्थिति बेहतर बनाने के लिए अभी से मैदानी मोर्चा संभाल चुके हैं। दरअसल, 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस के लिए अप्रत्याशित रहे नतीजे विधायकों के टेंशन का बड़ा कारण बन गए हैं। भाजपा और कांग्रेस के साथ ही मौजूदा विधायकों ने अपनी सीट को बचाने के लिए अभी से चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है। ताकि सीट को कोई दूसरा भेद ना पाए। भाजपा, कांग्रेस से लेकर निर्दलीय विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में डेरा डाल वोटरों से संपर्क बढ़ाने में जुट गए हैं। विधायकों को अब अपने क्षेत्र की समस्याएं भी नजर आने लगी हैं।

वीडी ने काटी वंशवाद की बेल

मप्र भाजपा के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। अपनी टीम में वीडी ने नए चेहरों को शामिल कर वंशवाद की बेल को काट दिया है। टीम वीडी में सक्रिय नेताओं को तव्वजों दी गई है। यह इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में भाजपा युवा नेताओं को ही तवज्जो देगी। गौरतलब है कि कई वरिष्ठ नेताओं के बावजूद भाजपा आलाकमान ने वीडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अब शर्मा ने उसी नक्शे कदम पर चलते हुए संगठन विस्तार किया है। शर्मा ने भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष की कमान वैभव पंवार को सौंपी है। शर्मा की नई टीम में 30 साल बाद पार्टी में पीढ़ी परिवर्तन की झलक दिखाई दे रही है। इससे पहले स्व. सुंदरलाल पटवा ने भाजपा में नई पीढ़ी को लाए थे, जो अब तक सत्ता-संगठन में शीर्ष पदों पर है। कार्यकारिणी में ज्यादातर नए चेहरों को जगह दी गई है।

आखिरकार साढ़े चार साल बाद भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी में बदलाव हो गया है। लेकिन इससे सबसे बड़ा झटका सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को लगा है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की टीम में सिंधिया के एक ही समर्थक मदन कुशवाहा को जगह मिली है। उन्हें प्रदेश मंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दबदबा कायम हैं। प्रदेश कार्यकारिणी में 8 करीबी नेताओं को संगठन में पद मिला है। किसान मोर्चा के अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष भगत सिंह कुश्वाहा मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं। संगठन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा की पसंद का ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही संगठन और संघ में पैठ रखने वाले भी शर्मा की टीम में शामिल हैं। जबकि इस बार 2 उपाध्यक्ष और 3 प्रदेश मंत्री के पद बढ़ा दिए गए हैं। पिछली कार्यकारिणी में 10 उपाध्यक्ष और 9 प्रदेश मंत्री थे, लेकिन अब दोनों 12-12 हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कार्यकारिणी में पार्टी के सभी दिग्गज नेताओं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के करीबियों को जगह देकर संतुलन बनाया है। कार्यकारिणी में संघ की पंसद को भी शामिल किया है।

टीम वीडी 2023 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन के लिहाज से सामंजस्य बैठाने की कोशिश की गई है। टीम में युवा चेहरों को मौका दिया गया है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा और विजेश लूनावत प्रदेश कार्यकारिणी से बाहर कर दिए गए हैं। पूर्व मेयर आलोक शर्मा और राहुल कोठारी को इसमें शामिल किया गया है। खास बात ये रही कि सिंधिया समर्थक चेहरों को प्राथमिकता नहीं दी गई है। नई कार्यकारिणी में तीन विधायक और दो सांसद भी शामिल किए गए हैं।

मंत्रिमंडल विस्तार में जिन वरिष्ठ विधायकों को उम्मीद थी कि उन्हें संगठन में जगह मिलेगी, लेकिन उनकी जगह नए चेहरों पर भरोसा किया गया है। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला को कार्यकारिणी में नहीं लिया गया, लेकिन उनके करीबी राजेश पांडे को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह पूर्व मंत्री रामपाल सिंह, संजय पाठक और अजय विश्नोई भी जगह पाने में कामयाब नहीं हो सके। शिवराज सिंह चौहान के करीबी भोपाल के पूर्व महापौर आलोक शर्मा, महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष सीमा सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया है। जबकि प्रदेश मंत्री राजेश पांडे, ललिता यादव, लता वानखेड़े, प्रभुदयाल कुशवाहा भी मुख्यमंत्री के समर्थक माने जाते हैं।

नरेंद्र सिंह तोमर के खास सिंगरौली के जिला अध्यक्ष रहे कांतदेव सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी ग्वालियर के मदन कुशवाहा को प्रदेश मंत्री बनाया गया है। कैलाश विजयवर्गीय के करीबी जीतू जिराती और विधायक बहादुर सिंह सोंधिया प्रदेश मंत्री बने हैं। नरोत्तम मिश्रा के कोटे से मुकेश चौधरी को उपाध्यक्ष बनया गया है। हालांकि सांसद संध्या राय को उपाध्यक्ष बनाए जाने को लेकर कहा जा रहा है कि इन्हें संगठन में लेने के लिए नरोत्तम ने ही वीटो लगाया था। भाजपा के दो प्रदेश प्रवक्ताओं रजनीश अग्रवाल और राहुल कोठारी को प्रमोशन मिला है। रजनीश संगठन महामंत्री सुहास भगत और राहुल नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी हैं। भाजपा सूत्रों का कहना है कि सिंधिया समर्थकों को निगम-मंडलों में नियुक्तियां दी जाएंगी। हालांकि कयास यह लगाए जा रहे थे कि सिंधिया के 3-4 समर्थकों को एडजस्ट किया जाएगा। शर्मा ने पांच महामंत्रियों की नियुक्ति विधानसभा उपचुनाव से पहले कर दी थी। गौरतलब है कि फरवरी 2020 में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए वीडी शर्मा ने लगभग 11 महीने बाद अपनी टीम बनाई है। जिसमें भौगोलिक, जातिगत, गुटीय संतुलन पर भी खास ध्यान दिया गया है। संगठन के पुराने पदाधिकारियों में सिर्फ जीतू जिराती और पंकज जोशी की ही वापसी हुई है। महिला मोर्चे की प्रदेशाध्यक्ष रहीं सीमा सिंह की दस साल बाद संगठन में वापसी हुई है।

● **अरविंद नारद**

4 मोर्चों में प्रमोशन पाकर अध्यक्ष बने, 2 की नई एंट्री

कार्यकारिणी के अलावा 7 मोर्चों के अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है। इसमें से 4 अध्यक्ष तो प्रमोशन पाकर अध्यक्ष बने हैं। इसमें माया नारोलिया महिला मोर्चा में महामंत्री थी। इसी तरह दर्शन सिंह चौधरी किसान मोर्चा में उपाध्यक्ष थे। वैभव पवार युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष और रफत वारसी अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष थे। इन चारों को अध्यक्ष बनाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी भगत सिंह कुशवाहा एक बार फिर पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष बन गए हैं। जबकि पूर्व विधायक डॉ. कैलाश जाटव अनुसूचित जाति मोर्चा और अनुसूचित जनजाति मोर्चा कली सिंह भाबर को अध्यक्ष बनाया गया है। दोनों की मोर्चे में नई एंट्री है। दोनों नेता संघ के कोटे से बने हैं।

मशीनों से रेत खनन का अधिकार

मप्र शायद देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है, जहां पर नदियों में रेत खनन के काम में मशीनों के उपयोग की मंजूरी दी गई है। मशीनों के उपयोग की मंजूरी ठेकेदारों को स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा दी जा सकेगी। ठेकेदारों को दी जाने वाली इस सुविधा के लिए खनिज विभाग द्वारा कलेक्टरों को पत्र जारी किया जा चुका है। हालांकि मशीनों के उपयोग से नर्मदा नदी को अलग रखा गया है। हालांकि इस पत्र में कलेक्टरों को रेत खनन योजना का अनुमोदन करते समय रेत खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार नियम 2019 के दो नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखने को कहा गया है। इसकी वजह है तय दोनों नियमों का पालन होने पर ही सिया रेत खदान के लिए पर्यावरण अनुमति जारी करता है।

पहले नियम के प्रावधानों के मुताबिक नर्मदा नदी की स्वीकृत रेत खदानों से मशीनों द्वारा रेत खनन, लदान तथा भंडारण पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। अन्य नदियों में स्थित 5 हैक्टेयर क्षेत्रफल तक की खदानों में से रेत खनन, लदान तथा भंडारण स्थानीय श्रमिकों की समिति ही करेगी तथा 5 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली खदानों में रेत खनन आदि के कामों में स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। अन्य नदियों में रेत खनन के लिए मशीनों के उपयोग की अनुमति तथा खनन योजना और पर्यावरण स्वीकृति में प्राप्त मंजूरी के आधार पर दी जा सकेगी। दूसरे नियम के प्रावधानों मे केंद्र द्वारा जारी सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइंस 2016 के अनुसार 8 मामलों में रेत निकालना प्रतिबंधित रहेगा। एक, किसी पुल से 200 मीटर के भीतर। दो, किसी जलप्रदाय योजना या जल संसाधन योजना के 200 मीटर धारा के प्रतिकूल (अपस्ट्रीम) तथा डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों के भीतर। तीन, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा रेलवे लाईन के किनारों से 100 मीटर के भीतर। चार, किसी नहर, जलाशय या भवन से 50 मीटर। पांच, राजकीय राजमार्ग के किनारों से 50 मीटर तथा अन्य ग्रामीण सड़क के किनारों से 10 मीटर के भीतर। छह, कोई भी क्षेत्र, जो कि बाढ़ नियंत्रण हेतु निर्मित किए गए हैं, से निर्धारित दूरी के भीतर। सात, सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व के स्थल से 200 मीटर दूरी के भीतर। आठ, ऐसे क्षेत्र जो जिला कलेक्टर द्वारा पर्यावरणीय या अन्य कारणों से प्रतिबंधित घोषित किए गए हों। हालांकि उक्त नियम में यह भी कहा गया है कि यदि ठेकेदार आवेदन करता है तो प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमा के भीतर रेत खनन की अनुमति दिए जाने पर संबंधित प्रशासकीय विभाग से एनओसी प्राप्त होने पर विचार किया जा सकेगा।

मप्र आज भले ही बीमारू राज्य के कलंक से मुक्त हो गया है, लेकिन अवैध तरीके से रेत खनन की बीमारी ने राज्य को इस तरह ग्रसित कर लिया है कि हर साल सरकार को अरबों रुपए की चपत लगी है। खासकर खनन माफिया के निशाने पर नर्मदा नदी है। माफिया, मनी और मसल के जोर पर नर्मदा में अवैध खनन जोरों पर है। खनन माफिया को सफेदपोशों और अफसरों का संरक्षण मिला हुआ है। इस कारण सरकार की सख्ती के बाद भी नर्मदा में अवैध खनन रुके नहीं रुक रहा है।

एनजीटी ने इस बात पर चिंता जताई है कि नर्मदा सहित प्रदेश की नदियों में मशीनों से रेत की खुदाई की जा रही है। गौरतलब है कि नर्मदा नदी में मशीनों के जरिए रेत खनन पर रोक लगाई हुई है। नर्मदा में सिर्फ मैन्युअल तरीके से ही रेत खोदी जा सकती है। लेकिन नर्मदा में आज भी मशीनें धड़ाधड़ रेत खोद रही हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पूर्ववर्ती शासनकाल में नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए थे। लेकिन दिसंबर 2018 में सत्ता परिवर्तन के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद एक बार फिर से नर्मदा में अवैध रेत खनन का सिलसिला शुरू हुआ। कांग्रेस के 15 माह के शासनकाल में माफिया ने नर्मदा में मशीनों से जमकर खुदाई की। यही नहीं मार्च 2020 में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा की सरकार बनी तब भी माफिया नर्मदा नदी से रेत निकालने में जुटा रहा। विगत माह विदिशा निवासी रूपेश नेमा ने एनजीटी में एक याचिका लगाकर नर्मदा नदी में अवैध खनन की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया।

माफिया नर्मदा नदी में किस तरह अवैध तरीके से रेत निकाल रहे हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सीहोर और रायसेन जिलों के रेत ठेकेदारों ने मानसून आने से पहले नर्मदा की 12 खदानों से महज डेढ़ महीने में 7 लाख 52 हजार 572 घनमीटर रेत खोद डाली। यानी 45 दिन के भीतर लगभग 42 हजार डंपर रेत। यानी रोजाना करीब-करीब एक हजार डंपर रेत। एक डंपर में वैध रूप से 14 घनमीटर और ओवरलोडिंग कर 18 घनमीटर रेत भरी जाती है। इतने कम समय में भारी मात्रा में मैन्युअली फावड़े-तगाड़ी से रेत खनन कैसे संभव है? एनजीटी ने रूपेश नेमा की याचिका पर संज्ञान लेते हुए सीहोर और रायसेन कलेक्टर को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ इसकी जांच कराने के आदेश दिए हैं। एनजीटी ने दोनों कलेक्टर से दो माह के भीतर जांच रिपोर्ट तलब की है।

● **रजनीकांत पारे**

शिवराज हुए आगबबूला

नर्मदा सहित प्रदेश की नदियों में रेत का अवैध खनन किस कदर हुआ है, इसका अंदाजा इस साल की पहली कमिश्नर-कलेक्टर कांफ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सख्त तेवर देखकर लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने अफसरों को जमकर फटकार लगाई और उन्हें हिदायत दी कि वैध कॉन्ट्रेक्टर को हमें प्रोटेक्ट करना है, अवैध को रोकना है। रेत के काले धंधे को हमें पूरी तरह से खत्म करना है। वाहन जब्त करने से कुछ नहीं होगा, उन्हें राजसात करना है। अवैध के नाम पर पैसे वसूलना पाप है, यह नहीं होने देंगे। रेत से किसी ने पैसा निकालने की कोशिश की तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। ऐसी शिकायतें नहीं आनी चाहिए, अगर शिकायतें आएंगी तो मैं कड़ी कार्रवाई करूंगा। नौकरी से बर्खास्त तक कर दूंगा। सभी यह ध्यान रखें। रेत से अगर किसी ने पैसा बनाने की सोची तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी के दवाब में आने की जरूरत नहीं है। मैंने तय किया है कि मैं भी कॉन्ट्रेक्टर से बात करूंगा, उनसे भी फीडबैक लूंगा।

जंगलों में पहुंचा बर्ड फ्लू

कोरोना महामारी के बीच देश में बर्ड फ्लू ने अब तेजी से पैर पसारना शुरू कर दिया है। देश के 10 राज्यों में एवियन इन्फ्लूएंजा फैलने की पुष्टि हुई है। वहीं, अब बर्ड फ्लू का संक्रमण जंगलों तक भी पहुंच गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने बताया है कि अब एवियन इन्फ्लूएंजा यानी बर्ड फ्लू हिमाचल प्रदेश, गुजरात, केरल के जंगलों और संरक्षित इलाकों में भी मिल चुका है। यहां कई प्रवासी बत्तख संक्रमित पाई गई हैं, जबकि बाकी राज्यों में बर्ड फ्लू ने पोल्ट्री को प्रभावित किया है। ऐसे में जंगलों में फैलने से जानवरों की विलुप्त हो रही प्रजातियों पर खतरा मंडराने लगा है।

मंत्रालय के एडिशनल डायरेक्टर जनरल सौमित्र दासगुप्ता ने बताया, 'एवियन इन्फ्लूएंजा का पहला मामला हिमाचल प्रदेश के पोंग डैम में मिला। इसके बाद ऐसी रिपोर्ट्स आई कि यह केरल और गुजरात के वनों तक पहुंच गया है जहां बर्ड फ्लू से बत्तखों (प्रवासी) की प्रजातियां प्रभावित हुई हैं।' मंत्रालय वनों में बर्ड फ्लू के प्रसार को रोकने के लिए मत्स्य विभाग जैसी अन्य एजेंसियों की मदद ले रहा है। दासगुप्ता ने कहा, 'हमें यह देखना होगा कि पक्षियों की कौन-सी अन्य प्रजातियां बर्ड फ्लू से संक्रमित हुई हैं।'

बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी के डायरेक्टर बिवश पांडव ने बताया, 'एवियन इन्फ्लूएंजा सामान्य स्थितियों में मानव शरीर को संक्रमित नहीं करता, लेकिन यह घरेलू पक्षियों में आसानी से फैल सकता है। इसकी वजह से हमारी पूरी पोल्ट्री बर्बाद हो सकती है यहां तक कि सुअर भी इससे संक्रमित हो सकते हैं।' उन्होंने कहा कि विलुप्त हो रहे जानवरों में वायरस जाने की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता है। मंत्रालय की एडवाइजरी के मुताबिक, बर्ड फ्लू से प्रभावित पक्षियों में दौरे, डायरिया, लकवा जैसी समस्याएं देखी जा रही हैं। एडवाइजरी में सभी चीफ वाइल्डलाइफ वॉर्डन्स से माइग्रेटरी पक्षियों की निगरानी करने के साथ ही आपात स्थिति से निपटने के लिए एक्शन प्लान बनाने को कहा गया है।

अब तक केरल, राजस्थान, मप्र, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उप्र, दिल्ली, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में इस वायरस संक्रमण की पुष्टि की गई है। दिल्ली सरकार ने संजय झील में बत्तखों के बर्ड फ्लू से संक्रमित पाए जाने के बाद शहर के बाहर से प्रसंस्कृत (प्रोसेस्ड) और पैक किया हुआ चिकन लाकर बेचने पर पाबंदी लगा दी। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अब तक केवल संजय झील की बत्तखों में ही बर्ड फ्लू संक्रमण पाया गया है। दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के चलते संक्रमण पक्षियों को मारने की कार्रवाई शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बर्ड फ्लू के डर के बीच अन्य राज्यों से आ रहे सभी पोल्ट्री (कुक्कुट से संबंधित) उत्पादों पर एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी है। एक बयान में यहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पोल्ट्री उत्पादों के जरिए अन्य राज्यों से संक्रमण का स्त्रोत न आ जाए। अब तक 4,357 प्रवासी जल पक्षियों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड के देहरादून और ऋषिकेश में कई कौओं समेत करीब 200 पक्षी मृत मिले हैं। देहरादून के अलग-अलग हिस्सों में 165 पक्षी मृत मिले हैं, जिनमें से अकेले भंडारी बाग क्षेत्र में 121 कौए मृत पाए गए हैं। वन प्रभागीय अधिकारी राजीव धीमान ने बताया कि देहरादून में मृत मिले पक्षियों में से 162 कौए, दो कबूतर और एक अन्य पक्षी है। उप्र के शाहजहांपुर और बलिया जिलों में विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की ताजा घटनाएं सामने आई हैं। राज्य में इस फ्लू की रोकथाम के लिए सतर्कता बढ़ा दी गई है। कानपुर चिड़ियाघर में मरे कुछ पक्षियों में बर्ड फ्लू पाए जाने के बाद लखनऊ प्राणी उद्यान प्रशासन ने अपने यहां पक्षियों के बाड़े को दर्शकों के लिए बंद कर दिया है। महाराष्ट्र के परभणी, मुंबई, बीड़ और दापोली में विभिन्न पक्षियों की मौत भोपाल की प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट के आधार पर एविएन इन्फ्लूएंजा से होने की पुष्टि हुई है। पिछले कुछ दिनों में करीब 900 मुर्गियों की मौत बर्ड फ्लू के कारण होने की पुष्टि हुई है और जिला प्रशासन ने गांव में करीब 8,000 पक्षियों को मारने का फैसला किया है।

मप्र की राजधानी भोपाल के आईसीएआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनीमल डिजीज के अनुसार मुंबई में दो कौवे बर्ड फ्लू से मर गए। उसकी रिपोर्ट के अनुसार ठाणे के तीन बगुले और एक तोता एच5एन1 एवियन इन्फ्लूएंजा से संक्रमित थे। गुजरात के सूरत और वडोदरा जिलों में भी मृत कौओं के नमूनों की जांच में उनके एवियन इन्फ्लूएंजा से संक्रमित पाए जाने के बाद दोनों जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। पशुधन विभाग, सूरत की उप निदेशक नीलम दवे ने कहा कि 6 जनवरी को सूरत के बरदोली तालुका में दो जगहों से चार कौओं के नमूने लेकर उन्हें भोपाल स्थित प्रयोगशाला भेजा गया था।

● **राकेश ग्रोवर**

प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों को सावधान रहने को कहा

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न हिस्सों में बर्ड फ्लू की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर सभी राज्यों से इसका प्रसार रोकने के लिए सावधान रहने को कहा है। साथ ही उन्होंने स्थानीय प्रशासन से जलाशयों के आसपास, चिड़ियाघरों और मुर्गी पालन केंद्रों पर निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, 'वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशु पालन विभाग के बीच जितना अधिक समन्वय होगा, उतनी ही तेजी से हम बर्ड फ्लू को नियंत्रित करने में सफल होंगे।' केंद्र सरकार ने फ्लू की रोकथाम के लिए तमाम कदम उठाने के बीच राज्यों से मुर्गा मंडियों को बंद नहीं करने या कुक्कुट उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित नहीं करने को भी कहा, क्योंकि मानव में बर्ड फ्लू संचरण की कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट सामने नहीं आई है।

कैसे बनेंगे संकटमोचक?

मप्र कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के इर्द-गिर्द ही सिमट गई है। प्रदेश में पार्टी का भविष्य भी नाथ के भविष्य पर निर्भर हो चला है नाथ सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं इसलिए प्रासंगिक रहना और जगह बना लेना खूब जानते हैं। प्रदेश में सत्ता जाने के बाद उपचुनाव में भी जब वापसी की गुंजाइश नहीं बनी तो वह केंद्रीय संगठन में लौटने की तैयारी में है। इधर, मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा और गांधी परिवार के करीबी अहमद पटेल के निधन से कांग्रेस संगठन में बड़ी रिक्तता आई है, जिसे भरने के लिए पार्टी का एक धड़ा भोपाल से दिल्ली तक कमलनाथ का नाम चला रहा है। उन्हें पार्टी में संकटमोचक तक कहा जाने लगा है। हालांकि यह स्वर भी उभर रहे हैं कि जो अपनी सत्ता न बचा सका, उपचुनाव में इसे वापस हासिल न कर सका, वह पार्टी का संकटमोचक कैसे साबित हो सकता है? वहीं कांग्रेस की कमान फिर से राहुल गांधी के हाथ में आने के स्पष्ट संकेत भी सवाल खड़े करते हैं कि टीम राहुल में कमलनाथ को अहम भूमिका मिलेगी या नहीं?

कमलनाथ 1980 से लगातार 9 बार छिंदवाड़ा सांसद रहे। 2019 में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने यहां अपने बेटे नकुलनाथ को मौका दिया और उन्हें संसद भेजा। नाथ खुद विधायक बन गए। मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद भी उनके पास रहा। मार्च 2020 में सरकार जाने के बाद कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आ गए हैं। पीसीसी अध्यक्ष का पद बना हुआ है। यानी कमलनाथ कांग्रेस के लिए मप्र में सदन से संगठन तक का चेहरा बन चुके हैं। ऐसे में अचानक केंद्र में जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस जिन राज्यों में विपक्ष की भूमिका में है, उनमें संख्या बल के आधार पर सबसे मजबूत स्थिति मप्र में है। ऐसे में जब कांग्रेस को मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, तब कमलनाथ की दिल्ली जाने की अटकलें नेतृत्व शैली पर सवाल खड़े करती हैं।

चर्चा है कि कांग्रेस की कमान फिर से राहुल गांधी के हाथ में आ सकती है। राहुल की टीम में कमलनाथ के भविष्य को आंकने से पहले दोनों नेताओं की परस्पर संबंध पर गौर करना जरूरी है। मप्र में उपचुनाव के दौरान इमरती देवी पर दिए बयान के लिए राहुल ने नाराजगी जताई थी, लेकिन उनकी मंशा के अनुरूप कमलनाथ ने माफी नहीं मांगी। उन्होंने बमुश्किल खेद जताकर मामला खत्म करना चाहा। बीते दिनों भी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि सोनिया गांधी की दिल्ली में हुई बैठक में राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस 2018 में सिर्फ छत्तीसगढ़ में जीती थी, राजस्थान और मप्र में वास्तव में भाजपा हार गई थी। मप्र में सरकार बनाने की कमलनाथ की सफलता को राहुल ने एक तरीके से दरकिनार कर दिया। कांग्रेस के करीबी इससे इनकार नहीं करते कि राहुल गांधी युवाओं की टीम लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं जिसमें शायद कमलनाथ फिट नहीं बैठते। पार्टी और चुनाव के लिए वित्तीय प्रबंधन बेहद अहम जिम्मेदारी है, जो गांधी परिवार अपने विश्वस्त को ही देना चाहेगा। इस दृष्टिकोण से कमलनाथ फिलहाल अहमद पटेल और मोतीलाल वोरा उत्तराधिकारी नहीं दिखाई पड़ते। इसके अलावा कांग्रेस की मुश्किल यह भी है कि पार्टी में कई उम्रदराज दिग्गज सक्रिय हैं और भी कई खेमों में बंटे हैं। संगठन में प्रतिस्पर्धा के चलते यह कई बार एक-दूसरे का रास्ता रोक देते हैं। इसके शिकार कमलनाथ भी हो जाएं, तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। सभी दलों को साधकर अपनी जगह बना लेना कमलनाथ के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होगा।

कमलनाथ को दिल्ली जाने से रोकने वालों के लिए 2018 के विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के आंकड़े ही पर्याप्त होंगे। 2018 में जब कमलनाथ मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किए गए थे और कांग्रेस एकजुट थी, तब भाजपा (41.6 प्रतिशत) और कांग्रेस (41.5 प्रतिशत) का वोट प्रतिशत लगभग बराबर था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद जब उपचुनाव हुए और **सत्ता वापसी** के लिए कमलनाथ का चेहरा बतौर मुख्यमंत्री आगे किया गया तब यह फासला 10 प्रतिशत से अधिक हो गया। भाजपा को 49.5 प्रतिशत और कांग्रेस को 40.5 प्रतिशत वोट शेयर मिले। 28 में से 19 सीटें भाजपा और 9 सीटें कांग्रेस ने जीती थीं। चुनाव-उपचुनाव के परिणामों का अंतर कमलनाथ की छवि को प्रभावित कर गया। उपचुनाव में कांग्रेस की हार का ठीकरा कमलनाथ पर ही फूटा, क्योंकि वही पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के पास प्रदेश कांग्रेस की कमान थी और सत्ता वापसी की स्थिति में फिर से मुख्यमंत्री भी उन्हें ही बनना था। उपचुनाव में कांग्रेस के कई शीर्ष नेताओं ने दूरी बना ली थी। ऐसे में कमलनाथ को कांग्रेस का संकटमोचक बताकर दिल्ली दरबार पहुंचने की चर्चाएं कई सवाल खड़े कर रही हैं।

● **लोकेंद्र शर्मा**

मप्र में बैठकर दिल्ली संभालेंगे कमलनाथ!

मप्र के कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रदेश नहीं छोड़ने जा रहे हैं। उनका राजनीति से संन्यास लेने का दांव काम आ गया है। अब वे संन्यास भी नहीं लेंगे और मप्र भी नहीं छोड़ेंगे। वे प्रदेश में रहकर ही दिल्ली यानी केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी काम करेंगे, जैसे अभी असंतुष्ट नेताओं की सोनिया गांधी से बैठक कराने में की। कमलनाथ ने ही असंतुष्ट नेताओं से बात की थी और फिर सोनिया गांधी को उनके साथ बात करने के लिए तैयार किया था। उस बातचीत में सबके गिले-शिकवे काफी हद तक दूर किए गए। उसके बाद ही कांग्रेस के हर कार्यक्रम में गुलाम नबी आजाद सक्रियता के साथ दिखने लगे हैं। बताया जा रहा है कि इस पहल के लिए प्रियंका गांधी ने कमलनाथ से बात की थी। वे केंद्रीय राजनीति में प्रियंका गांधी के साथ काम कर रहे हैं। ध्यान रहे अपने शुरुआती दिनों में भी वे इंदिरा गांधी की बजाय संजय गांधी के साथ काम करते थे। असल में कांग्रेस आलाकमान को उनकी उपयोगिता का पता है। लेकिन यह भी पता चल गया है कि कमलनाथ प्रदेश नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने खुद भी कह दिया है कि वे मप्र से हिलेंगे नहीं और न राजनीति से संन्यास लेंगे। इसका मतलब है कि वे भोपाल में बैठकर केंद्रीय नेतृत्व के लिए संकटमोचक का काम करेंगे।

मप्र में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरु कर दी है। विधानसभा के उपचुनाव के जरिए अपने दम पर सत्ता में आई भाजपा निकाय चुनावों में पूरे दमखम से मोर्चा संभालेगी। हालांकि भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती सभी नगर निगम में जीत हासिल करने की होगी। पिछले चुनाव में भाजपा ने 16 निगमों में से सभी पर जीत हासिल की थी। वहीं, प्रदेश में सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस निकाय चुनावों में जीत दर्ज कर साख बचाने की जुगत में है। निकाय चुनाव के सहारे दोनों पार्टियों की कोशिश यह है कि वे अगले दो दशक के लिए अपने नेता तैयार करें।

अगले दो दशक की तैयारी

मप्र में चौथी बार सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के ऊपर अगले दो दशक के लिए नेता तैयार करने की जिम्मेदारी आन पड़ी है। ऐसे में आगामी दिनों में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव युवा नेतृत्व को आगे लाने का बड़ा प्लेटफार्म बन सकता है। ऐसे में भाजपा ने निकाय चुनाव में अधिक से अधिक युवा नेताओं को टिकट देने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। भाजपा की तरह ही कांग्रेस भी इस कोशिश में लगी हुई है कि अधिक से अधिक युवाओं को चुनावी मैदान में उतारा जाए। अभी हाल ही में धार जिले के मोहनखेड़ा में युवक कांग्रेस के कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने घोषणा की कि निकाय चुनाव में अधिक से अधिक युवाओं को टिकट दिलवाया जाएगा। यानी भाजपा और कांग्रेस ने अगले दो दशक के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है।

मप्र भाजपा की कमान 4जी (फॉर्थ जनरेशन यानी चौथी पीढ़ी) के वीडी शर्मा के हाथ में है और उन्होंने अपनी टीम में युवाओं को जगह देकर यह संकेत दे दिया है कि भाजपा में अब युवाओं को अधिक महत्व दिया जाएगा। ऐसे में नगरीय निकाय चुनावों को भाजपा पीढ़ी परिवर्तन का अवसर बनाने की तैयारी में है। यानी रणनीति सफल रही तो इसमें टिकट 30 से 45 साल तक के दावेदारों को दिया जाएगा, जिससे पार्टी के प्रति युवाओं का रूझान और उनके लिए अवसर बढ़ाए जा सकें। पार्टी पार्षद से लेकर नगर परिषद और नगर पालिका अध्यक्ष और महापौर पद के लिए नए चेहरों को मौका देगी।

दरअसल, भाजपा में मौजूदा दौर में सक्रिय नेताओं में अधिकतर 90 के दशक या उससे भी पहले के हैं। युवाओं को भरपूर अवसर न मिलने से पीढ़ी परिवर्तन का लाभ पार्टी को कम ही मिला। ऐसे में जब वीडी शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो संगठन में एक नई ताजगी महसूस की गई। युवाओं के साथ अन्य क्षेत्रों से भी लोगों ने पार्टी में रूचि दिखाई। शर्मा की टीम में भी पांचों महामंत्री भी नई पीढ़ी के हैं। संभावना है कि घोषित होने वाली कार्यकारिणी में भी ज्यादातर चेहरे नए होंगे।

पार्टी अगले दो दशक का नेतृत्व तैयार करने के रोडमैप पर चल रही है। यही वजह है कि मंडल अध्यक्षों के चुनाव में आयु सीमा 35 से 40 वर्ष तय की गई थी। पार्टी स्थानीय निकाय में चुनाव लड़ने वाले 55-60 साल से ज्यादा उम्र के किसी भी नेता को टिकट नहीं देना चाहती है। भाजपा ने लोकसभा व विधानसभा चुनावों में 75 साल या ज्यादा उम्र के नेताओं को मौका नहीं दिया था।

2018 के विधानसभा चुनाव में 18 से 29 साल के मतदाताओं की संख्या 1,53,60,832 थी, जिसमें 18-19 साल के मतदाताओं की संख्या 16 लाख से ज्यादा, वहीं 20 से 29 वर्ष की आयु 1,37,82,779 मतदाता रहे। पहली बार वोट डालने का हक पाने वाले लगभग 12 लाख

भाजपा ने किया था क्लीनस्वीप

बीते नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा ने प्रदेश के सभी 16 नगर निगमों के महापौर पद पर जीत दर्ज कर क्लीनस्वीप किया था। भाजपा पर बीते चुनाव के परिणामों की बड़ी चुनौती बनी हुई है, जबकि कांग्रेस के पास इसमें खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अधिकांश नगर निगमों में जिताऊ उम्मीदवारों की खोज बनी हुई है। यही नहीं उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ग्वालियर-चंबल अंचल में बनी हुई हैं। इस अंचल में श्रीमंत और उनके समर्थकों द्वारा भाजपा में जाने की वजह से संगठन पूरी तरह से बिखर चुका है। यही नहीं पार्टी के बड़े और प्रभावशाली नेता भी भाजपा का दामन थाम चुके हैं। भाजपा संगठन को उम्मीद है कि वह नगरीय निकाय चुनाव में पिछले चुनाव की अपेक्षा अधिक अच्छा प्रदर्शन करेगी। क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस संगठन पूरी तरह बिखर चुका है। वहीं भाजपा उपचुनाव के बाद से ही नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। अतः इस बार भी भाजपा क्लीनस्वीप कर सकती है।

मतदाता थे। निर्वाचन आयोग के अनुसार 2018 में मप्र में करीब पांच करोड़ मतदाता थे। यानी राज्य में कुल मतदाताओं के मुकाबले 18 से 29 वर्ष की आयु के मतदाताओं का अनुपात लगभग 35 प्रतिशत है। अब दो साल में कम से कम 12 लाख युवा मतदाता बढ़ने की संभावना है।

उपचुनाव के परिणामों ने एक तरह से कांग्रेस के बुजुर्ग नेताओं का सियासी भविष्य हाशिए पर डाल दिया है। युवाओं को मौका देने का पार्टी पर दबाव है। ऐसे में यदि युवा नेताओं को मौका मिलता है, तो प्रदेश के युवाओं का रूझान कांग्रेस की तरफ बढ़ सकता है। विपक्ष में होने से युवाओं की अपेक्षा यदि कांग्रेस सियासी संघर्ष में बदलने में कामयाब रही, तो भाजपा की मुश्किलें बढ़ेंगी, ऐसे में भाजपा निकाय चुनावों में ही युवाओं को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश कर रही है।

निकाय चुनावों के लिए प्रत्याशी चयन के लिए भाजपा ने चयन समिति बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने भी अपना वार रूम शुरू कर दिया है। भाजपा प्रदेश सरकार की जनहितैषी नीतियों को लेकर मैदान में उतरेगी तो कांग्रेस अपने 15 महीने के कार्यकाल को लेकर वोट मांगेगी। मालूम हो, प्रदेश में 407 नगरीय निकाय हैं। इनमें 16 नगर निगम, 99 नगर पालिका और 292 नगर परिषद हैं। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि पार्टी विधायकों और सांसदों को महापौर के लिए टिकट नहीं देगी। पार्टी चाहती है कि नए नेतृत्व को अवसर मिले और इसलिए यह फैसला लिया गया है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि भाजपा चुनावों के लिए तैयार है। सरकार की ओर से भी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। पार्टी भारी मतों से जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि नए आइडिया पर काम करें। समीक्षा बैठकों में मंत्रियों को प्रजेंटेशन देना होगा।

वहीं मप्र में इसी साल जल्द होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ दल भाजपा की शिव व वीडी की जोड़ी को कांग्रेस की ओर से कमलनाथ चुनौती देने की तैयारी कर चुके हैं। इन चुनावों को शिव सरकार के कामकाज की शहरी जनता की समीक्षा के अलावा दो साल बाद होने वाले विधानसभा के आम चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। दरअसल प्रदेश में वर्ष 2023 में आम विधानसभा चुनाव होने हैं। यही वजह है कि इन चुनावों के मद्देनजर अब लगातार मुद्दों पर दोनों दल एक-दूसरे की घेराबंदी में लगे हुए हैं।

इसी के साथ ही दोनों दलों में दौरे भी तय किए जा रहे हैं। भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा अभी से नगरीय निकाय चुनावों के लिए पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं तो वहीं कांग्रेस की ओर से सिर्फ कमलनाथ अकेले ही मोर्चा संभालने की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा की ओर से निकाय चुनाव की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री शिवराज ने मोर्चा संभाल लिया है। इसी सिलसिले में उन्होंने 13 जनवरी को महाकाल की नगरी उज्जैन से शहरी इलाकों के दौरों की शुरूआत कर दी है। वे इसी माह में नगर निगमों वाले सभी शहरों में जाने का कार्यक्रम तय कर चुके हैं। इसके अलावा वीडी शर्मा भी समय-समय पर संगठन की तैयारी की दृष्टि से इसी तरह के दौरे करने वाले हैं। इसके प्रतिउत्तर में कांग्रेस की ओर से भी कमलनाथ के दौरों को लेकर योजना तैयार की जा रही है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि निकाय चुनावों को लेकर कमलनाथ अगले माह दौरे करने वाले हैं। इसके लिए पीसीसी स्तर पर कार्यक्रम तैयार करने का काम किया जा रहा है। इससे यह तय है कि वीडी और शिव की जोड़ी को नाथ चुनौती देने के लिए तैयार हैं। हालांकि नए साल के पहले दौरे की शुरूआत नाथ ने धार से की है। यह दौरा उनका पार्टी की युवा इकाई के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण को लेकर था। इसके बाद उन्होंने 15 जनवरी को अपने गृह जिले छिंदवाड़ा में कृषि बिल के खिलाफ अभियान शुरू कर निकाय चुनाव का शंखनाद भी कर दिया है। माना जा रहा है कि नाथ उपचुनाव में मिले सबक से इस बार निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही शहरी इलाकों में दौरे करने जा रहे हैं।

कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने स्टार प्रचारक कमलनाथ के दौरा कार्यक्रम तय कर दिए हैं। जनवरी में नगरीय निकाय में पहुंचकर कमलनाथ पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने का काम करेंगे और फरवरी महीने में ताबड़तोड़ दौरे कार्यक्रम होंगे। नगरीय निकाय चुनाव तीन माह टलने के बाद भी भाजपा और कांग्रेस ने अपनी तैयारियों में कोई ढील नहीं दी है। कांग्रेस ने समय का सदुपयोग करते हुए उन दावेदारों से आवेदन मंगवा लिए हैं, जो महापौर अथवा पार्षद का चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। उधर, भाजपा ने भी महापौर, अध्यक्ष और पार्षद के दावेदारों के नामों पर मंथन शुरू कर दिया है।

● **सुनील सिंह**

कमियां तलाश रही कांग्रेस

विधानसभा उपचुनावों में हुई हार ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। प्रदेश में वापसी की बाट जोह रही कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि वो इन चुनावों में जरूर जीत हासिल करेगी लेकिन करारी हार ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस झटके से सबक लेकर कांग्रेस अब अपनी कमियां तलाश रही है। कांग्रेस विधानसभा की उपचुनाव वाली 28 सीटों पर पोस्ट पोल सर्वे करा रही है। एक से दो महीने में पोस्ट पोल सर्वे की पूरी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। इस सर्वे के आधार पर कांग्रेस अपनी आगामी रणनीति पर काम करेगी। उपचुनावों के चौंकाने वाले परिणामों ने पार्टी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि किन कारणों से 15 महीने पहले जीती सीटें वो इतने बड़े अंतर से हारी। यही कारण तलाशने के लिए कांग्रेस ने अपनी टीमों को उपचुनाव वाली सभी 28 सीटों पर सर्वे के लिए टीमें उतार दी हैं। ये टीमें बूथ स्तर तक जाकर सर्वे कर रही हैं। लोगों से ये पूछा जा रहा है कि कांग्रेस की कौन सी कमियों की वजह से उन्होंने भाजपा को वोट दिया। क्या 15 महीने में उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई थी। उनकी सरकार से क्या उम्मीदें थीं जिन पर पानी फिर गया। आखिर लाखों वोट से कांग्रेस से हारने की वजह क्या हैं। जल्द ही ये रिपोर्ट तैयार हो जाएगी जिनमें कांग्रेस के हार के कारण लिखे होंगे।

पटरी पर इंदौर मेट्रो

मप्र में नगरीय निकाय चुनाव की हलचल के बीच मेट्रो का जिन्न फिर निकल आया है। 10 महीने से मेट्रो प्रोजेक्ट बंद पड़ा था, जिस पर अब फिर से काम शुरू हो गया है। मेट्रो ट्रेन को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने हैं। दोनों ही दल नगरीय निकाय चुनाव में इस मुद्दे को भुनाने की तैयारी में लगे हैं। मप्र की भाजपा सरकार ने 2013 के विधानसभा चुनाव में ये दावा किया था कि 2018 तक भोपाल और इंदौर के एक हिस्से में मेट्रो पटरी पर दौड़ने लगेगी। घोषणा के 7 साल बाद मेट्रो तो पटरी पर नहीं आ पाई लेकिन हर चुनाव में मेट्रो का मुद्दा जरूर दौड़ता दिखाई दिया। अब जबकि नगरीय निकाय चुनाव सिर पर हैं उससे पहले एक बार फिर मेट्रो का जिन्न निकल आया है। करीब 10 महीने से बंद पड़े काम को आनन-फानन में शुरू करा दिया गया है।

मप्र में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव से पहले 2 बड़े शहरों भोपाल और इंदौर के सबसे बड़े प्रोजेक्ट मेट्रो रेल को गति देने की बात सत्ताधारी दल भाजपा फिर कहने लगी है। हालांकि मेट्रो का श्रेय लेने की होड़ कांग्रेस ने भी की थी और 14 सितंबर 2019 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 7500.8 करोड़ की लागत से बनने वाली इंदौर मेट्रो का दोबारा **भूमिपूजन** कर दिया था। लेकिन कमलनाथ सरकार की विदाई के साथ ही इंदौर मेट्रो का काम भी बंद हो गया। अब जैसे ही नगरीय निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज हुई तो एक बार फिर मेट्रो का काम शुरू करा दिया गया है जिससे लोगों को लगे कि मेट्रो चलने वाली है और तो और इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह को मेट्रो प्रोजेक्ट का चेयरमैन बना दिया गया है। उनका कहना है इंदौर मेट्रो का काम धीरे-धीरे पिकअप कर रहा है। भू-अर्जन और हाइटेंशन लाइन हटाने के मुद्दे सॉर्ट आउट किए जा रहे हैं। इसके बाद इंदौर मेट्रो का काम गति पकड़ लेगा।

इंदौर मेट्रो के कर्ताधर्ता बैठकों में काम तेज करने की वकालत तो कर रहे हैं, लेकिन बाधाएं हटाने के लिए जमीनी स्तर पर कोई सार्थक पहल नजर नहीं आ रही है। पहले चरण में एमआर-10 रेल ओवरब्रिज से पूर्वी रिंग रोड के मुमताज बाग तक जिस पहले हिस्से में काम होना है, वहीं की बाधाएं हटाने की कोई गतिविधि फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं। इस हिस्से में सुखलिया, सयाजी तिराहा, विजय नगर और खजराना चौराहे की रोटरी हटना है। ये काम नगर निगम को करना है। इंदौर से मेयर की दौड़ में शामिल सिंधिया के खास नेता मोहन सेंगर इसी क्षेत्र से पिछला चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे लेकिन वो रमेश मेंदोला से हार गए थे। अब वे भाजपा में हैं और मेट्रो का मुद्दा भुनाने की तैयारी में लग गए हैं। उनका कहना है भाजपा ही मेट्रो का संकल्प पूरा करेगी और तय समय सीमा मे ही मेट्रो का काम पूरा होगा।

इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी बाधा बापट चौराहा से विजय नगर के बीच एमआर-10 के बीचों बीच बिजली की हाईटेंशन लाइन है। इसका हटना भी अभी दूर की कौड़ी लग रहा है, क्योंकि उससे पहले बिजली ट्रांसमिशन कंपनी को वैकल्पिक लाइन का काम करना होगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला का कहना है कि भाजपा की नीयत ही नहीं है कि इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाए। यही वजह रही कि पिछले 7 साल में ये प्रोजेक्ट 9 दिन चले अढ़ाई कोस की कहावत पर चल रहा है। भाजपा चाहती तो कब की मेट्रो ट्रेन पटरियों पर दौड़ने लगती। लेकिन चुनाव से पहले एक बार फिर जनता को बरगलाने के लिए मेट्रो का सपना दिखाना शुरू कर दिया गया है। चुनाव समाप्त होते ही ये प्रोजेक्ट फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा।

बता दें कि इंदौर के मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट में निर्माता कंपनी और जनरल कंसल्टेंट के बीच कुछ विवाद चल रहा था। यह पूरी तरह से सुलझ गया है। विवाद के कारण मेट्रो प्रोजेक्ट का काम 10 महीने से ठप पड़ा था। ड्रॉइंग-डिजाइन को लेकर पूरा विवाद था। दोनों में ही इसे लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी। अब मेट्रो प्रोजेक्ट की निर्माता कंपनी दिलीप बिल्डकॉन और जनरल कंसल्टेंट के बीच सहमति बन गई है। कंसल्टेंट कंपनी सभी पेंडिंग 127 ड्रॉइंग को मंजूरी देने जा रही है। कंपनी बापट चौराहे से काम शुरू कर रेडिसन चौराहा होते हुए खजराना की ओर बढ़ेगी।

नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह कहते हैं कि इंदौर के मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर कुछ तकनीकी और वित्तीय कठिनाइयां थीं, लेकिन अब उन्हें दूर कर लिया गया है। मंत्री ने माना कि कोरोना के कारण उपजी वित्तीय कठिनाइयों के कारण इंदौर को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत दिए जाने वाले 300 करोड़ रुपए की राशि सरकार नहीं दे पाई है। नगर निगमों को पूरक बजट का पैसा अध्यादेश के माध्यम से जल्द मिलना शुरू होगा।

● **विकास दुबे**

भगवान भरोसे काम

मेट्रो प्रोजेक्ट की इंदौर में धीमी पड़ी गति को एक बार फिर से रफ्तार मिलने जा रही है। 10 महीने के विवाद के बाद मेट्रो प्रोजेक्ट फिर शुरू हो गया है। निर्माता कंपनियों के बीच बनी सहमति के बाद काम शुरू किया जा रहा है। निगम आयुक्त के अनुसार आने वाले साल में काम युद्ध स्तर पर शुरू हो जाएगा। यदि दूसरे शहरों में मेट्रो की बात की जाए तो नागपुर मेट्रो रेल का भूमि पूजन 31 मई 2015 को हुआ था और 21 अप्रैल 2018 से 6 किलोमीटर की राइड शुरू कर दी गई। पहली कमर्शियल लाइन 9 मार्च 2019 को शुरू हुई और 20 किलोमीटर के एरिया में मेट्रो ट्रेन चलने लगी। आगामी फरवरी तक नागपुर मेट्रो का काम पूरा हो जाएगा, लेकिन इंदौर मेट्रो कब तक कागजों से पटरी पर दौड़ेगी ये कह पाना मुश्किल है। चुनाव में जरूर ये मुद्दा अहम बन जाता है।

विस्थापन का दर्द

पिछले तीन दशक में सरदार सरोवर बांध से हुए नफा और नुकसान की मोटे तौर पर दो तस्वीरें हमारे दिलो-दिमाग पर उभरती हैं। पहली तस्वीर बिजली, पानी और विकास की गंगा के रूप में प्रस्तुत की जाती है। दूसरी तस्वीर हजारों लागों के विस्थापन का दर्द लिए हमारे सामने उजागर होती है। नर्मदा पर बन रहे बांधों के जन विरोध के कारण समय-समय पर विकास बनाम विनाश चर्चा के केंद्र में रहता है। लेकिन, यह बात कम ही लोग जानते हैं कि सरदार सरोवर बांध के खिलाफ चल रहे आंदोलन की दो रेखाएं समानांतर चलती रही हैं। एक अहिंसा पर आधारित लड़ाई को जारी रखती है तो दूसरी रचनात्मकता का रास्ता दिखाती है।

ऐसी ही एक रचनात्मक कोशिश है 'जीवनशाला', जिसने हजारों लोगों के जीवन में रोशनी फैलाने का काम किया है। बता दें उजाला बांटने का यह प्रयास कई वर्षों से जारी है। प्रश्न है कि यह जीवनशाला क्या है? बांध से प्रभावित आदिवासियों के मुताबिक लड़ाई-पढ़ाई साथ-साथ होना जरूरी है। यही सोचकर आदिवासियों ने अपने अंचल में अपने बच्चों के लिए जीवनशाला नाम से कई स्कूल तैयार किए, जिनमें एक पढ़े-लिखे भविष्य का निर्माण अनवरत जारी है।

विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमालाओं की ओट में यहां कई छोटे और सुंदर गांव हैं। यह गांव अपने जिला मुख्यालय से बहुत दूर और घनघोर जंगलों के बीच मौजूद हैं। इन जगहों पर स्कूल भवन बनने और शिक्षक आने की राह तकना कभी नियति का खेल समझा जाता था। ऐसा नहीं है कि बांध विस्थापितों ने बच्चों की शिक्षा के लिए कभी सरकार से गुहार नहीं लगाई हो। अधिकारियों को कई बार आवेदन दिए, फाइलें बनीं, लेकिन ये फाइलें कभी सरकी ही नहीं। हर बार सरकारी अधिकारी आश्वासन देते रहे और स्थिति जस की तस बनी रही। आखिरकार, आदिवासियों ने खुद बदलाव की यह पहल की। तीन दशक पहले-पहले चिमलखेड़ी और नीमगांव में जीवनशालाएं शुरू हुईं। यहां के आदिवासी बताते हैं कि एक तो काम नया-नया था और दूसरा ज्यादा कुछ मालूम भी नहीं होने से चुनौतियां पहाड़ की तरह खड़ी थीं। फिर भी जीवनशाला का आधार स्वावलंबी रखा गया।

शुरुआत से ही सीमित साधन, संसाधन और सामुदायिक क्षमता के अनुरूप बेहतर शिक्षा की बात पर बल दिया गया। इन जीवनशालाओं का मकसद महज सरकारी स्कूलों की शून्यता भरना भर नहीं था बल्कि आदिवासी जीवनशैली को कायम रखना भी था। आज की तारीख में इन इलाकों में तेरह से ज्यादा जीवनशालाएं संचालित हो रही हैं, जो आसपास के 1500 से ज्यादा बच्चों को जिंदगी की बारहखड़ी सिखा रही हैं। भले ही जीवनशाला का जन्म विस्थापन रोकने की लड़ाई का नतीजा रहा हो, मगर जल्द ही ऐसे स्थान आंदोलनकारियों के लिए विविध चर्चा, रणनीति और कार्यक्रम आयोजन का मुख्य केंद्र बन गए। इस प्रकार, आंदोलन और जीवनशाला, दोनों एक-दूसरे के लिए मददगार साबित हुए। यही वजह है कि आज ऐसे स्थान आदिवासी एकता और भागीदारी के प्रतीक बन गए हैं।

विस्थापन से विकराल आशंकाओं का बोझ

जीवनशाला से निकली पहली पीढ़ी अब तैयार हो चुकी है। जो अब शिक्षक बनकर अपने संस्कारों को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि, विस्थापन की प्रक्रिया ने उन्हें एक ऐसे बाजार में खड़ा कर दिया है, जहां जीवन की राह निकाल पाना मुश्किल है। लेकिन, जीवनशाला ने उन्हें इससे पार होने की सीख दी है। विस्थापन यानी दोबारा या बार-बार बसना, सरकारी योजना का लाभ न उठा पाना, कानूनी हक से बेदखल, मेजबान समुदाय की आनाकानी, नया समायोजन, शोषण, यौन उत्पीड़न, अधिक व्यय, हिंसा, अपराध, अव्यवस्था, संसाधन या सीमित जमीन, निर्णय की गतिविधि से कटाव, अस्थायी मजदूरी, मवेशियों का त्याग, प्रदूषण, सुविधा व स्वास्थ्य संकट। ऐसे में फिर यही कहना है कि एक तरफ बांध के कारण विस्थापन से विकराल आशंकाओं का इतना भारी बोझ है। वहीं, दूसरी ओर जीवनशाला के नन्हें बच्चों के हाथों में खुली किताबों-सा खुला आसमान है, जहां उन्हें आगे बहुत-सी परीक्षाएं पास करनी हैं।

जीवनशाला में पढ़ाई-लिखाई का तरीका सहज है। लोगों के बीच से कुछ लोग निकले और शिक्षक बन पढ़ा रहे हैं। इसमें गांव की बोली को वरीयता दी गई। इस दौरान किताबों का प्रकाशन भी पवरी या भिलाली जनजातीय बोलियों में किया गया। पहली बार बच्चों को उनकी बोली की किताबें मिल सकी हैं। शिक्षकों ने अमर केन्या (हमारी कथाएं) में कुल बारह आदिवासी कहानियों को समेटा है। इसके अलावा सामाजिक विषयों पर अम्रो जंगल (हमारा जंगल) और आदिवासी वियाब (आदिवासी विवाह) जैसी किताबों को लिखा गया है। केवल सिंह गुरूजी ने अम्रो जंगल में यहां की कई जड़ी-बूटियों का महत्व बताया है। खुमान सिंह गुरूजी ने रोज्या नाईक, चीमा नाईक किताब में अंग्रेजी हुकूमत के वक्त संवरिया गांव के संग्राम पर रोशनी डाली है। ऐसी किताबों में आदिवासी समाज का इतिहास, साहित्य, कला, संस्कृति और परंपराओं से लेकर स्थानीय भूगोल, प्रशासन और कानूनी हक तक की बातें होती हैं। जब आप किसी जीवनशाला में जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक तरफ यहां विस्थापन से विकराल आशंकाओं का इतना भारी बोझ है और दूसरी ओर जीवनशाला के नन्हें बच्चों के हाथों में खुली किताबों-सा खुला आसमान है।

हर किताब जैसे कुदरत के साथ दोस्ताना रिश्ता बनाने का संदेश देती है। पढ़ाई को दिलचस्प बनाने के लिए अनेक तरीकों को अजमाया गया है। जैसे कि अक्षर ओलखान (अक्षरमाला) में यहां की बोली के मुताबिक अक्षरों की पहचान और जोड़ना सिखाया गया है। इसमें कई आवाजों को निकालकर या आसपास की चीजों से मेल-जोल कराना होता है। नाच-गाना, चित्र और खेलों से पढ़ाई मनोरंजक बन जाती है। इनमें लिखने की कई विधियों को भी बार-बार दोहराया जाता है।

● **प्रवीण कुमार**

नशा तस्करी पर बड़ी चोट

मप्र में जबसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ हल्ला बोला है, प्रदेशभर में नशा तस्करों की शामत आ गई है। खासकर प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में तो कई तस्करों को पुलिस ने धर दबोचा है। अभी हाल ही में क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स मामले में देश की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई का खुलासा किया। गिरफ्त में आए 5 आरोपियों से 70 करोड़ रुपए की 70 किलो एमडीएमए ड्रग्स बरामद की। इनके पास से 13 लाख रुपए नकद भी बरामद हुए हैं। आरोपी तेलंगाना और मप्र के रहने वाले हैं। आरोपी ड्रग्स की खेप देने और टोकन मनी लेने के लिए एकत्रित हुए थे। आरोपियों की माने तो वे ट्रेन, प्लेन, बस, ट्रक ट्रांसपोर्ट और निजी कार हर प्रकार से ड्रग्स लाते थे। ये इतने शातिर थे कि ट्रांसपोर्ट से ड्रग्स भेजते समय वे पैकेट में मुर्गी दाना पाउडर या बीमारियों के वैक्सीन का पाउडर बताते थे।

एडीजी योगेश देशमुख के अनुसार इंदौर पुलिस ने अब तक अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एमडीएमए, ब्राउन शुगर, गांजा व अन्य मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के कई सदस्यों को पकड़ा है। पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली थीं। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि हैदराबाद के कुछ तस्कर इंदौर और देवास के रहने वाले स्थानीय एजेंट्स और ड्रग्स पैडलरों के जरिए बड़ी मात्रा में मप्र में एमडीएमए की तस्करी करने वाले हैं। पुलिस के अनुसार एमडीएमए ड्रग्स को लेकर यह देश की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इंदौर में पकड़ा गया ड्रग्स गिरोह पिछले दो साल में 100 करोड़ से अधिक की ड्रग्स को इंदौर में खपा चुका है।

एडीजी योगेश देशमुख के अनुसार मुखबिर ने बताया था कि नायता मुण्डला सनावदिया के पास की सड़क किनारे पहाड़ी के पास नशे के कुछ सौदागर एकत्रित हुए हैं, जिस पर एक टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया। पकड़ में आए आरोपियों ने अपना नाम दिनेश अग्रवाल पिता नारायण लाल अग्रवाल, निवासी- निशदिन औरा ब्लॉक बी 406 बी बालाजी हाइट महालक्ष्मी नगर इंदौर, अक्षय अग्रवाल उर्फ चीकू पिता दिनेश अग्रवाल, निवासी- 19 होराइजन सिटी थाना लसूडिया इंदौर, चिमन अग्रवाल पिता मदन लाल, निवासी-38 ए प्रेम कॉलोनी स्टेशन रोड मंदसौर, वेदप्रकाश व्यास पिता स्व. बिहारी लाल निवासी- 2/4, 299 जलवायु विहार तिरूमलगिरी हैदराबाद और मांगी वेंकटेश पिता मांगी मारा निवासी प्रकाशम पंतुलू उषामुल्लापुड़ी जेटीमेडला हैदराबाद बताया।

एडीजी योगेश देशमुख ने बताया कि काफी समय से दिनेश अग्रवाल को लेकर सूचना मिल रही थी कि वह एमडीएमए ड्रग्स का कारोबार कर रहा है। इस पर 20 दिन से क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम निगरानी कर रही थी। इस दौरान उसके गरोठ (मंदसौर) में एक कनेक्शन की बात पता चली। एक-एक कड़ियां जोड़ीं तो खुलासा हुआ कि ये हैदराबाद की फार्मा कंपनी में एमडीएमए (सिंथेटिक ड्रग्स) तैयार करवाकर सड़क और रेलवे कार्गो के माध्यम से इंदौर, आगर-मालवा, निमाड़ अंचल और राजस्थान में सप्लाई कर रहे हैं। हैदराबाद में इसे वेदप्रकाश व्यास से तैयार करवाया। पुलिस ने दिनेश, अक्षय और चिमन को निगरानी में ले लिया। इनसे पूछताछ की तो पता चला कि ड्रग्स हैदाराबाद से वेदप्रकाश सप्लाई करता है।

आरोपी वेदप्रकाश व्यास पिता बिहारी लाल व्यास देवास का रहने वाला है। वह पहले एक दवा कंपनी में एमआर था। इसके बाद वह देवास से हैदराबाद शिफ्ट हो गया था और वहां पर दवा कंपनी की फार्मा यूनिट और लेबोरेटरी खोल ली। दवाई का काम करते समय ही वह हैदराबाद के ड्रग्स तस्करों के संपर्क में आया। इसके बाद योजना बनी और ये इंदौर, देवास, उज्जैन सहित अन्य आसपास के जिलों में ड्रग्स की सप्लाई करने लगे। धीरे-धीरे इन्होंने हर जिले में एजेंट बना लिए। इसी ग्रुप में एंट्री की मंदसौर के रहने वाले चिमन अग्रवाल ने। चिमन ने इंदौर, उज्जैन, देवास में तस्करी के लिए अपने चाचा दिनेश और चचेरे भाई अक्षय को मिला लिया। ये दोनों इंदौर में रहते हैं। इनका उज्जैन और इंदौर में टेंट हाउस का काम है। इसी काम के कारण ये अन्य जिलों में भी आना-जाना करते थे। इन्होंने ऐसी पैठ बनाई कि मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, खंडवा, भोपाल, इंदौर, देवास आदि जिलों में भी ये ड्रग्स सप्लाई करने लगे। पूछताछ में इन्होंने पहले भी बड़ी मात्रा में ड्रग सप्लाई करना और खुले में बेचना कबूला है। आरोपी अक्षय, दिनेश अग्रवाल का बेटा है, जबकि आरोपी चिमन आरोपी दिनेश का भतीजा है।

● **नवीन रघुवंशी**

वेदप्रकाश युवाओं को बना रहा था नशे का आदी

वेदप्रकाश ने मंदसौर में एमआर रहते हुए एमडी ड्रग्स की तस्करी शुरू कर दी थी। इसमें काफी रुपए मिलने पर चिमन और दिनेश अग्रवाल भी इससे जुड़ गए थे। बाद में उसने एक नामी फार्मा कंपनी में भी नौकरी की। फिर वह हैदराबाद शिफ्ट हुआ और यहां खुद की फार्मा कंपनी एरिस्टॉन फार्मा नोवाटेक प्राइवेट लिमिटेड खोल ली। इसी की आड़ में वह एमडी ड्रग्स तैयार करने लगा। इतनी बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग्स सप्लाई करने वाले हैदराबाद का फार्मा कारोबारी आरोपी वेदप्रकाश व्यास इंदौर के युवाओं को ड्रग्स का आदी बनाकर उन्हें बर्बाद कर रहा था। वहीं वह अपने बेटे की पढ़ाई अमेरिका के शिकागो में करा रहा है। बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पुलिस उसके परिवार के अन्य सदस्यों की जानकारी भी जुटा रही है। आईजी मिश्र ने बताया कि पकड़ाई एमडीएमए ड्रग्स 80 प्रतिशत डेंसिटी की क्वालिटी वाली है। इसे एक लैब में टेस्ट करवाया है। ड्रग्स पैडलर्स व तस्कर इसे कई ग्रामों में खरीदकर उसे दोगुना एमडी मिलावट कर बना लेते हैं और उससे भी मुनाफा कमाते हैं। अब तक देश में मुंबई पुलिस ने 2018 में सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 से 20 किलो के बीच एमडीएमए ड्रग्स पकड़ी थी। अब पुलिस का दावा है कि इंदौर में उससे भी बड़ी कार्रवाई हुई है।

आर्थिक चुनौतियों का साल

भारत के प्रयासों से देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

कृषि एवं सहायक गतिविधियों की विकास दर दूसरी तिमाही के दौरान आशाजनक रही। खासतौर से खरीफ उत्पादन से संबंधित अनुमान अच्छे संकेत देने वाले रहे। वर्ष 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन 14.45 करोड़ टन के रिकॉर्ड स्तर छूने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 2019-20 के उत्पादन से 0.80 फीसदी अधिक है। दलहन उत्पादन करीब 93.1 लाख टन अनुमानित है, जो 2019-20 की तुलना में करीब इक्कीस फीसदी अधिक है। इसी तरह तिलहन का उत्पादन 2.57 करोड़ टन अनुमानित है, जो 2019-20 की तुलना में 15.28 फीसदी अधिक है। एशियाई विकास बैंक सहित विभिन्न वैश्विक संगठनों के मुताबिक कोविड-19 से जंग में भारत के प्रयासों से देश की अर्थव्यवस्था पर जो भी प्रभाव पड़ा, वह अन्य देशों की तुलना में कम ही रहा। कोरोना महामारी के बीच भारत ने आपदा को अवसर में भी बदला है। ऐसे में वर्ष 2021 की तस्वीर उम्मीदों भरी है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में गिरावट तो आएगी, लेकिन भारत ने कोरोना संकट से निपटने के लिए जिस तेजी से सुधार के कदम उठाए हैं, उससे आगामी वित्तीय वर्ष में भारत 8.8 फीसदी की विकास दर हासिल करने की संभावनाओं वाला देश बन गया है। बस जरूरत है तो इस बात की कि सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेजों पर पूरी ईमानदारी के साथ अमल हो और जरूरतमंदों तक इनका लाभ पहुंचे।

आने वाले साल में मुश्किलें कम नहीं हैं और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए स्पष्ट और ठोस नीतियों की जरूरत है। बीते वर्ष पर नजर डालें तो पाते हैं कि फरवरी के बाद जैसे-जैसे देश पर कोरोना महामारी का साया गहराता गया, वैसे-वैसे देश में अकल्पनीय आर्थिक निराशा और बेरोजगारी का दौर भी बढ़ता गया। कोरोना संकट से उद्योग कारोबार की बढ़ती मुश्किलों के मद्देनजर वित्त मंत्रालय ने 19 फरवरी को कोरोना को प्राकृतिक आपदा का ऐलान कर दिया था। चूंकि भारतीय दवा उद्योग, वाहन उद्योग, रसायन उद्योग, खिलौना कारोबार और बिजली व इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार प्रमुख रूप से चीन से आयातित कच्चे माल व वस्तुओं पर आधारित रहे हैं, ऐसे में इनकी आपूर्ति रुकने से ये उद्योग-कारोबार गंभीर संकट में फंस गए और इनमें से ज्यादातर के सामने बंद होने की नौबत खड़ी हो गई।

खासतौर से देश के करीब 45 करोड़ कार्यबल में से असंगठित क्षेत्र के नब्बे फीसदी श्रमिकों और कर्मचारियों का काम बंद हो गया। लाखों श्रमिक शहर छोड़कर अपने-अपने गांवों को लौट गए। यह वह वर्ग था जिसके पास सामाजिक सुरक्षा की कोई छतरी नहीं थी। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना प्रकोप और पूर्णबंदी से भारत के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के रोजगार पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है। काम-धंधे बंद हो जाने के कारण भारत में लोगों की आमदनी घटी और रोजगार संबंधी मुश्किलें भी बढ़ीं और इस वजह से भारत में एक बड़ी आबादी की खपत का स्तर गरीबी रेखा के निकट पहुंच गया। एक मोटा अनुमान यह है कि कोविड-19 महामारी के कारण भारत की गरीब आबादी में करीब 1 करोड़ 20 लाख लोग और जुड़ गए हैं।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस साल के वैश्विक भूख, कुपोषण और मानव विकास सूचकांक से संबंधित रिपोर्टों में भारत की स्थिति संतोषप्रद नहीं बताई गई है। वैश्विक भूख सूचकांक (जीएचआई) 2020 में 107 देशों की सूची में भारत 94वें स्थान पर है। पिछले साल 117 देशों की सूची में भारत का स्थान 102वां था। यह चिंताजनक है कि देश में खाद्य उपलब्धता और दो तिहाई आबादी के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने के बावजूद देश के करोड़ों लोग भूख और कुपोषण की समस्या से जूझ रहे हैं। विश्व बैंक द्वारा तैयार किए गए 174 देशों के वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक में भारत का स्थान 116वां रहा। यह सूचकांक मानव पूंजी के प्रमुख घटकों स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, स्कूल में नामांकन और कुपोषण पर आधारित है।

कोविड-19 के संकट से चरमराती देश की अर्थव्यवस्था के लिए आत्मनिर्भर अभियान के तहत वर्ष 2020 में मार्च से नवंबर के बीच सरकार ने एक के बाद एक कुल 29.87 लाख करोड़ की राहत पैकेजों का ऐलान किया। इसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान-एक के तहत 11,02,650 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 1,92,800 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 82911 करोड़ रुपए, आत्मनिर्भर भारत अभियान-दो के तहत 73,000 करोड़ रुपए, आरबीआई के उपायों से राहत के तहत 12,71,200 करोड़ रुपए और आत्मनिर्भर भारत अभियान-तीन के तहत 2.65 लाख करोड़ की राहत शामिल थे।

तीसरे आर्थिक पैकेज में दो तरह की राहतें थीं। पहली, दस उद्योग क्षेत्रों के लिए 1.46 लाख करोड़ रुपए की उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन (पीएलआइ) योजना और दूसरी, अर्थव्यवस्था को गतिशील करने के लिए रोजगार सृजन, ऋण गारंटी समर्थन स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास, रियल एस्टेट कंपनियों को कर राहत, ढांचागत क्षेत्र में पूंजी निवेश की सरलता, किसानों के लिए उर्वरक सब्सिडी, ग्रामीण विकास तथा निर्यात सेक्टर को राहत देने के 1.19 लाख करोड़ रुपए के लिए लाभपूर्ण प्रावधान। इन विभिन्न राहतों से तेजी से गिरती हुई अर्थव्यवस्था को बल तो मिला है। यह बात महत्वपूर्ण रही कि जून के बाद अर्थव्यवस्था को धीरे-धीरे खोलने की रणनीति के साथ राजकोषीय और नीतिगत कदमों का अर्थव्यवस्था पर अनुकूल असर पड़ा। हालांकि देश महामारी से नहीं उबरा है, लेकिन अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिखने लगे हैं। कोरोनाकाल में सरकार को उन श्रम, कृषि, कारोबार और अन्य सुधारों को आगे बढ़ाने का भी मौका मिल गया जो दशकों से लंबित थे।

● **धर्मेन्द्र सिंह कथूरिया**

बिगड़े वनों में बढ़ी हरियाली

मप्र में बिगड़े वनों को सुधारने के लिए सरकारी स्तर पर निरंतर प्रयास जारी हैं। प्रदेश के 14 जिलों के 18 वन मंडलों के 7 लाख 35 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में फैले ऐसे 722 माइक्रोवाटर शेड की पहचान कर ली गई है, जो जलवायु परिवर्तन के खतरों से घिरे हैं। राष्ट्रीय जल परिवर्तन कार्य-योजना के अंग के रूप में ग्रीन इंडिया मिशन योजना में अभी तक प्रदेश के 20,192 हेक्टेयर वनों का उपचार किया जा चुका है। इसके साथ ही इन वनों पर आश्रित स्थानीय समुदाय के सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े हितग्राहियों को चिन्हांकित कर उन्हें वैकल्पिक रोजगार के साधन उपलब्ध किए जा रहे हैं।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक लालसिंह रावत ने बताया कि ग्रीन इंडिया मिशन योजना में ऐसे क्षेत्रों का लैंडस्केप आधारित उपचार किया जा रहा है जिनसे जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों से प्रतिकूल प्रभावित होना संभावित है, वहां ऐसे वन क्षेत्रों का ह्रास होने से इन वनों पर आश्रित स्थानीय समुदायों को भी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। रावत ने बताया कि वैज्ञानिकों द्वारा ऐसे क्षेत्रों में फैले माइक्रोवाटर शेड की पहचान कर ली गई है।

वन विभाग द्वारा ग्रीन इंडिया मिशन योजना में वैकल्पिक रोजगार के रूप में प्रदेश के 151 गांवों के 4 हजार 22 हितग्राहियों को पहचान कर उनको आवश्यकता और उनकी अपेक्षा के मुताबिक सिलाई प्रशिक्षण, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, जेसीबी ऑपरेटर, मछली पालन, कांस हस्तशिल्प और मास्क निर्माण आदि गतिविधियों में स्थानीय संयुक्त वन प्रबंधन समिति के माध्यम से प्रशिक्षित कराया जा चुका है। इससे अभी तक 3,461 हितग्राहियों को रोजगार भी मिल चुका है। रावत ने बताया कि उत्तर बैतूल वन मंडल के चापड़ा, पहावाड़ी, पावरझंडा, सेमलपुरा, हीरावाड़ी, जामनगरी, कोठा, मूढ़ा एवं दक्षिण सिवनी मंडल के चिक्लिटोला रमली और पापरिया ग्राम की 225 महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण दिलाया गया। इस प्रशिक्षण के बाद बैंगलुरु स्थित शाही एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 18 महिलाओं का चयन भी कर लिया गया है। इन्हें 9 हजार रुपए प्रतिमाह प्रारंभिक वेतन भी मिलने लगा है। बेरोजगार युवाओं की क्षमता विकास विकसित कराने के लिए उत्तर बैतूल वन मंडल के शाहपुर और भोंरा क्षेत्र के 64 युवक और युवतियों को इलेक्ट्रीशियन एवं मोटर बाइंडिंग का प्रशिक्षण दिलाया गया हैं। इसी तरह इलेक्ट्रीशियन मोटर बाइंडिंग में प्रशिक्षित युवाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना में पंचायतों से बिजली फिटिंग का कार्य मिल गया है। इन्हीं में से प्रशिक्षित युवती रितिका खांडे को मास्टर ट्रेनर का रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है।

सभी रेंज वनों से जुड़ी रिपोर्ट करेंगे तैयार

वन मुख्यालय का निर्देश मिलने के बाद डीएफओ ने सभी रेंज आफिसर्स को निर्देशित किया है कि वह निर्धारित फार्मेट में अपने यहां की जानकारी प्रस्तुत करें। इसमें हर बीट के हिसाब से वन क्षेत्रफल, वन समिति का नाम, कार्य इकाई में प्रस्तावित क्षेत्रफल आदि की जानकारी दी जाएगी। इस रिपोर्ट में भू-आकृति, चट्टानों और मृदा का प्रकार, भूजल स्तर, प्रजातियों के प्रकार आदि की जानकारी देनी होगी। वनों को निजी निवेश पर देने का कारण भी वन मुख्यालय ने स्पष्ट किया है। जिसमें कहा गया है कि अल्पावधि स्थानीय समुदाय को रोजगार में वृद्धि करने और दीर्घावधि में प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित आजीविका को सुदृढ़ करना है। काष्ठ आधारित उद्योगों को स्थानीय उत्पाद उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना भी है। जलवायु परिवर्तन की दिशा में सकारात्मक कदम बढ़ाते हुए हरियाली की मात्रा बढ़ाई जानी है।

मांडू वन परिक्षेत्र के अंतर्गत लगभग 16 हजार हेक्टेयर क्षेत्र की बंजर एवं कम घनत्व वाली भूमि पर 50 हजार पौधे लगाए गए हैं। ग्रीन इंडिया मिशन के तहत वन क्षेत्र के 6 कंपार्टमेंट में काम किया जा रहा है। परिणाम यह है कि एक बार फिर मांडू-धामनोद वन परिक्षेत्र के जंगल मूल स्वरूप में लौटने लगे हैं। जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखकर वन विभाग द्वारा जंगल को हराभरा करने के लिए योजना पर काम किया जा रहा है। इन जंगलों को अलग-अलग उद्देश्यों की पूर्ति जैसे पौधरोपण कर पर्यावरण का सुधार करना, मवेशियों के लिए ग्रासलैंड का विकास करना, पहाड़ों नदी-नालों एवं सड़क के किनारे शेल्टर बेल्ट पर पौधरोपण करना, नगरीय क्षेत्रों के आसपास आमजन को वनों के जोड़ने के उद्देश्य से अर्बन एरिया और रोपण क्षेत्रों का विकास करना है। कई हरे-भरे पेड़ों की प्रजातियों के साथ मांडव की औषधियों के पौधों को भी यहां लगाने की योजना वन विभाग बना रहा है।

योजना के अंतर्गत वनों, वनस्पतियों, वन्यप्राणियों, वनों के जल स्रोतों एवं वनों पर आश्रित समुदायों का विकास इस प्रकार किया जाना प्रस्तावित है, जिससे जलवायु परिवर्तन को ध्यान में वनों का विकास किया जा सकेगा। ग्रीन इंडिया मिशन की पहल अब मांडव के जंगलों में धरातल पर देखने को मिल रही है। जंगलों के उजड़ने के बाद उन्हें संवारने में सरकार की बड़ी रकम खर्च हो रही है। इसके बावजूद जितने पौधे हर साल लगाए जाते हैं उसमें कुछ ही जीवित रह पाते हैं। लगातार बढ़ते खर्च को देखते हुए अब वन विभाग ने तय किया है कि वनों में हरियाली बढ़ाने की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र की कंपनियों को सौंपी जाएगी। इसके लिए सरकार ने वन भूमि को लीज पर देने के नियमों में संशोधन कर दिया है। साथ ही वन मुख्यालय का पत्र सीसीएफ और डीएफओ के पास पहुंच चुका है जिसमें क्षेत्र के वनों की वर्तमान स्थिति मांगी गई है। कंपनियों के साथ अनुबंध करने की जिम्मेदारी सरकार ने अभी अपने पास ही रखी है, वहीं से तय होगा कि रीवा सहित विंध्य के अन्य जिलों के जंगलों की रखवाली आने वाले समय में कौन करेगा।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

नदी जोड़ से बुंदेलखंड को घाटा

बीते तीन दशकों से कागजों पर चल रही बुंदेलखंड की केन व बेतवा नदी को जोड़ने की योजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी फिर से संदिग्धता के दायरे में आ गई है। यह बात साफ होती जा रही है कि 45,000 करोड़ रुपए खर्च कर बुंदेलखंड को पानीदार बनाने का जो सपना बेचा जा रहा है, उसमें पानी तो मिलेगा, पर इसकी कीमत बहुत कुछ देकर चुकानी होगी। नदियों का पानी समुद्र में न जाए, बारिश में लबालब होती नदियां गांवों-खेतों में घुसने के बजाय ऐसे स्थानों की ओर मोड़ दी जाए, जहां इसे बहाव मिले तथा जरूरत पर इसके पानी का इस्तेमाल किया जा सके, इस मूल भावना को लेकर नदियों को जोड़ने के पक्ष में तर्क दिए जाते रहे हैं। पर केन-बेतवा के मामले में तो 'नंगा नहाए क्या निचोड़े क्या' की लोकोक्ति सटीक बैठती है। केन और बेतवा, दोनों का उद्गम स्थल मप्र में है। दोनों नदियां **लगभग समानांतर** एक ही इलाके से गुजरती हुई उप्र में यमुना में मिल जाती हैं। जाहिर है कि जब केन के जल ग्रहण क्षेत्र में अल्प वर्षा या सूखे का प्रकोप होगा, तो बेतवा की हालत भी ऐसी ही होगी। वैसे भी केन का इलाका पानी के भयंकर संकट से जूझ रहा है। वर्ष 1990 में केंद्र की एनडीए सरकार ने नदियों के जोड़ के लिए एक अध्ययन शुरू करवाया था और इसके लिए केन-बेतवा को चुना गया। केन-बेतवा मिलन की सबसे बड़ी त्रासदी तो उप्र झेलेगा, जहां राजघाट और माताटीला बांध पर खर्च अरबों रुपए व्यर्थ हो जाएंगे। यहां बन रही बिजली से भी हाथ धोना पड़ेगा।

राजघाट परियोजना का काम जापान सरकार से प्राप्त कर्जे से अब भी चल रहा है। राजघाट से 953 लाख यूनिट बिजली भी मिल रही है। जनवरी, 2005 में केंद्र के जल संसाधन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में उप्र के अधिकारियों ने कहा था कि केन में पानी की अधिकता नहीं है और इसका पानी बेतवा में मोड़ने से केन के जल क्षेत्र में भीषण जल संकट उत्पन्न हो जाएगा। ललितपुर के दक्षिण और झांसी जिले में बेहतरीन सिंचित खेतों का पानी इस परियोजना के कारण बंद होने की आशंका भी उस बैठक में जताई गई थी।

केन-बेतवा को जोड़ना संवेदनशील मसला है। इस इलाके में सामान्य बारिश होती है और यहां की मिट्टी कमजोर है। यह परियोजना तैयार करते समय इस पर विचार ही नहीं किया गया कि बुंदेलखंड में जौ, दलहन, तिलहन, गेहूं जैसी फसलें होती हैं, जिन्हें सिंचाई के लिए अधिक पानी की जरूरत नहीं होती। जबकि इस योजना में सिंचाई की जो तस्वीर बताई गई है, वह धान जैसी अधिक सिंचाई वाली फसल के लिए कारगर है। इस परियोजना में पन्ना टाइगर रिजर्व पूरी तरह डूब जाएगा। पिछले साल सर्वोच्च न्यायालय भी सवाल कर चुका है कि किस आधार पर इतने महत्वपूर्ण वन की भूमि को डूब में बदलने की अनुमति दी गई।

जलवायु परिवर्तन की वैश्विक त्रासदी में नदी जोड़ के बड़े बांध खलनायक की भूमिका निभाएंगे। इससे जंगल कटेंगे, विशाल जलाशय व नहरों के कारण नए दलदली क्षेत्र विकसित होंगे, जो मीथेन उत्सर्जन का जरिया होते हैं। यह परियोजना 1980 की है, जब जलवायु परिवर्तन या ग्रीनहाउस गैसों की चर्चा भी शुरू नहीं हुई थी। यदि इस योजना पर काम शुरू भी हुआ, तो एक दशक इसे पूरा होने में ही लगेगा तथा इस दौरान अनियमित जलवायु, नदियों के अपने रास्ता बदलने की त्रासदियां और गहरी होंगी।

ऐसे में जरूरी है कि सरकार नई वैश्विक परिस्थितियों में नदियों को जोड़ने की योजना का मूल्यांकन करे। इतने बड़े पर्यावरणीय नुकसान, विस्थापन, पलायन और धन व्यय करने के बाद भी बुंदेलखंड के महज तीन से चार जिलों को मिलेगा क्या, इसका आंकलन भी जरूरी है। इससे एक चौथाई से भी कम धन खर्च कर बुंदेलखंड के पारंपरिक तालाब, बावड़ी, कुओं और जोहड़ों की मरम्मत की जा सकती है। अंग्रेजों के बनाए पांच बांध सौ साल में दम तोड़ गए हैं, आजादी के बाद बने तटबंध व स्टाप डैम पांच साल भी नहीं चले, पर बुंदेलखंड में एक हजार साल पुराने चंदेलकालीन तालाब रख-रखाव के अभाव के बावजूद लोगों के गले व खेत तर कर रहे हैं। बुंदेलखंड की किस्मत बदलने के लिए कम व्यय में छोटी परियोजनाएं ज्यादा कारगर होंगी।

नदी जोड़ने की परियोजना देश की सिंचाई, बाढ़ और खाद्य संकट जैसी बहुत सी समस्याओं को खत्म कर सकती है, लेकिन यह इतना भी आसान नहीं है जितना हमारे राजनेता समझते हैं। बता दें कि नदियों को जोड़ने की चर्चा देश में रह-रहकर उठती रही है। यह सिलसिला 1970 के दशक से लगातार चल रहा है। उन दिनों गंगा को कावेरी से जोड़ने की बात होती थी और अब लगभग 30 नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव है, जिनमें से केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना भी एक है।

● **सिद्धार्थ पांडे**

नदियों को जोड़ने के पीछे असली मकसद

असल में नदियों को जोड़ने के पीछे जो मकसद बताया जा रहा है वह यह है कि देश की नदियों में कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा पड़ा है। अगर नदियों को जोड़ दिया जाएगा तो सिंचाई का रकबा भी बढ़ जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि नदियों में तेजी से पानी घट रहा है। बिहार के सहरसा और खगड़िया जैसे जिलों में आज से कोई दस साल पहले बाढ़ ने अपना घर बना लिया था, लेकिन अब यहां वर्षा 1300 मिलीमीटर से घटकर 1000 मिलीमीटर तक आ गई है, इस कारण वहां की नदियों का जल स्तर भी कम होना पाया गया है, इसकी किसी को कोई चिंता नहीं है। असल सवाल तो यही है कि जब नदियों में पानी ही नहीं होगा तो नदियों को जोड़कर भी क्या कर लेंगे। बहरहाल हम नदियों को जोड़ने का काम शुरू कर भी दे तो इसकी क्या गारंटी की इस योजना का हर राज्य समर्थन ही करेगा। नदी जोड़ परियोजना के मामले में हमें थोड़ा अतीत में झांककर देखना होगा। ज्ञात हो कि पुनर्वास और तटबंधों के रेखांकन को लेकर व्यापक जन-आक्रोश के कारण 1956 के अंत में कोसी नदी के निर्माणाधीन तटबंधों का काम रोक देना पड़ा था। तब यह सवाल बिहार विधानसभा में भी उठा था और उस समय सरकार ने सदन को बताया था कि जनविरोध के कारण काम बंद कर देना पड़ा।

मप्र की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों 2019 में आयकर छापे के दौरान मिली एक हवाला डायरी चर्चा में है। डायरी की जांच के बाद सीबीडीटी की रिपोर्ट को आधार बनाकर केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 3 आईपीएस और 1 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी सहित अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया है, उससे हंगामा मचा हुआ है। सवाल उठता है कि क्या किसी डायरी को आधार बनाकर किसी को दोषी माना जा सकता है।

● राजेंद्र आगाल

मप्र सहित देश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों 7 अप्रैल 2019 में मप्र में मारे गए आयकर छापों के बाद आई सीबीडीटी की रिपोर्ट चर्चा का विषय बनी हुई है। इस छापे में मिली एक हवाला डायरी को आधार बनाकर 3 आईपीएस और 1 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी सहित एक सैकड़ा से अधिक विधायकों, नेताओं और अन्य लोगों को दोषी माना गया है। 904 पेज की रिपोर्ट में 2019 के लोकसभा चुनावों में 281 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी के संग्रह और लेनदेन के रिकॉर्ड हैं। उधर, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने आईपीएस सुशोभन बैनर्जी, संजय माने और वी मधु कुमार और मप्र राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी अरुण मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन देश में अभी तक जितनी हवाला डायरियां सुर्खियों में रही हैं, उनके परिणाम देखकर ऐसा नहीं लगता है कि यह जांच भी किसी मुकाम पर पहुंच पाएगी।

दरअसल, साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कमलनाथ सरकार के समय मप्र में पड़े आयकर विभाग के छापों के दौरान चारों अफसरों और नेताओं के बीच पैसों के कथित लेनदेन का जिक्र मिला था। इन छापों ने मप्र के साथ-साथ देश की सियासत को भी गरमा दिया था जिसने काफी तूल पकड़ा था। आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग के अनुसार हवाला कारोबारी ललित चेलानी के लैपटॉप से चौंकाने वाली एंट्री मिली है। जिन लोगों के यहां आयकर विभाग की कार्रवाई हुई थी, इसमें कमलनाथ के करीबी प्रवीण कक्कड़, राजेंद्र मिगलानी और रिश्तेदार रतुल पुरी की कंपनी के साथ अश्विनी शर्मा, ललित चेलानी के साथ प्रतीक जोशी शामिल रहे। ललित चेलानी के लैपटॉप से पता चला कि लोकसभा चुनाव 2019 से पहले कांग्रेस के कई नेताओं को अवैध परिवहन के जरिए धन पहुंचाया गया। इसी मामले में कानूनी कार्रवाई के लिए प्रस्तावित किया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या **किसी डायरी** या कम्प्यूटर में मिली डीटेल के आधार पर किसी को दोषी मानकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

जैन, सहारा, सोम को भूले लोग

मप्र में इस समय हवाला कांड को लेकर उथल-पुथल मची हुई है। तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जैन हवाला कांड, सहारा हवाला कांड और मप्र के **सोम** डिस्लरी हवाला कांड के परिणाम को देखें तो यह साफ विदित होता है कि डायरियों का भ्रमजाल कुछ दिन, कुछ माह या फिर कुछ साल तक राजनीतिक हंगामा मचाने के अलावा और कुछ नहीं है। आज इन हवाला कांड को लोग भूल गए हैं।

जैन हवाला डायरी का हश्र

सबसे पहले मात्र 64 करोड़ के जैन हवाला घोटाले की चर्चा करें। जैन भाइयों की डायरियों में 1990-91 के दौरान सत्ता और विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं को करोड़ों रुपए देने का जिक्र था। इस हवाला कांड ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। हवाला कांड में नाम आने के कारण लालकृष्ण आडवाणी ने सांसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था तो छत्तीसगढ़ के विद्याचरण शुक्ल और अरविंद नेताम तथा कमलनाथ को कांग्रेस ने लोकसभा टिकट से वंचित कर दिया था। जैन हवालाकांड और डायरी की दिलचस्प दास्ता है। पुरानी दिल्ली के एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में एक पुलिस कांस्टेबल गश्त के दौरान एक कश्मीरी युवक अशफाक हुसैन लोन को संदेह के आधार पर पुलिस थाने ले गया। वहां उस युवक ने स्वयं के कश्मीरी आतंकवादी होने की पुष्टि कर दी। उसके मददगार के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र शहाबुद्दीन गौरी का नाम सामने आया। उसकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में आर्थिक मददगार के रूप में भिलाई (छत्तीसगढ़) के उद्योगपति एसके जैन के एक कर्मचारी जेके जैन का नाम सामने आया। पुलिस एसके जैन तक पहुंची तो छापे में वहां 58 लाख रुपए नगद, दो लाख रुपए के बराबर डॉलर, 15 लाख के इंदिरा विकास पत्र, 2 डायरियां तथा एक नोटबुक भी मिली थी। पता चला कि विदेशों से लाई गई रकम कश्मीर **वामपंथियों** को पहुंचाई जा रही थी। इसी स्त्रोत से लाया गया धन कई बड़े राजनेताओं सहित बड़े अफसरों तक पहुंचाया जा रहा था। कोडवर्ड में कई नेताओं के नाम, रकम डायरी में अंकित थी। फिर सीबीआई की जांच भी दबाव में शुरू की गई। बाद में लीपापोती का दौर चलता रहा। अक्टूबर 1993 में सर्वोच्च न्यायालय में जब अर्जी दी गई तो मामले को दबाए रखने के कारण सीबीआई को फटकार लगाई गई सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका पर मुस्तैदी से कार्यवाही की और संविधान के अनुच्छेद 142 में दिए गए अधिकारों का कारगर ढंग से उपयोग करते हुए केंद्र सरकार और सीबीआई पर इतना दबाव बना दिया कि 7 प्रमुख लोगों के खिलाफ सीबीआई को चालान प्रस्तुत करना पड़ा। वैसे इस मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव तथा आंध्र कैडर के सीबीआई संचालक की भी विशेष भूमिका रही।

नरसिंह राव ने अपने मंत्रिमंडल के 3 वरिष्ठ मंत्रियों सहित राजनीति के महापंडितों पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इन डायरियों में 115 नाम थे जिसमें 92 की पहचान कर ली गई थी। **एसके जैन** ने भी अपने 29 पेज के बयान में किन-किन लोगों को किन-किन परिस्थितियों में पैसा देने की बात स्वीकार की, इसी बयान को सीबीआई ने सबूत के तौर पर पेश किया। डायरी में 115 नामों में 55 राजनेता, 23 अफसर और कम से कम 3 पत्रकार शामिल थे। फरवरी 1988 से मार्च 91 तक 64 करोड़ का भुगतान अलग-अलग लोगों को किया गया था। सबूतों के आधार पर सीबीआई ने 16 जनवरी 1996 में पहले लालकृष्ण आडवाणी और विद्याचरण शुक्ल तथा बाद में 25 नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। लालकृष्ण आडवाणी ने लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा भी तत्काल दे दिया। बाद में 8 अप्रैल 1997 को हाईकोर्ट के न्यायाधीश मो. शमीम ने आडवाणी और विद्याचरण को साफ बरी कर दिया। कोर्ट ने डायरियों को 'बुक ऑफ एकाउंट' यानी पक्के खाते मानने से इंकार कर दिया। यानी वे डायरियां सबूत के तौर पर स्वीकार ही नहीं की गई। भारतीय साक्ष्य कानून के मुताबिक बिजनेस के काम के लिए लगातार अपडेट किए जाने वाले पक्के खातों को सबूत के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है, पर जस्टिस शमीम का कहना था 'कागजों के ऐसे पुलिंदे को जिसमें एक मिनट में कागज निकाले या जोड़े जा सकते हैं', पक्का

आईपीएस अधिकारियों के नाम के आगे 25-25 लाख रुपए

कमलनाथ सरकार के समय पड़े आयकर छापों के दस्तावेजों में लेनदेन करने वाले बड़े चेहरों का खुलासा हुआ है। तीन आईपीएस अधिकारियों सुशोभन बैनर्जी, संजय माने, बी मधुकुमार के साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, बिसाहूलाल सिंह, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, प्रद्युम्न सिंह तोमर, सज्जन सिंह वर्मा के साथ 50 से अधिक वर्तमान विधायकों व नेताओं के नाम हैं। आईपीएस अधिकारियों के नाम के आगे 25-25 लाख रुपए की राशि का जिक्र है। आयकर विभाग दिल्ली की इन्वेस्टिगेशन विंग ने 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़, सलाहकार राजेंद्र मिगलानी, मोजेर बियर कंपनी के मालिक भांजे रतुल पुरी और एक अन्य कारोबारी अश्विन शर्मा के 52 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे थे। 8 अप्रैल को आयकर विभाग ने 14.6 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी बरामद की थी। इसके साथ बड़े पैमाने पर डायरियां और कम्प्यूटर फाइल जब्त की थीं। इनमें सैकड़ों करोड़ रुपए के लेनदेन के हिसाब थे। बाद में आयकर विभाग ने बताया था कि दस्तावेजों में यह प्रमाण मिले हैं कि 20 करोड़ रुपए की राशि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के दिल्ली स्थित मुख्यालय भेजी गई। इन छापों में कुल 281 करोड़ रुपए के लेनदेन के पुख्ता प्रमाण मिले थे। यह पैसा विभिन्न कारोबारियों, राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों से एकत्र किया गया था। यह 20 करोड़ रुपए की नकदी हवाला के माध्यम से तुगलक रोड स्थित एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के मुख्यालय को भेजी गई थी।

खाता नहीं कहा जा सकता।' बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की गई पर नतीजा कुछ नहीं निकला।

सहारा का मिला सहारा

जैन हवाला डायरी की तरह ही 2014 में सहारा समूह पर छापे के दौरान मिली एक डायरी चर्चा का केंद्र बनी रही। इस डायरी में भी बड़े-बड़े लोगों का नाम था। डायरी में करीब 100 से अधिक नेताओं के नाम थे। नवंबर, 2014 में जब मोदी सरकार का कार्यकाल शुरू हो चुका था, आयकर विभाग ने सहारा समूह की कुछ कंपनियों पर छापा मारा। इस छापे में 137 करोड़ रुपए के अलावा **कॉरपोरेट ऑफिस** से कई कम्प्यूटर स्प्रेड शीट और नोट शीट बरामद हुईं। बरामद हुए इन दस्तावेजों ने भी सरकारी कर्मचारियों को किए गए भुगतानों को उजागर किया। एक स्प्रेड शीट में तारीखों, राशियों और 2013-14 तक की 115 करोड़ रुपए नकद की प्राप्ति के स्रोतों का उल्लेख था। ये लेनदेन 40 से 50 अलग-अलग दिनों में किए गए थे। दूसरी तरफ अलग-अलग लोगों को इस नकद के वितरण का उल्लेख था। (सटीक तौर पर कहें, तो 115 करोड़ में से 113 करोड़ का)। इस नकद वितरण के ब्यौरे स्पष्ट लिखे थे। इसमें तारीखें लिखी थीं, जिस व्यक्ति को कैश दिया गया उसका नाम, जिस जगह पेमेंट दिया गया उसका नाम, यहां तक कि जो व्यक्ति यह भुगतान करने गया था उसकी जानकारी भी थी। इस स्प्रेडशीट में जिस व्यक्ति के नाम सबसे ज्यादा भुगतान का उल्लेख था, वे थे 'गुजरात मुख्यमंत्री मोदी जी'। इन सभी एंट्री के मुताबिक उन्हें 9 किश्तों में कुल 40 करोड़ रुपए पहुंचाए गए। इसके बाद दूसरे सबसे बड़े हिस्से का भुगतान हुआ था मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। उन्हें दो तारीखों पर 10 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इसमें अन्य नामों के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को 4 करोड़ और दिल्ली के मुख्यमंत्री (जो उस समय शीला दीक्षित थीं) के नाम 1 करोड़ दर्ज था। एक और नोटशीट में 2010 में विभिन्न लोगों को किए गए पेमेंट के ब्यौरे दर्ज थे।

ये सारे दस्तावेज आयकर अधिकारियों के द्वारा जब्त किए गए थे और इन पर उनके दस्तखत हैं। इसके अलावा इन पर दो गवाहों और सहारा के एक अधिकारी ने दस्तखत किया है। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि इन दस्तावेजों की गंभीरता के बावजूद आयकर विभाग ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत इस मामले की जांच सीबीआई को नहीं सौंपी। इसको लेकर देश की राजनीति में जमकर बवाल मचा। लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सहारा कंपनी ने इनकम टैक्स एक्ट के अनुच्छेद 245 के तहत आयकर विभाग के साथ इस मामले को सुलझाने के लिए सेटलमेंट कमीशन का दरवाजा खटखटाया था। सेटलमेंट कमीशन के सामने आया एक मुद्दा यह था कि क्या स्प्रेडशीट में वर्णित भुगतानों को अघोषित आय के रूप में सहारा की आमदनी के तौर पर शामिल किया जा सकता है? आयकर विभाग ने अपनी टिप्पणी में कहा कि ये भुगतान साफतौर पर प्रामाणिक थे, क्योंकि पहला, ये खाते लंबे समय से चले आ रहे थे और इनकी देखभाल की जा रही थी। दूसरा, क्योंकि स्प्रेडशीट में दिखाई गई नकद प्राप्ति सहारा की मार्केटिंग कम्युनिकेशन कंपनी मैरकॉम के खाते की एंट्री से मेल खाती है। तीसरा, सहारा द्वारा दी गई सफाई जिसमें उसने इन दस्तावेजों की वैधता पर सवाल उठाए थे, विरोधाभासी थी और उन पर यकीन नहीं किया जा सकता था। इसलिए यह साफ था कि सहारा को इस मामले में बेदाग नहीं कहा जा सकता था, लेकिन फिर भी सेटलमेंट कमीशन ने सहारा को आयकर अधिनियम के तहत आपराधिक जवाबदेही से मुक्त कर दिया और उसे छिपाकर रखी गई आमदनी पर एक हजार करोड़ रुपए के करीब का टैक्स भरने का आदेश देकर छोड़ दिया। इससे भी ज्यादा दिलचस्प यह है कि सेटलमेंट कमीशन ने इस मामले का निपटारा रिकॉर्ड समय में यानी सिर्फ तीन सुनवाइयों और तीन महीने से कम समय के भीतर कर दिया। इस मामले में 10 नवंबर, 2016 को फैसला आ गया था। और तो और यह मामला कमीशन के सिर्फ दो सदस्यों ने मिलकर निपटा दिया गया, क्योंकि सरकार द्वारा तीसरे सदस्य का तबादला कर दिया गया था।

जैन हवाला कांड में सब बेदाग

जैन हवाला कांड में उस समय के लगभग सभी बड़े राजनेताओं का नाम सामने आया था। लालकृष्ण आडवाणी, विद्याचरण शुक्ल, अर्जुन सिंह, नारायणदत्त तिवारी, माधवराव सिंधिया, कमलनाथ, बलराम जाखड़, चिमन भाई पटेल, प्रणब मुखर्जी, शरद यादव सहित कई अन्य महत्वपूर्ण नेताओं और बड़े अफसरशाहों के नाम थे। तब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे और कमल मोरारका कार्मिक मंत्री। जैन डायरियां मिलने के बाद हवाला और कश्मीरी अलगाववादियों और नेताओं-अफसरों की जांच करने की बजाय सीबीआई ने पूरे मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की और छापे में बरामद डायरियां और दूसरी चीजें सीबीआई के मालखाने में जमा करवा दी गईं। पूरे दो साल बाद इस मामले में तब फिर जान आई जब डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि हवाला कारोबारी ने लालकृष्ण आडवाणी को दो करोड़ रुपए दिए। कुछ ही दिन बाद वकील राम जेटमलानी ने अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लेकिन उनका जोर लालकृष्ण आडवाणी की बजाय अर्जुन सिंह का नाम सामने लाने पर था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीबीआई डीआईजी ओपी शर्मा भी मौजूद थे और वहीं ऐलान किया गया कि हवाला कांड के मामले में अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। अक्टूबर 1993 में जब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई तो मामले को दबाए रखने के लिए सीबीआई को कोर्ट ने कड़ी फटकार सुनाई और उद्योगपति एसके जैन की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए। इसके बाद मार्च 1994 को जैन को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने सीबीआई को 29 पेज का बयान दिया जिसमें उन्होंने बताया कि किन-किन लोगों को उन्होंने पैसा दिया और किन परिस्थितियों में भुगतान किया गया। इसी बयान में जैन ने सीबीआई को इतालवी व्यापारी ऑतोवियो क्वॉत्रोक्वी से अपनी मुलाकात की बात भी बताई थी। उन्होंने कहा कि वो 1982 में क्वॉत्रोक्वी से मिले थे और उनके जरिए ऊर्जा सेक्टर के 4,000 करोड़ रुपए के ठेके हासिल करना चाहते थे। उन्होंने ये भी कहा कि वो रिलायंस के धीरूभाई अंबानी की तरह धनी संपन्न होना चाहते थे। इन डायरियों में 115 नाम थे जिनमें से 92 नामों की पहचान कर ली गई थी। इनमें से 55 नेता, 23 अफसर और कम से कम तीन पत्रकार थे। लेकिन किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई।

डायरी पर्याप्त सबूत नहीं

लंबे समय तक ये दस्तावेज आयकर विभाग के अंदर ही दफन रहे और जैसे-तैसे 2016 में ही फिर से सामने आ पाए। इन दस्तावेजों से पहली नजर में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत किए गए अपराधों का पता चल रहा था, जिनकी जैन हवाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप गंभीरता से **पूर्ण जांच किए** जाने की जरूरत थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ डायरी में की गई कोड एंट्रियों (जिसमें सिर्फ शुरुआती अक्षर 'इनिशियल्स' और दी गई रकम का जिक्र था) को कोर्ट की निगरानी में जांच बैठाने के लिए पर्याप्त आधार माना था। यह अलग बात है कि कोर्ट के इस आदेश के बावजूद सीबीआई ने जैन डायरियों की जांच के दौरान इसमें शामिल सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति की जांच नहीं की और सिर्फ डायरियों के आधार पर ही चार्जशीट दायर कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसके बाद इस चार्जशीट को इस आधार पर खारिज कर दिया कि महज डायरियों को किसी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता।

सोम डायरी का अता पता नहीं

मप्र में 1993-94 में सोम डिस्लरी के यहां आयकर छापा पड़ा था, जिसमें एक डायरी मिली थी। उस डायरी में मप्र की राजनीति के बड़े-बड़े नेताओं के नाम लेन-देन के जिक्र के साथ अंकित थे। इसको लेकर प्रदेश में जमकर राजनीतिक हंगामा भी हुआ। लेकिन आज सोम डायरी कहां है, इसका कोई अता-पता नहीं है। सोम डिस्लरी का कारोबार आज भी प्रदेश में धड़ल्ले से जारी है और जिन लोगों के ऊपर हवाला के जरिए पैसे लेने के आरोप लगे थे, वे भी अपनी राजनीति कर रहे हैं। दरअसल, कानून के जानकारों का कहना है कि किसी डायरी या कम्प्यूटर में किसी का नाम या किसी को रकम देने का उल्लेख होने भर से अपराध नहीं बनता है। जैन हवाला कांड में जब प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ शब्दों में कहा था कि कागज के टुकड़े को आधार बनाकर जांच का आदेश कैसे दिया जा सकता है। ये प्रमाण बताते हैं कि आयकर छापों में मिली डायरियां केवल राजनीतिक हंगामा मचाती हैं।

ईओडब्ल्यू क्या करेगा जांच?

कमलनाथ के शासनकाल के दौरान 2019 के लोकसभा चुनाव में अवैध लेनदेन मामले में केंद्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड (सीबीडीटी) की रिपोर्ट में जिन पुलिस अफसरों के नाम हैं, उनके खिलाफ राज्य सरकार ने ईओडब्ल्यू से केस दर्ज कर जांच करने का निर्देश दे दिया है। नियमत: ईओडब्ल्यू आर्थिक अनियमितता की जांच करता है। जानकारों का कहना है कि जब आर्थिक अनियमितता हुई ही नहीं है तो ईओडब्ल्यू इस मामले में क्या कर सकता है। दरअसल, केंद्रीय चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश पर राज्य सरकार ने 3 आईपीएस और 1 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के खिलाफ ईओडब्ल्यू में केस दर्ज करवा दिया है लेकिन जांच में कुछ निकलने वाला नहीं है। राज्य सरकार अब 3 आईपीएस अफसर सुशोभन बनर्जी, संजय माने और वी मधुकुमार के साथ राज्य पुलिस सेवा के अफसर अरुण मिश्रा को आरोप पत्र देकर जवाब तलब करेगी। इधर, आरोपी अफसरों ने भी अपने बचाव में मोर्चा खोल दिया है। इन अफसरों ने सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि आयकर की अप्रेजल रिपोर्ट के आधार पर सरकार को कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अप्रेजल रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किया जा सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला भी दिया गया है।

सरकार को लिखे पत्र के बारे में चारों अफसर मीडिया से कुछ भी कहने से इंकार कर रहे हैं। हालांकि एडीजी सुशोभन बनर्जी ने सरकार को पत्र लिखने की पुष्टि की है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हम अपना पक्ष सरकार के सामने रखेंगे, ना कि मीडिया के सामने। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुमति दिए जाने की जानकारी मिलने के बाद आरोपी अफसरों ने भी मोर्चा खोल दिया है। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग ने सीबीडीटी की रिपोर्ट मप्र सरकार को भेजने के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को आरोपी 3 आईपीएस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। इससे पहले आयोग ने मप्र के मुख्य सचिव और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को 5 जनवरी को तलब कर इस मामले में की गई कार्रवाई के बारे में पूछा था। हालांकि इससे पहले ही राज्य शासन ने रिपोर्ट आर्थिक अपराध

डायरियों के धमाके

बड़े लोगों का कद ही कुछ ऐसा है कि उनकी व्यक्तिगत डायरियां कई साल बाद भी सियासी तूफान खड़ा करने का दमखम रखती हैं। इनमें से कुछ का जिक्र हम यहां कर रहे हैं।

गाइडो हेशके की डायरी: अगस्ता-वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील में बिचौलिए की भूमिका अदा करने वाले स्विस-इतालवी की डायरी ने दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में बवाल मचा दिया। इसी डायरी से पता चला कि इस लेनदेन में 16 लाख यूरो की रिश्वत दी गई है। इस डायरी में किसी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन नामों के पहले अक्षर लिखे हैं और अब जांचकर्ता इस बात का पता लगाने में जुटे हैं कि जीके, एपी, सीएएफ, पीजी, सीएम, एलएम और जूली का जिक्र किन लोगों के लिए किया गया है।

मार्टिन अर्दबो की डायरी: मार्टिन अर्बदो बोफोर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, जो स्वीडन की हथियार बनाने वाली कंपनी है। साल 1987 में बोफोर्स पर आरोप लगा कि उसने एक डील हथियाने के लिए भारतीय नेताओं और अफसरों को 4.9 करोड़ डॉलर की रिश्वत दी है। अर्दबो की निजी डायरी स्वीडिश पुलिस ने अपने कब्जे में ली थी, जिसमें आर, पी, एन, नेरो, जीपीएचएच, जीपी, एसपी, और क्यू जैसे अक्षर लिखे थे।

बिड़ला की डायरी: कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में सीबीआई को आदित्य बिड़ला समूह के अधिकारियों से डायरी मिली थी। इस डायरी में लिखा था कि तालाबीरा ब्लॉक हिंडाल्को को देने की ऐवज में दस साल की अवधि के दौरान बिड़ला कंपनी के एक ट्रस्ट ने नेताओं और सांसदों को 1,000 से ज्यादा भुगतान किए।

शिवशंकर भट्ट की डायरी: रायपुर में सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के दफ्तर में छापे के दौरान भट्ट की डायरी मिली। वो निगम में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। इसमें नाम भी थे और अक्षर भी। उनके सामने रकम लिखी थी। 1,50,000 करोड़ रुपए के पीडीएस घोटाले में कई मंत्रियों और मुख्यमंत्री रमन सिंह, उनकी पत्नी का नाम आया। साथ ही अधिकारियों पर आरोप लगे कि उन्होंने मिल मालिकों और राशन की दुकानवालों के साथ मिलकर गरीब परिवारों को खराब चावल मुहैया कराए।

ए राजा की डायरी: 2जी घोटाले में सीबीआई का आंकलन है कि सरकारी खजाने को करीब 4.6 अरब डॉलर का घाटा हुआ। इस मामले में ए राजा और कनिमोझी जैसे नेताओं का नाम उछला। राजा के मकान से तीन डायरी मिलीं, जिनमें तमिल और अंग्रेजी में एंट्रीज लिखी गई थीं। इसमें साल 2003 से लेकर 2010 तक का कारोबारी ब्यौरा था। साथ ही मामले में शामिल बिचौलिए के नाम और नंबर भी थे।

कमलनाथ सरकार के हवाला कांड में नाम

इन नेताओं तक हवाला के जरिए कालाधन पहुंचा

सीबीडीटी की रिपोर्ट के अनुसार 7 अप्रैल 2019 को आयकर ने छापे मारे थे, उनमें मप्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी 5 लोग शामिल थे। जिसमें बड़े पैमाने पर पैसों के लेनदेन के सबूत मिले थे। इसके बाद इकट्ठा किए गए सबूत और रिपोर्ट सीबीआई को भेज दिए गए थे। आयकर विभाग ने चुनाव आयोग को जो साक्ष्य और जांच रिपोर्ट सौंपी, उसमें लोकसभा चुनाव के दौरान 11 उम्मीदवारों को कथित तौर पर भारी रकम ट्रांसफर किए जाने का आरोप है। जिन नेताओं तक हवाला के जरिए कालाधन पहुंचने का जिक्र है, उनमें अजय सिंह, कम्प्यूटर बाबा, शाद अहमदाबाद, योगेश राठौर, रणदीप सुरजेवाला, दिग्विजय सिंह, अभिषेक मिश्रा, फुंदेलाल मार्को, विजय राघवेंद्र सिंह, ओमकार सिंह मरकाम, नारायण पट्टा, योगेंद्र बाबा, डॉ. असोक मर्सकोले, अर्जुन काकोदिया, संजय उइके, ब्रह्मा भलावी, भूपेंद्र मरावी, सज्जन सिंह, बाबू जंडेल, बैजनाथ कुशवाहा, प्रवीण पाठक, घनश्याम सिंह, गोपाल सिंह चौहान, तनवर लोधी, नीरज दीक्षित, विक्रम सिंह नातीराजा, शिवदयाल बागरी, सिद्धार्थ कुशवाहा, संजय यादव, शशांक भार्गव, आरिफ मसूद, गोवर्धन सिंह दांगी, बापू सिंह तोमर, महेश परमार, राजेश कुमार (सपा), राणा विक्रम सिंह, देवेंद्र पटेल, रामलाल मालवीय, मुरली मोरवाल, झूमा सोलंकी, सचिन बिड़ला, रवि रमेशचंद्र जोशी, केदार चिड़ाभाई डावर, ग्यारसीलाल रावत, चंद्रभागा किराड़े, मुकेश रावत पटेल, कलावती भूरिया, वीरसिंह भूरिया, वाल सिंह मेढ़ा, प्रताप ग्रेवाल, पांचीलाल मेढ़ा, हर्ष विजय सिंह गेहलोत, आरकेएम, मीनाक्षी नटराजन, कमल मरावी, प्रमिला सिंह, मधु भगत, देवाशीष जरारिया, शशि कर्णावत, शैलेंद्र सिंह दीवान, कविता नातीराजा, मुकेश श्रीवास्तव, ब्रजेश पटेल, बिरला लोधा आदि। इनके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस से भाजपा में गए नेताओं में बिसाहूलाल सिंह, प्रद्युम्न सिंह तोमर, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, एदल सिंह कंसाना, गिर्राज दंडोतिया, रणवीर जाटव, कमलेश जाटव, रक्षा संतराम सिरोनिया, प्रद्युम्न लोधी, राहुल लोधी, नारायण सिंह पटेल, सुमित्रा देवी कास्देकर एवं मनोज चौधरी। बसपा के रामबाई और संजीव सिंह कुशवाह (भाजपा के साथ) हैं। लेनदेन का ये सारा हिसाब 2018 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ।

अन्वेषण ब्यूरो को भेजकर प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने के निर्देश दे दिए थे।

रिपोर्ट में 64 विधायकों के नाम

सीबीडीटी की रिपोर्ट में तत्कालीन कमलनाथ सरकार के मंत्री सहित 64 विधायकों के नाम हैं। इनमें से 13 विधायक रिपोर्ट आने से पहले भाजपा का दामन थाम चुके हैं। भाजपा के 13 में से 8 विधायक (इसमें से दो प्रद्युमन सिंह तोमर और राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव मंत्री भी हैं) सिंधिया समर्थक हैं। रिपोर्ट में सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम नहीं है, लेकिन दिग्विजय सिंह पर लोकसभा चुनाव में 90 लाख रुपए मिलने के आरोप हैं। दरअसल, सीबीडीटी की रिपोर्ट प्रतीक जोशी की डायरी, दस्तावेज, कम्प्यूटर फाइल, व्हाट्सएप मैसेज के साथ प्रतीक और ललित चेलानी के बीच चैट के आधार पर है। ये सत्यापित करना एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही सीबीडीटी की रिपोर्ट में जिन लोगों के नाम हैं, उन्हें कोई समन जारी नहीं हुआ है। सचिवालय में कार्यरत एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सीबीआई ने चुनाव आयोग की सिफारिश लेने से इनकार क्यों किया? ये सभी जानते हैं कि हवाला कांड कैसे चला गया। वहीं, इस मामले में स्वतंत्र साक्ष्यों के आधार पर एफआईआर संभव है। किसी के भी खिलाफ आपराधिक मामले के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य ढूंढने होंगे। वहीं, चुनाव आयोग के इस कदम ने कइयों को हैरानी में डाल दिया है। सूत्रों के अनुसार, सीबीडीटी की रिपोर्ट पर आपराधिक मामलों के लिए सिफारिशें मप्र सरकार को दी गई हैं। रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा चुनावों में एक आईपीएस अधिकारी के 25 लाख रुपए के कथित योगदान का जिक्र है। वहीं, आयकर विभाग के छापे के दौरान प्रतीक जोशी की डायरी और व्हाट्सएप संदेशों में भी ये है। वहीं, सीबीडीटी की रिपोर्ट में नामित एक अधिकारी ने बताया कि अगर सरकार सीबीडीटी की रिपोर्ट को ध्यान में रखती है, तो उसे 2013 के विधानसभा चुनावों से पहले एक कंपनी की तरफ से मुख्यमंत्री के ओएसडी को मिले 10 करोड़ रुपए की रिश्वत को भी शामिल करना चाहिए। मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाकर इस मामले में जांच की मांग की थी। अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि अगर 2019 लोकसभा चुनावों के बारे में आईटी रिपोर्ट पर ध्यान दिया जा रहा है तो अन्य विधानसभा चुनावों पर आईटी रिपोर्ट को शामिल क्यों नहीं किया जाता है। एक साथ दोनों रिपोर्टों पर कुछ निष्पक्ष जांच होने दें।

बेघर घुमंतू जातियों का दर्द

आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने वाले घुमंतू (घुमक्कड़) लोग आज भी बेघर हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी 193 लड़ाका जनजातियों के लोगों को अंग्रेजों ने ही क्रिमिनल ट्राइब यानी अपराधी समूह का दर्जा दिया था। सन् 1871 में इन लड़ाकू 193 जातियों को अंग्रेजों ने आपराधिक जातियां घोषित कर दिया था, जिन्हें देखते ही मार देने तक के आदेश पास हुए थे। कथित तौर पर अपराधी घोषित इन जातियों में बंजारा, बाजीगर, सिकलीगर, नालबंध, सांसी, भेदकूट, छड़ा, भांतु, भाट, नट, डोम, बावरिया, राबरी, गंडीला, गाडियालोहार, जंगमजोगी, नाथ, पाल, गड़रिया, बघेल, मल्लाह, केवट, निषाद, बिंद, धीवर, डलेराकहार, रायसिख, महातम, लोहार, बंगाली, अहेरिया, बहेलिया, नायक, सपेला, सपेरा, पारधी, लोध, गूजर, सिंघिकाट, कुचबंध, गिहार, कंजड़ आदि सम्मिलित थीं। अंग्रेज इन जातियों के गुरिल्ला युद्ध और हमलों से परेशान थे।

आज देश में बहुत से लोगों को आजादी का श्रेय जाता है। लेकिन देश के तथाकथित पूंजीवादी और सत्ताधारी उन लोगों को आजादी का सिपाही नहीं मानते, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई में अपने परिवार तक तबाह कर डाले। ऐसे लोगों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और वन्य जातियों के अलावा घुमंतू जातियों के लोग भी शामिल रहे हैं। यह दुर्भाग्य ही है कि जिन लोगों ने देश की आजादी में चुपचाप अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी-बड़ी लड़ाईयां लड़ीं, खुद के साथ-साथ अपने परिवार, कुनबे की बलि दे दी; लेकिन उन्हीं लोगों की पीढ़ियों को सम्मान तो दूर की बात आज तक जीने का हक भी नहीं मिल सका है। हमारा देश 15 अगस्त, 1947 को आजाद जरूर हो गया, मगर विमुक्त घुमंतू जातियों के चार करोड़ लोग आज भी अपने ही वतन में गैर-मुल्कियों जैसा ही जीवन जी रहे हैं। यह अलग बात है कि इनमें से कई को नौकरियां भी मिली हैं, बहुत से बस्तियों में रहते भी हैं; लेकिन अधिकतर आज भी बेघर ही हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने 31 अगस्त, 1952 को एक कानून बनाकर इन्हें स्वतंत्र घोषित किया था, लेकिन इनमें अधिकतर जातियां सामाजिक भेदभाव और तिरस्कार की शिकार हैं। यही वजह है कि अंग्रेजों की आंखों की किरकिरी बनने वाली ये जातियां आज भी दर-ब-दर हैं और जंगलों में भटकती हैं। स्वतंत्रता की लड़ाई में क्रांतिकारियों के संदेशवाहक की भूमिका अगर किसी ने सबसे ज्यादा निभायी, तो वे भी घुमंतू लोग ही थे। अपनी युद्ध कला, बलिष्ठता, बुद्धि, लड़ाकेपन, आपराधिक बुद्धि और भेष बदलने में माहिर होने का भरपूर उपयोग इस समाज के लोगों ने अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने में किया था। जंगलों में रहने के कारण ये लोग अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आते थे। लेकिन फिर भी इनके कई दलों को अंग्रेजों ने पकड़-पकड़कर मौत की नींद सुला दिया था।

सन् 1857 के बाद से ही इनकी निगरानी के लिए अंग्रेजों ने देशभर में 50 से अधिक अलग बस्तियां बना दी थीं, जिनका काम घुमंतुओं की गतिविधियों पर नजर रखना होता था। दुर्भाग्य यह है कि आज भी खुद को सभ्य मानने वाले समाज ने इन्हें नहीं अपनाया है। देश के लिए जान देने वाले और अपने नागरिक अधिकारों को खो देने वाले इन लोगों को समाज के लोगों से घृणा और तुच्छता के अलावा कुछ नहीं मिला। हां, एक समय में इन्हें भीख की तरह खाने-पीने की चीजें जरूर मिलती थीं; लेकिन वो भी किसी काम या किसी चीज के बदले। हालांकि अब इन जातियों के कुछ लोग भिक्षावृत्ति में भी उतर गए हैं।

आज विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों की कुल आबादी करीब 12 से 13 करोड़ है। एक अनुमान के मुताबिक, इनमें से 78 फीसदी के पास न तो रहने को घर है और न जिंदगी को संवारने के अन्य मूलभूत संसाधन, जिनमें शिक्षा एक महत्वपूर्ण अंग है। संविधान के लागू होने के बावजूद आज भी इन्हें सभी नागरिक अधिकार नहीं मिले हैं, जिससे इन्हें **दस्तावेज** बनवाने, बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने और सरकारी नौकरियां पाने में बहुत दिक्कतें आती हैं। अलग-अलग राज्यों में इन्हें अलग-अलग जाति-वर्ग में रखा गया है, जिससे कई राज्यों में इन्हें वो फायदे भी नहीं मिल पाते, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को मिलते हैं; जबकि इनका जीवन उनसे भी निम्न स्तर का है। कला में माहिर घुमंतू लोग समाज के लिए त्यागी प्रवृत्ति के थे। कहा जाता है कि बाल काढ़ने की कंघी, पांव की महावर और महिलाओं के साज-सज्जा की कई अन्य चीजें इन्हीं घुमंतू जातियों की महिलाओं की देन हैं।

● **राजेश बोरकर**

आजीविका के लिए व्यापार

घुमंतू जातियों को लूटपाट करने वाला, अपराधियों की तरह से सभ्य समाज में देखा जाता रहा है। लोग इन्हें बहुत ही नीचे का मानते हैं और इनके पास आने को भी गुनाह जैसा समझते हैं। लेकिन यह बहुत बड़ी बात है कि इन जातियों की आजीविका व्यापार पर चलती रही है। इन जातियों का काम लोहे के हथियार, हींग, मसाले, जंगली जड़ी-बूटियां, गोंद, पालतू जानवर, मोर पंख, फल-फूल आदि बेचना रहा है। इन जातियों के लोग पहले से ही बहुत-सी बहुमूल्य बेचकर अपनी आजीविका चलाने वाले स्वाभिमानी लोग रहे हैं। लेकिन सभ्य कहे जाने वाले समाज ने इन्हें कभी भी अच्छा नहीं माना। आज भी इन्हें जिस दृष्टि से समाज में देखा जाता है, वह इनका अपमान ही कहा जाएगा। मानव इतिहास सदियों पुराना है। अगर भारत के इतिहास को गौर से देखें, तो पता चलता है कि किसी दौर में यहां राज करने वाले लोगों को विदेशी आक्रमणकारियों ने हराकर दर-ब-दर कर दिया या फिर गुलाम बनाया। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। जैसे चमड़े का काम करने वाली जाति के लोगों का इतिहास अगर उठाकर देखें, तो पता चलता है कि इस जाति के लोगों के पूर्वज कभी भारत में शासक हुआ करते थे। लेकिन विदेशी ताकतों ने उन्हें युद्ध में हराकर उनसे निम्न स्तर के काम कराए और उन्हें गुलाम बनाकर रखा ताकि वे निकृष्ट बने रहें। इसी तरह दूसरी अनुसूचित जातियों के पूर्वज भी इस देश के मूल निवासी और अलग-अलग दौर के शासक रहे हैं। घुमंतू जाति के लोगों का कहना है कि उनके पूर्वजों ने विदेशी ताकतों का गुलाम बनने से ज्यादा बेहतर घर-बार छोड़कर खानाबदोश यानी खानाबर्बादी की जिंदगी को चुना और खुद जंगलों में जाकर रहने लगे। यही वजह है कि हम लोग आज भी दर-ब-दर हैं।

दिशाहीन विपक्ष

भारतीय इतिहास में पिछले 6 साल ऐसे रहे हैं, जहां विपक्ष पूरी तरह दिशाहीन नजर आया है। विपक्ष के सामने मुद्दों का अभाव हो लेकिन वह उन मुद्दों को धार देने और जनता को उनसे जोड़ने में विफल रहा है। 2020 में सीएए, कोरोना संकट, चीनी घुसपैठ जैसे कई मुद्दे विपक्ष को मिले लेकिन किसी को भी वह भुनाने में विफल रहा। खासकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस तो सबसे कमजोर नजर आई। वहीं अन्य विपक्षी पार्टियां भी भाजपा को घेरने के मुद्दे गंवाती रही।

सत्तापक्ष की तरह विपक्ष की भी एक प्रकृति होती है। दुख की बात है कि भारतीय राजनीति में पिछले 5-6 वर्षों के दौरान विपक्ष की इस प्रकृति में विकृति पनपती दिख रही है जिसमें विरोध नीतियों के बजाय व्यक्ति केंद्रित हो गया है। इसमें देशहित के खिलाफ मुखरता को भी लोकतंत्र की लड़ाई का नाम देकर सही ठहराया जाने लगा है। यही कारण है कि 2014 से लगातार हाशिये पर खिसकते जा रहे विपक्ष ने अब अपनी पहचान भी खोनी शुरू कर दी है। देखा जाए तो एक सर्वमान्य और सक्षम नेतृत्व का अभाव आज विपक्ष का सबसे बड़ा संकट है। हालांकि कांग्रेस राहुल गांधी को सर्वमान्य नेता बनाने की असफल कोशिश करती रही है, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिली है। लिहाजा अब खुद पार्टी के ही कई नेताओं ने खुलकर कह दिया है कि या तो परिवारवाद जिंदा रह सकता है या फिर पार्टी, लेकिन कांग्रेस में अभी भी परिवार का झंडा उठाने वालों की संख्या ही अधिक है।

राहुल गांधी की अनियमितता और अहम मौकों पर छुट्टी पर जाने की उनकी आदत ने विपक्ष के दूसरे दलों को भी असहज करना शुरू कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में मतों की गिनती के बीच उनका छुट्टी पर जाना राजद को रास नहीं आया था। यहां तक कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी उनकी योग्यता पर संदेह जता दिया। एक तरह से कांग्रेस में नेतृत्व का संकट विपक्ष का नेतृत्व संकट भी बन गया है। निकट भविष्य में इस संकट का समाधान भी होता नहीं दिख रहा।

दरअसल विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है, जिसकी अखिल भारतीय पहचान हो। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन और स्टालिन जैसे नेता अपने-अपने राज्यों में तो भीड़ जुटा सकते हैं, लेकिन उसके बाहर उनका कोई प्रभाव नहीं है। इनमें किसी एक नेता को सभी विपक्षी दल अपना नेता मानने को भी तैयार नहीं हैं। ले-देकर एकमात्र शरद पवार ऐसे विपक्षी नेता हैं, जिनका सम्मान सभी दलों के नेता करते हैं। उनकी पार्टी राकांपा भले महाराष्ट्र में सिमटी हुई है, लेकिन उनमें विपक्ष को एकजुट करने की क्षमता है। शायद यही कारण है कि शिवसेना की ओर से संप्रग के नेतृत्व के लिए शरद पवार का नाम उछाला गया है, लेकिन यह भी तय है कि कांग्रेस किसी भी स्थिति में संप्रग की कमान किसी दूसरे दल और उसके नेता के हाथों में जाने नहीं देगी। इस सिलसिले में कांग्रेस नेताओं के बयान आने भी शुरू हो गए हैं।

विपक्ष में सक्षम नेतृत्व के संकट का एक आयाम यह भी है कि लगभग सभी दल परिवार आधारित होकर रह गए हैं। कांग्रेस, तृणमूल, राजद, सपा, बसपा, झामुमो, द्रमुक, राकांपा, जदएस-सभी में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। ये परिवार आधारित पार्टियां सैद्धांतिक रूप से लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए फिट नहीं हैं।

बिहार में भाजपाई घोड़े को रोकने में विपक्ष रहा नाकामयाब

राजनीतिक अश्वमेध के भाजपाई घोड़े को रोकने के लिए विपक्ष ने बिहार में 15 साल पुरानी नीतीश कुमार सरकार को निशाना बनाया। कोरोनाकाल में लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों की परेशानियों के साथ-साथ लालू यादव के जंगलराज के बाद पली-बढ़ी पीढ़ी को रोजगार का सब्जबाग दिखाकर राजग और खासकर नीतीश कुमार के खिलाफ जबरदस्त माहौल बनाया गया। मुस्लिम-यादव गठजोड़ के साथ अन्य जातियों के नाराज युवाओं को जोड़कर इस फॉर्मूले को अजेय साबित करने की कोशिश हुई। हालांकि जेपी नड्डा की अध्यक्षता में पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरी भाजपा ने चुनावी पंडितों और एक्जिट पोल के आंकलनों को धता बताते हुए न केवल सत्ता बचाई, बल्कि कम सीटों पर लड़कर भी राजद के बराबर सीटें लाकर साबित किया कि बिहार की जनता को भाजपा की विकास नीतियों में पूरा भरोसा है और वह अभी तक लालू यादव के जंगलराज को पूरी तरह नहीं भूली।

लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती, शिबू सोरेन, शरद पवार और ममता बनर्जी जैसे नेता अपने दम पर जनता का भरोसा जीतने में सफल रहे, मगर बाद में उन्होंने ही नेतृत्व के स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया को रोककर उसे परिवार के हाथों में सौंप दिया। वैसे संख्या बल में देखें तो मौजूदा समय में भी लगभग 200 सांसदों के साथ विपक्ष को कमजोर नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह संख्या बल इतने टुकड़ों में बंटा है और उनके आपसी हित इस तरह आपस में टकराते हैं कि वे किसी भी मुद्दे पर एकजुट होकर सरकार को चुनौती देने की स्थिति में नहीं आ पाते। विपक्ष की इस कमजोरी का सीधा फायदा सत्तापक्ष को मिल रहा है। कहने को तो भाजपा के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस, वामपंथी दल और कांग्रेस एक हैं, लेकिन बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दल तृणमूल के खिलाफ खड़े हैं। वहीं केरल में कांग्रेस और वामपंथी घनघोर विरोधी हैं। ओडिशा में बीजू जनता दल और आंध्रप्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस भाजपा के बजाय कांग्रेस को अपना बड़ा दुश्मन मानती है। जाहिर है आपसी लड़ाई में विपक्ष की पहचान गुम हो गई है, जिसे हासिल करना निकट भविष्य में संभव नहीं दिख रहा है।

उधर मोदी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ जरूरतमंदों को मिल रहा है। इससे भाजपा का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। अपने खोते जनाधार को बचाने के लिए विपक्ष शासित कई राज्य इन योजनाओं के क्रियान्यवन को बाधित करने में जुटे हैं, लेकिन इससे विपक्ष को ही नुकसान होने का खतरा ज्यादा है। मोदी सरकार देश में 9 करोड़ किसानों को हर चार महीने पर प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत दो हजार रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया करा रही है, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने इस योजना को यह कहते हुए लागू नहीं होने दिया कि केंद्र सरकार किसानों के खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर करने के बजाय राज्य सरकार को दे। राज्य सरकार उसे किसानों को वितरित करेगी, लेकिन मोदी सरकार ने सिर्फ बंगाल के लिए योजना में बदलाव से इंकार कर दिया है। इस लड़ाई में नुकसान किसानों का हो रहा है। इसका खामियाजा अगले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है।

ऐसा नहीं है कि विपक्ष के सामने मुद्दों का अभाव हो, लेकिन वह उन मुद्दों को धार देने और जनता को उनसे जोड़ने में विफल रहा है। 2020 में सीएए, कोरोना संकट, चीनी घुसपैठ जैसे कई बड़े मुद्दे विपक्ष को मिले, लेकिन उनमें से किसी को भी वह भुनाने में विफल रहा। हालांकि सीएए के मामले में विपक्षी दलों में एकता देखने को जरूर मिली और उससे सरकार भी बैकफुट पर नजर आई, लेकिन मुसलमानों के एक तबके और कुछ वामपंथी संगठनों के अलावा उसे आम लोगों का व्यापक समर्थन नहीं मिला। वहीं कोरोना संकट और चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर जिस तरह से कांग्रेस ने सवाल उठाए और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ व्यक्तिगत हमले किए, वह कई विपक्षी दलों को भी रास नहीं आया। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने की कीमत लोकसभा चुनाव में चुकाने के बाद भी कांग्रेस नहीं चेती। देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता के मुद्दे पर कांग्रेस का अकेले पड़ जाना सरकार के खिलाफ मुद्दों की पहचान में उसके नेतृत्व की अपरिपक्वता और दूरदर्शिता के अभाव को साफ दर्शाता है। उम्मीद है कि आगामी साल में इन सबसे विपक्ष कुछ सीख लेगा और अपनी प्रकृति में आई इस विकृति को दूर करेगा।

राष्ट्रीय राजनीति और लोकसभा चुनाव में मोदी और भाजपा के समक्ष मुकाबले में भी नजर न आने वाले विपक्ष की उम्मीदें अब राज्यों के विधानसभा चुनावों तक ही सीमित हैं, जहां दो ध्रुवीय राजनीति है या फिर भाजपा अकेलेदम चुनाव न लड़ पाने की स्थिति में है। अगर वहां भी विपक्ष **आत्मघाती रणनीति** से जीती हुई बाजी हारेगा तो तय मानिए कि भारतीय राजनीति में सशक्त विपक्ष का शून्य भरने के बजाय और पराभव का विस्तार ही पाएगा। बेशक यह संकट पूरे विपक्ष का है। आखिर 2017 में हम देश के सबसे बड़े राज्य उप्र का विधानसभा चुनाव परिणाम देख चुके हैं। दो दशक से भी ज्यादा समय तक उप्र की राजनीति ही नहीं, सत्ता पर भी दो क्षेत्रीय दलों (सपा-बसपा) का वर्चस्व रहा, लेकिन 2017 के विधानसभा और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी की भाजपा की ऐसी लहर चली कि शेष सभी दलों का अस्तित्व ही संकट में नजर आने लगा है। फिर भी कांग्रेस का संकट इसलिए ज्यादा बड़ा और चिंताजनक है, क्योंकि वह देश की आजादी के आंदोलन से निकली पार्टी है और जाति-वर्ग-संप्रदाय से ऊपर उठकर उसकी स्वीकार्यता रही है, पर 2014 के लोकसभा चुनाव में हुए ऐतिहासिक पराभव के बाद लगता है मानो कांग्रेस का अपना आत्मविश्वास डगमगा गया है। यह सही है कि अतीत में भी केंद्र की सत्ता से बेदखल कांग्रेस वापस लौटी है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ सत्ता से बेदखली तक सीमित नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मात्र 44 और 2019 के लोकसभा चुनाव में 52 सीटों पर सिमट जाना बताता है कि फिसलती कांग्रेस का संकट कितना गहरा है। चाहे 1977 की हार हो या फिर 1989 और 1996 की, कांग्रेस सत्ता से बेदखल हुई थी, पर राजनीतिक दल के रूप में उसका आत्मविश्वास और प्रासंगिकता, दोनों ही बरकरार थीं। इस बार का संकट गहरा इसलिए है कि अब आत्मविश्वास और प्रासंगिकता, दोनों पर ही सवालिया निशान लग गया है। ऐसे में विपक्ष भाजपा के अजेय रथ को कैसे रोक पाएगा यह सवाल देश की राजनीतिक वीथिका में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है।

● **इन्द्र कुमार**

भाजपा को राज्यसभा में अपना संख्याबल बढ़ाने में मिली सफलता

इस साल भाजपा को राज्यसभा में अपना संख्याबल बढ़ाने में भी सफलता मिली। राज्यसभा में अल्पमत के कारण ही सरकार सुधारों के एजेंडे पर अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इसके चलते उसे कई विधेयक मनी बिल के रूप में पारित कराने पड़े जिसकी आलोचना भी हुई। कई राज्यों में मिली मजबूती से राज्यसभा में दमदार हुई भाजपा को अब अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। वर्ष 2020 में भाजपा ने विपक्षी दलों को राजनीति का एक नया पाठ भी पढ़ाया। वह यह कि राजनीति के शिखर की सीढ़ी निचले पायदान से शुरू होती है। हैदराबाद का स्थानीय निकाय चुनाव इसकी मिसाल बना जहां पार्टी के तमाम दिग्गज नेता सक्रिय रहे।

भाजपा का चक्रव्यूह

पश्चिम बंगाल विस चुनाव का रण सज गया है। सत्तारूढ़ टीएमसी को घेरने के लिए भाजपा ने चक्रव्यूह बना दिया है। इस कारण राज्य में शह-मात का खेल जोरों पर है। कभी शाह की रणनीति कारगर साबित होती है, तो कभी ममता बाजी मार ले जाती हैं, लेकिन कई मोर्चे हैं, जहां भाजपा को अभी काम करने की जरूरत है। अब देखना यह है कि सत्ता के इस खेल में भाजपा पश्चिम बंगाल में भगवा फहरा पाती है या नहीं।

शाह और ममता के शह-मात से पश्चिम बंगाल का विस चुनाव रोचक हो चला है। शाह के दौरे पर हमले हुए तो ममता ने जांच के आदेश दिए। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हमले भी हो चुके थे। भाजपा की सियासी कोशिशों को ममता करतूत यानी नौटंकी करार दे रही हैं, तो भाजपा विस चुनाव को सत्ता परिवर्तन का अवसर बताने के अभियान पर है। ममता भाजपा को बाहरी बताने के लिए मजाक उड़ाते हुए कहती हैं भाजपा वालों के पास कोई काम नहीं बचा, जब देखो शाह चले आते हैं, तो कभी-कभी कुछ चड्डा-मड्डा-फड्डा-भड्डा-नड्डा भी दिखाई पड़ते हैं। ठंड के इस दौर में हर एक घटनाक्रम के साथ चढ़ रहे सियासी पारे के बीच हम उन रणनीतियों पर चर्चा करेंगे, जो भाजपा ने ममता और उनकी टीएमसी को घेरने के लिए तैयार की है।

भाजपा राज्य में सीएए और एनआरसी लागू करने की बात दोहराती रही है। अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें बाहर करना भी उसकी प्राथमिकता है, जबकि ममता इसे विवादास्पद कानून बताकर लागू करने से इनकार करती रही हैं। पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश की सीमा लगती है, जहां से मौका पाकर बांग्लादेश से अवैध रूप से आने वालों का सिलसिला चलता रहा है, जिसके कारण राज्य में अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ती गई और अब स्थानीय संसाधनों पर दबाव है। ये मुद्दा राज्य का ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा व कानून-व्यवस्था से भी जुड़ता है। भाजपा ने इसे प्रमुखता से उठाकर टीएमसी को घेरने की शुरुआत कर दी है।

ममता का 'अमरा' बनाम 'ओरा' (अंदरूनी बनाम बाहरी) नारा वास्तव में इन क्षेत्रों में भाजपा द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। हिंदू जागृति के बूते भाजपा 2019 के लोकसभा चुनावों में टीएमसी को अपनी ताकत दिखा चुकी है। टीएमसी को 22 और भाजपा को 18 सीटों पर जीत मिली थी। भाजपा इसे मजबूत करते हुए कई जाति समुदायों में अपनी पैठ बढ़ा रही है, जिससे वह उनके नेताओं को स्थानीय बताकर बाहरी बनाम अंदरूनी के नारे से निपट सके।

पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है, जहां देश की दूसरी सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। जनसंख्या के प्रतिशत के मामले में यह लक्षद्वीप, जम्मू-कश्मीर और असम के बाद चौथे स्थान पर है। राज्य के तीन जिलों में मुसलमान बहुमत में हैं। भाजपा ने ममता की अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की राजनीति को मुद्दा बना लिया है। इस आधार पर भाजपा ने ममता और टीएमसी को हिंदू विरोधी **तक करार** दे दिया है। इधर, टीएमसी इस मुद्दे पर मुखर होने के बजाय रक्षात्मक मुद्रा में आ रही है।

भाजपा ने 'ओर नोइ अन्याय' यानी 'और नहीं अन्याय' अभियान शुरू किया है, जो टीएमसी सरकार में भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा को उजागर करने पर आधारित है। पिछले

पश्चिम बंगाल में भाजपा के लिए नेतृत्व फैक्टर बड़ी चुनौती

पश्चिम बंगाल में भाजपा ने अभी तक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। संभावना है कि यह मामला दिल्ली हाईकमान के पास जाएगा और मोदी सरकार के साथ चलने वाले का नाम आगे किया जाएगा। मोदी का ही चेहरा आगे रखकर चुनाव लड़े जा रहे हैं, जिससे भाजपा और महाजोत दोनों की संभावनाओं को चोट पहुंच सकता है। ध्यान देने वाली बात है कि सामान्य धारणा रही है कि एक-तिहाई वोटर्स विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री उम्मीदवार के आधार पर वोट करते हैं। ऐसे में ममता के मुकाबले मुख्यमंत्री उम्मीदवार या स्पष्ट मुख्यमंत्री विकल्प सामने न होने से ममता को फायदा मिल सकता है। भाजपा और वामपंथी के पास ऐसा कोई नेता नहीं है, जिसकी ममता के समान पूरे राज्य में लोकप्रियता हो या उसे सियासी करिश्मा माना जाता हो, जैसा कि ममता ने वाम मोर्चा सरकार को उखाड़ फेंक खुद को स्थापित किया है। मोदी पर भाजपा की निर्भरता को उसकी कमजोरी के रूप में देखा जा सकता है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि 'अगर मोदी नहीं, तो कौन?'

कुछ वर्षों में देश ने देखा है कि राज्य में भाजपा और वाम दलों के सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता मारे गए हैं। कानून-व्यवस्था की लचर हालत और अराजकता की स्थिति को लेकर भाजपा कई बार देशों के सामने अपनी बात रख चुकी है। उसका दावा है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के हाथों अब तक 125 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं। राज्य के विभिन्न इलाकों में टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच छोटे-बड़े अनगिनत खूनी झगड़े हो चुके हैं। विगत दिनों ही पश्चिम बर्धमान जिले में भाजपा की रैली में कथित तौर पर कच्चे बम फेंके गए थे, जिससे कई पार्टी कार्यकर्ता घायल हुए थे।

टीएमसी ने 2011 में राज्य में सत्ता परिवर्तन के लिए जिन मुद्दों को आधार बनाया था उनमें भ्रष्टाचार भी शामिल था, लेकिन महज 10 साल के शासनकाल में खुद टीएमसी पर आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे हैं। इसे भाजपा ने मुद्दा बना लिया है और वह मनमोहन सरकार की याद दिलाकर मोदी सरकार की उजली छवि पर बात करती है। साथ ही पश्चिम बंगाल में भी परिवर्तन की अपील कर रही है। टीएमसी कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा लिया गया कथित कमीशन पूरे राज्य में विवाद के रूप में सामने आ रहा है। मध्य और निचले स्तर के टीएमसी कार्यकर्ताओं व नेताओं पर जबरन वसूली और आपराधिक सिंडिकेट चलाने के आरोप हैं। राज्य ऐसा समय भी देख चुका है जब ममता ने अल्टीमेटम जारी कर चेताया था कि ऐसी गतिविधियों में लिप्त लोग टीएमसी छोड़ दें। शारदा, नारद, चक्रवात अम्फन राहत घोटाले ने ममता और टीएमसी की छवि को धूमिल किया है। 2019 के आम चुनावों में तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के गढ़ में सेंध लगाने के बाद भाजपा अब राज्य में सत्ता परिवर्तन के इरादे से आगे बढ़ रही है। टीएमसी सरकार में परिवहन और सिंचाई मंत्री रहे सुवेंदु अधिकारी कई विधायकों के साथ भाजपा में आ चुके हैं। उनका 65 विस सीटों पर प्रभाव माना जाता है। वह पूर्वी मिदनापुर जिले के प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से हैं। पिता शिशिर अधिकारी 1982 में कांथी दक्षिण से कांग्रेस के विधायक थे, जो बाद में टीएमसी के संस्थापक सदस्य भी बने। इधर, 2019 के लोकसभा चुनावों में खाता भी न खोल सका वाम मोर्चा अब कांग्रेस के साथ संभावनाएं तलाश रहा है।

भाजपा राज्यपाल से लगातार मांग कर रही है कि ममता को बहुमत साबित करने के लिए कहें, क्योंकि हाल ही में कई नेताओं ने ममता और उनके भतीजे अभिषेक के कामकाज के तरीके की खुले तौर पर आलोचना की है। दूसरी ओर, ममता पीके यानी प्रशांत किशोर की सलाह पर सरकारी योजनाओं को घर तक पहुंचाने वाले अभियान दुआरे सरकार की शुरुआत कर रही हैं। टीएमसी की चिंता बढ़ी है, तो उसकी एक वजह 2019 लोकसभा चुनाव के परिणामों का विस सीटों के परिप्रेक्ष्य का आंकड़ा, जो बताता है कि टीएमसी 161 विधानसभा सीटों पर आगे थी, जो साधारण बहुमत से 16 अधिक है, जबकि भाजपा 123 सीटों पर आगे थी। भाजपा की कोशिशों के बावजूद ममता अभी भी बंगाल जीतने के लिए पसंदीदा दिखाई देती हैं। जून 2020 में किए गए सर्वेक्षण में टीएमसी को 159 सीटें दिखीं थी, जबकि महाजोत यानी वाम मोर्चा और कांग्रेस को 101 और भाजपा को 26 सीटें संभावित बताईं। यदि राज्य की सियासी तस्वीर पर नजर डालें तो ममता के पक्ष में कई कारक सामने आते हैं, जिसे हम दो आलेख में समझ सकते हैं।

टीएमसी ने गुजरात में भाजपा के 'गुजराती अस्मिता' के प्रभाव का परिणाम देखा है, जिसमें चुनावी जंग में स्थानीय बनाम बाहरी का राग छेड़कर भाजपा ने काफी हद तक सफलता हासिल की थी। अब पश्चिम बंगाल में वोटर्स के बीच टीमएसी बंगाली गौरव का भाव जागृत करने की कोशिश में है। राज्य में 86 प्रतिशत बंगाली और 14 प्रतिशत गैर-बंगाली हैं। यह रणनीति भाजपा की जातिगत, सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति और महाजोत की वर्गीय राजनीति को कड़ी टक्कर दे सकती है। 2019 के लोकसभा चुनावों के अंतिम चरण में भाजपा को 9 सीटों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। भाजपा की रैली के दौरान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर को लेकर विवाद के बाद टीएमसी ने बंगाली आइकन के अपमान पर उग्र अभियान शुरू किया। भाजपा के आक्रामक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की फिजां का मुकाबला करने के लिए बंगाली उप-राष्ट्रवाद और क्षेत्रीयता के संदेश आने वाले दिनों में उभरते दिखें तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। तमिलनाडु के क्षेत्रीय दल तमिल गौरव के समर्थक हैं, तो महाराष्ट्र में शिवसेना मराठी अस्मिता को सर्वोपरी रखती है। इधर, नवीन पटनायक की बीजू जनता दल ने भाजपा को रोकने के लिए ओड़िया गौरव की भूमिका बनाई।

बिहार में महागठबंधन और एनडीए के लगभग बराबर वोट शेयर हैं। दोनों को करीब 37 प्रतिशत, छोटे दलों और अन्य गठबंधन समूहों को 26 प्रतिशत वोट शेयर मिले। इस तरह विपक्षी मत विभाजन हुआ। हालांकि बिहार के विपरीत पश्चिम बंगाल में तीन तरह की तस्वीर है। 2019 के आम चुनावों में भाजपा को (+-33 प्रतिशत) लेफ्ट (-33 प्रतिशत) के पतन से फायदा हुआ। अगर वामपंथी अपने मतों के एक हिस्से को वापस जीत लेते हैं, तो भाजपा का वोट शेयर टीएमसी को फायदा पहुंचा सकता है।

● दिल्ली से रेणु आगाल

अल्पसंख्यक वोटर्स का गणित

भारत में मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी (2.47 करोड़) और आबादी में अनुपात के मामले में तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। मुस्लिम वोट 125 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत-हार तय करते हैं। ये संख्या पूरी विधानसभा की ताकत का 43 प्रतिशत ठहरती है। 2016 पर नजर डालें तो टीएमसी ने 90 सीटें जीतीं, जो 2011 से बेहतर था, जब टीएमसी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़कर 95 सीटें जीतीं थीं। राज्य में मुस्लिम प्रभावित सीटों पर कांग्रेस को समर्थन मिलता रहा है। हालांकि, बिहार से मिले सबक के बाद अब टीएमसी अल्पसंख्यक वोटों को अपनी ओर एकत्र करने की रणनीति पर आगे बढ़ेगी। 2019 में लोकसभा चुनावों में राज्य में भगवा प्रभाव के चलते इस चुनाव में मुस्लिम वोट अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगे। 2019 में भाजपा का वोट शेयर टीएमसी के करीब तक पहुंच चुका था। उस चुनाव में 70 प्रतिशत मुसलमानों ने टीएमसी का समर्थन किया था।

कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व

भाजपा खुद को गाय और राम मंदिर की राजनीति का संरक्षक मान सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भगवा ब्रिगेड को भूपेश बघेल शासन से कड़ी टक्कर मिल रही है। बघेल सरकार ने पिछले दो वर्षों में गाय, भगवान राम और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को केंद्रित कर कई योजनाएं लागू की हैं जिससे भाजपा की गाय और राम की राजनीति कमजोर हो रही है। इस बात की पुष्टि कोई और नहीं प्रदेश में संघ के प्रचारक भी करते हैं। बघेल सरकार का भाजपा को नया झटका दिल्ली में गोबर के उत्पादों का एक एम्पोरियम खोलना है। दिसंबर 2018 में सत्ता में आने के बाद भूपेश बघेल सरकार ने गौ पालकों से गोबर खरीदकर उसके उत्पादों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए योजना शुरू की। इसके साथ ही कथित तौर पर भगवान राम अपने 14 वर्षों के वनवास में राज्य के भीतर जिन क्षेत्रों से निकले उस ट्रैक को राम वन गमन पथ पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने का भी निर्णय लिया। ये योजनाएं न केवल देशभर में चर्चा का विषय बनीं बल्कि प्रदेश में भाजपा के राम और गौ संरक्षण की एकाधिकार वाली राजनीति पर भी **प्रश्नचिन्ह** लगा दिया है। भाजपा ही नहीं बल्कि संघ के पदाधिकारी भी इस बात से सहमत हैं कि राज्य में वापसी करने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यवाहक चंद्रशेखर वर्मा कहते हैं कि भूपेश बघेल सरकार की गोबर खरीदी गोधन न्याय योजना और राम वन गवन पथ पर्यटन सर्किट को विकसित करने की योजना स्वागत योग्य कदम हैं। हम लगातार गौरक्षा के लिए गाय के गोबर के उचित उपयोग को एक मजबूत साधन के रूप में वकालत करते रहे हैं। जाहिर तौर पर बघेल सरकार इसकी कीमत समझ चुकी है। हालांकि, जीएनवाई के लाभ और बड़े पैमाने पर इसके राजनीतिक परिणाम को देखा जाना बाकी है, लेकिन यह सच है कि भाजपा को अपने मूल एजेंडे को सुरक्षित रखने के लिए ठोस कदम उठाना पड़ेगा।

संघ के एक अन्य पदाधिकारी और प्रांत संघ प्रचारक विसरा राम यादव कहते हैं, 'यह स्वीकार करना होगा कि भूपेश बघेल की सरकार गौरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और राम वन गमन पथ पर्यटन सर्किट विकसित करने के लिए अच्छा काम कर रही है। भगवान राम, गाय और गाय के गोबर के उत्पादों से उसकी सुरक्षा संघ की विचार शैली का केंद्र रहा है। राम और उनका जीवन छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। भूपेश बघेल ने विकास का सही रास्ता अपनाया है। हालांकि गोधन न्याय योजना के राजनीतिक लाभ का अनुमान अभी लगाना बहुत मुश्किल है।' संघ से जुड़े गौ ग्राम स्वावलंबन अभियान के संयोजक भुवनेश्वर साहू कहते हैं, 'अच्छे कामों की सराहना की जानी चाहिए। वर्तमान में जीएनवाई के करीब 3726 केंद्र कार्यरत हैं। बघेल सरकार की योजना हर गांव में एक केंद्र खोलने की है। भाजपा को इसका सामना करने के लिए उपाय करना पड़ेगा अन्यथा अगला चुनाव बहुत संघर्षपूर्ण होगा।'

गौरतलब है कि 20 जुलाई 2020 को जीएनवाई के लॉन्च से पहले साहू के नेतृत्व में संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने बघेल से मुलाकात कर जीएनवाई पर सरकार को कंसल्टेंसी देने का प्रस्ताव रखा था लेकिन उसके बाद बात आगे नहीं बढ़ पाई। बतौर साहू, 'हमने ऑफर अपने अनुभव के आधार पर दिया था क्योंकि वर्मीकम्पोस्ट बनाने में हम किसानों की मदद पहले से करते आ रहे हैं। हमने गाय के गोबर की कीमत 1.50 से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति किलोग्राम करने का भी सुझाव दिया था लेकिन इसे आंशिक रूप में स्वीकार किया। हम इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री के साथ एक और बैठक की उम्मीद कर रहे हैं।' राजनीतिक विश्लेषक राज्य के राजनीतिक टिप्पणीकारों का कहना है कि भूपेश बघेल की राम और गाय से जुड़ी योजनाएं एक सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड जो भाजपा के लिए महंगा साबित होगा। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक उचित शर्मा कहते हैं, 'बघेल ने स्पष्ट रूप से भाजपा के साथ राजनीति की चाल को समझा है। उनके फैसले और नीतियां वास्तव में सॉफ्ट हिंदुत्व ही हैं। राम वन गमन पथ पर्यटन सर्किट, कौशल्या मंदिर और जीएनवाई के लागू होने का समय को देखें तो यह साफ तौर पर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का ही है।' शर्मा के अनुसार, 'बघेल ने छत्तीसगढ़ में राम और गाय पर भाजपा के एकाधिकार को तोड़ा है। इस बात को भाजपा नेता भी स्वीकार करते हैं कि बघेल का छत्तीसगढ़वाद और सॉफ्ट हिंदुत्व अगले विधानसभा चुनावों में उनके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं।

● रायपुर से टीपी सिंह

रोजाना 6 आत्महत्या

एक तरफ देश में कृषि बिल को लेकर किसान आंदोलन चल रहा है तो वहीं महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले साल 2020 के 11 महीनों में करीब 2270 किसानों ने महाराष्ट्र में आत्महत्या की है। यानी हर दिन लगभग 6 किसानों ने आत्महत्या की है। हैरानी की बात ये है कि इनमें से सिर्फ आधे किसान ही सरकारी मुआवजे के लायक समझे गए हैं। महाराष्ट्र में सरकार ने भले ही कर्जमाफी समेत किसानों के लिए कई योजनाएं चला रखी हों लेकिन इसके बाद भी किसान आत्महत्या के मामलों में कमी नहीं आई है।

महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार को सत्ता पर काबिज हुए एक साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इस दौरान महाराष्ट्र में 2270 किसानों ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। यह आंकड़ा साल 2020 के जनवरी महीने से लेकर नवंबर तक का है। हालांकि यह संख्या साल 2019 के आंकड़ों से कम बताई जा रही है। साल 2019 में 2566 किसानों ने आत्महत्या की थी।

आरटीआई एक्टिविस्ट जितेंद्र घाडगे की निकाली गई जानकारी पर गौर करें तो यह पता चलता है जिन 2270 किसानों ने आत्महत्या की है, उनमें से 40 प्रतिशत से ज्यादा यानी 920 किसान मुआवजे के हकदार थे। यह जानकारी महाराष्ट्र के राजस्व मंत्रालय की तरफ से आरटीआई के तहत दी गई है। सरकार कर्ज में डूबे किसानों को मुआवजा देती है। अक्सर यह मुआवजा उनके परिजनों को मिलता है जो तकरीबन एक लाख रुपए तक होता है। जानकारी के अनुसार आधे से ज्यादा किसान विदर्भ इलाके के हैं। जिसे महाराष्ट्र की कॉटन बेल्ट के रूप में भी जाना जाता है। इस इलाके से तकरीबन 1230 किसानों ने आत्महत्या की है। मराठवाड़ा के सूखे इलाके वाली जगहों पर 693 किसानों ने आत्महत्या की है। जबकि उत्तर महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 322 किसानों का है। पश्चिम महाराष्ट्र

जिसे शुगर बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है वहां आत्महत्या के 25 मामले दर्ज हुए हैं। जबकि कोंकण इलाके में आत्महत्या का एक भी मामला सामने नहीं आया है। इंडियन जर्नल ऑफ सायकाइट्री में 2017 में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, 'कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और अन्य राज्यों में प्रमाण मिले हैं कि किसानों की आत्महत्या में मानसिक विकारों से अधिक योगदान सामाजिक-आर्थिक चिंताओं का है। अध्ययनों में यह पता नहीं चला है कि आत्महत्या के पीछे मानसिक रोग है। इन अध्ययनों और अन्य आंकड़ों से पता चलता है कि सामाजिक और आर्थिक तंगहाली आत्महत्या के मूल में है। सेवाग्राम स्थित महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ने जनवरी 2005 से मार्च 2006 के बीच महाराष्ट्र के वर्धा में आत्महत्या करने वाले किसानों का अध्ययन कराया था। अध्ययन में पाया गया था कि आत्महत्या को केवल मानसिक स्वास्थ्य से जोड़कर नहीं देखा जा सकता।

एक अन्य अध्ययन फार्मर्स सुसाइड इन विदर्भ रीजन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट: ए मिथ ओर रिएलिटी के अनुसार, आत्महत्या में बहुत से कारक भूमिका निभाते हैं, जैसे, किसानों द्वारा पुराना कर्ज और वर्षों तक ब्याज अदा न कर पाने की असमर्थता, आर्थिक हालात खराब होने से पैदा होने वाले पारिवारिक विवाद, अवसाद व नशा, आत्महत्या के बाद मिलने वाले मुआवजे से परिवार को कर्ज चुकाने में मदद, कम उपज, कृषि की बढ़ती लागत और उपज की गिरती कीमतें। कृषि संकट और किसान आत्महत्या की समस्या के समाधान के लिए विस्तृत समझ की जरूरत है, केवल दिखावटी और छुटपुट प्रयास बदलाव से हालात नहीं बदलने वाले। दिल्ली और मुंबई में लगातार पहुंचने वाले किसान अपने असंतोष की चेतावनी दे रहे हैं। वे भी जीना चाहते हैं और हमें उन्हें महज के एक आंकड़े के रूप मृत्यु रजिस्टर में दर्ज होने को मजबूर नहीं करना चाहिए।

● **बिन्दु माथुर**

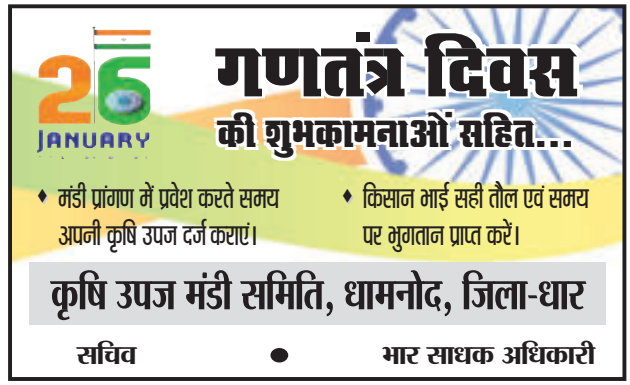

समीकरणों को तवज्जो

राजस्थान कांग्रेस की नई कार्यकारिणी की लंबे इंतजार के बाद घोषणा कर दी गई। सचिन पायलट के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद से पूरे राजस्थान में कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग थी और पार्टी की कमान गोविंद सिंह डोटासरा को सौंपी गई थी। कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी में 7 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव और 24 सचिव बनाए गए हैं। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच शक्ति संतुलन बनाने के साथ ही जातिगत संतुलन को भी ध्यान में रखा है। यही वजह है कि दोनों खेमे के लोगों को खास तवज्जो दी गई है।

बता दें कि पिछले साल जुलाई में सचिन पायलट ने अपने डेढ़ दर्जन समर्थक विधायकों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बागी रुख अपना लिया था। इसके चलते 14 जुलाई को कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने राजस्थान के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट को बर्खास्त कर दिया था और सारी कमेटी को भंग कर दिया गया था। इसके बाद प्रदेश की कमान गोविंद सिंह डोटासरा को सौंपी गई थी। गांधी परिवार के हस्ताक्षेप के बाद सचिन पायलट माने, जिसके बाद राजस्थान का सियासी संकट टला था। ऐसे में सवाल उठ रहा था कि प्रदेश संगठन में सचिन पायलट के कैंप को कितनी अहमियत दी जाएगी।

कांग्रेस की आई लिस्ट देखें तो सचिन पायलट कैंप के नजदीकियों को प्रदेश संगठन में अच्छी खासी जगह मिली है। प्रदेश के 8 महासचिव में से तीन महासिचव वेदप्रकाश सोलंकी, राकेश पारीक और जीआर खटाणा पायलट के नजदीकी माने जाते हैं। वे बगावत के दौरान सचिन पायलट के साथ हरियाणा के मानेसर में मौजूद रहे थे। इसी तरह, सचिन पायलट गुट के पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री राजेंद्र चौधरी व पूर्व शिक्षा राज्यमंत्री नसीम अख्तर को उपाध्यक्ष तथा प्रशांत सहदेव शर्मा, शोभा सोलंकी और महेंद्र सिंह खेड़ी को सचिव बनाया गया है। कांग्रेस कार्यकारिणी की घोषणा के बाद पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने ट्वीट कर सभी पदाधिकारियों को बधाई दी है। हालांकि, पायलट की टीम में कांग्रेस के विधायक विश्वेंद्र सिंह, पूर्व सांसद गोपाल सिंह ईडवा और पूर्व मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल को जगह नहीं मिल सकी है। विश्वेंद्र सिंह को गहलोत ने बगावत के चलते मंत्री पद से भी बर्खास्त कर दिया था।

प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की टीम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भले ही अपने बेटे वैभव गहलोत को जगह न दिला सके हों, लेकिन अपना दबदबा पूरी तरह से कायम रखा है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष में गोविद राम मेघवाल, हरीमोहन शर्मा, डॉ. जितेंद्र सिंह, महेंद्रजीत सिंह मालवीय और रामलाल जाट को शामिल किया गया है, जो गहलोत के करीबी माने जाते हैं। वहीं, महासचिव में हाकिम अली, लखन मीणा, मांगीलाल गरासिया और रिटा चौधरी मुख्यमंत्री खेमे के माने जाते हैं। पीसीसी में 5 महिला पदाधिकारियों को भी तवज्जो दी गई है। कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष से हटाते हुए उनकी टीम को भंग कर दिया था जिसकी भरपाई डोटासरा की नई टीम में नहीं की गई है। सचिन पायलट के साथ बगावत करने वाले चार विधायकों को भी कांग्रेस संगठन में जगह मिली है। प्रदेश कार्यकारिणी में सरकार के किसी मंत्री को शामिल नहीं किया गया है। कार्यकारिणी में मंत्रियों को जगह नहीं मिलने से संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ने के मूड में है, ताकि सत्ता और संगठन के दायित्वों को ठीक से निभाया जा सके।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में इन नियुक्तियों का लंबे समय से इंतजार था। कांग्रेस पार्टी ने पिछले साल जुलाई महीने में अशोक गहलोत सरकार के प्रति बगावत पर उतरे सचिन पायलट को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर गोविंद सिंह डोटासरा को यह जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके साथ ही राज्य की प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया था। डोटासरा की टीम का ऐलान होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, मुझे उम्मीद है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में आप सभी कांग्रेस पार्टी की नीतियों, कार्यक्रम, सिद्धांत एवं विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाने में कामयाब होंगे।

आपको बता दें कि कुछ दिन पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी और जिला स्तर की नियुक्तियों को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महासचिव अजय माकन के साथ बैठक की थी। इस बाबत डोटासरा ने कहा था कि पीसीसी पदाधिकारियों की पहली लिस्ट में अनुभवी और वरिष्ठ लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। पहले आने वाली लिस्ट में जिन लोगों को मौका मिलेगा वह वर्तमान सरकार में काम करने वाले विधायक और पूर्व की सरकारों में काम कर चुके वरिष्ठ नेता और उसके साथ ही संगठन का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ नेता होंगे। खास तौर से उपाध्यक्ष और महासचिव पदों में युवाओं के मुकाबले वरिष्ठ लोगों को तरजीह दी जाएगी, जबकि सचिव पद में युवाओं की संख्या ज्यादा रखने का प्लान तैयार किया गया है।

● जयपुर से आर.के. बिन्नानी

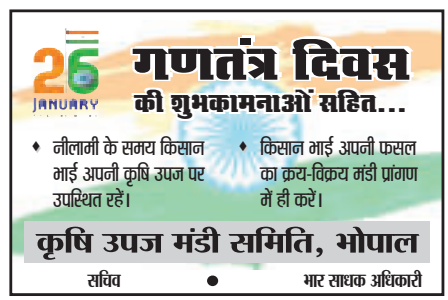

वापसी की जंग

क्या कभी सत्ता से कांग्रेस का वनवास खत्म होगा? क्या आने वाले समय में कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी? ऐसे कई सवाल हैं, जिनका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। लेकिन अब उप्र में कांग्रेस की बूथ मजबूत करने की मुहिम से लगता है कि यहां कांग्रेस का वनवास खत्म हो सकता है। कांग्रेस ने प्रदेश में 30 साल बाद ब्लॉक इकाइयों के गठन का काम शुरू कर दिया है। बड़ी बात यह है कि यहां पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने का काम कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के निर्देशन में चल रहा है। माना जा रहा है कि उनका मकसद बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़कर पार्टी को मजबूती प्रदान करना है। पिछले महीने पूरे प्रदेश में करीब 2300 से अधिक ब्लॉक इकाइयों का गठन किया जा चुका है।

प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू दिसंबर से ही प्रदेश का सिलसिलेवार दौरा कर रहे हैं। इसके लिए वह 16 जिलों की न्याय पंचायत स्तर की बैठकों में शामिल होकर ब्लॉक कांग्रेस समितियों और न्याय पंचायत समितियों के गठन में शामिल हो रहे हैं। उनका दावा है कि ब्लॉक स्तर पर 21 सदस्यों की समितियों का गठन किया जा रहा है और जल्द ही प्रदेश की सभी आठ हजार न्याय पंचायतों में पार्टी इन समितियों के गठन प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचा देगी। समितियों के गठन में तेजी लाने और अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से फिर से जोड़ने के लिए आगामी दिनों में हर जिले में 15 दिवसीय प्रवास की योजना बनाई जा रही है। इसके अंतर्गत पार्टी के पदाधिकारी अपने-अपने जिलों में संगठन की निर्माण प्रकिया को मजबूती देने के लिए अंतिम रूप देंगे। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी का लक्ष्य प्रदेश की सभी 60 हजार ग्राम सभाओं पर ग्राम कांग्रेस समितियों का **जल्द से जल्द गठन** पूरा करना है। हालांकि जानकारों का कहना है कि कांग्रेस ने ब्लॉक स्तर पर इकाइयों का गठन भाजपा की तर्ज पर करना शुरू किया है, लेकिन कांग्रेस के समर्थकों का कहना है कि भाजपा जब देश में कहीं नहीं थी, तबसे ही कांग्रेस बूथ मजबूत करने के लिए ब्लॉक और ग्राम स्तर पर कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ती रही है। बहरहाल जो भी हो, कांग्रेस के लोग इस मुहिम को पार्टी की डूबी हुई नैया को फिर से पार लगाने की पहल मान रहे हैं और इसे कांग्रेस की मौन क्रांति बता रहे हैं।

प्रदेश पार्टी इकाई का कहना है कि भाजपा की नीतियों और निरंकुश शासन से तंग लोग इस मुहिम से बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पार्टी में सलाहकार के रूप में उपेक्षित बुजुर्ग नेताओं को शामिल किया जा रहा है, ताकि उनके अनुभवों को भुनाया जा सके। राजनीति के जानकार कहते हैं कि जब तक कांग्रेस में

अंदरखाने जिस तरह कलह चल रहा है, अगर उसे खत्म नहीं किया गया, तो ब्लॉक इकाइयों के गठन का उतना फायदा नहीं मिलेगा, जितना कि मिलना चाहिए। इसके अलावा पार्टी को गांवों के साथ-साथ शहरों में भी खुद को मजबूत करना चाहिए। कुछ जानकारों का कहना है कि कांग्रेस को मीडिया में लगातार बने रहना चाहिए और सरकार को ऐसी नीतियों पर घेरे रहना चाहिए, जो देशहित में नहीं हैं।

बता दें कि आजादी के बाद से अब तक उप्र में 47 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिनमें कांग्रेस प्रदेश में 21 बार सरकार बना चुकी है। लेकिन प्रदेश में सन् 1989 से कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकी है। अब लोगों का कहना है कि केंद्र में कांग्रेस की वापसी का रास्ता उप्र से ही खुलेगा। अगर यह बात सही साबित होती है और 2022 में होने वाले उप्र विधानसभा चुनावों में कांग्रेस प्रदेश की सत्ता में वापसी होती है, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बने या न बने, लेकिन यह तय है कि उसे बड़ा बहुमत जरूर मिलेगा। इसकी उम्मीद इसलिए भी है, क्योंकि देशभर में भाजपा का विरोध बढ़ता जा रहा है। इन दिनों चल रहे किसान आंदोलन ने इस विरोध को और भी धार देनी शुरू कर दी है। कांग्रेस के समर्थक राजनीति के जानकारों का मानना है कि अगर प्रियंका गांधी के हाथ में उप्र की कमान रही, तो उप्र में कांग्रेस की सरकार बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को बिहार में अपनी ढीली गतिविधियों से करारी हार मिली है, इससे उसे सीख लेनी चाहिए और उप्र में इस तरह की लापरवाही से बचना चाहिए।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

उलटफेर के लिए बेकरार!

बिहार में नीतीश सरकार को बने डेढ़ महीना भी नहीं हुआ कि भाजपा-जेडीयू के बीच तल्खी इस कदर बढ़ गई है कि अब राज्य में सत्ता के परिवर्तित होने की अटकलें भी बढ़ती जा रही हैं। इसका कारण है कि न तो भाजपा को नीतीश कुमार पसंद आ रहे हैं न ही नीतीश को भाजपा पसंद आ रही है, यानी दोनों ओर से 'सियासी मोलभाव' शुरू हो चुका है। इस बीच बिहार में जेडीयू की धुर विरोधी राष्ट्रीय जनता दल भी अब नए समीकरण साधने में जुट गई है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पसंद आने लगे हैं। जबकि पिछले महीने हुए राज्य विधानसभा चुनाव में दोनों ने एक-दूसरे पर इतनी जबरदस्त सियासी हमले किए थे कि राजनीति की सारी मर्यादा ताक पर रख दी थी। लेकिन अब दोनों में नजदीकियां बढ़ती नजर आ रही हैं। अब आपको बताते हैं जेडीयू और भाजपा में दरार पड़नी कहां से शुरू हुई।

भाजपा और जेडीयू के बीच बढ़ती दरार की वजह से अभी तक बिहार में दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो सका है। इस देरी का ठीकरा नीतीश भाजपा पर फोड़ चुके हैं। दूसरी तरफ राज्य में बड़ी पार्टी होने के नाते भाजपा की मांग बढ़ती जा रही है। वह पहले ही विधान परिषद के सभापति का पद और विधानसभा अध्यक्ष का पद ले चुकी है। अब भाजपा के एक नेता ने गृह विभाग छोड़ने की मांग नीतीश कुमार से कर दी है। उसके बाद पिछले दिनों अरुणाचल प्रदेश में भाजपा ने जदयू के 6 विधायकों को अपने पाले में कर लिया। इस पर जदयू ने बदले की कार्रवाई करते हुए यह फैसला ले लिया कि वह अन्य राज्यों में अपने **बलबूते** चुनाव लड़ेगी। इसी बीच पहले उप्र में योगी और बाद में मप्र में भाजपा शासित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लव जिहाद पर कानून बनाकर जेडीयू को और भड़का दिया। भाजपा के इस नए 'लव जिहाद' कानून पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता केसी त्यागी और जेडीयू के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी आरसीपी सिंह ने कड़ी आपत्ति जताई है। इसके अलावा जेडीयू को अब लगने लगा है कि भाजपा इस कानून को लेकर बिहार सरकार पर दबाव की राजनीति बना रही है।

गौरतलब है कि बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से भाजपा 74 और जदयू 43 जीती है। दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल ने सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, उसने 75 सीटों पर विजय प्राप्त की है। इसके अलावा कांग्रेस को 19 सीटों पर सफलता मिली। यह सब जानते हैं कि इस बार बिहार के चुनाव में भाजपा मजबूत और जदयू कमजोर हुई है। इसके बावजूद भाजपा ने चुनाव पूर्व किए गए वादे के मुताबिक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद तो दे दिया लेकिन अब उसे अखरने लगा है।

वर्ष 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू ने मिलकर सरकार बनाई थी। इसमें नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली थी वहीं तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री बने थे। लेकिन उस समय परिस्थितियां जेडीयू के पक्ष में थी, इसलिए एक साल के अंदर ही आरजेडी से मतभेद बढ़ने पर जेडीयू अलग हो गई। उसके बाद भाजपा ने जेडीयू को समर्थन देकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया और भाजपा के सुशील मोदी उपमुख्यमंत्री बने थे। उस समय बिहार में भाजपा नीतीश को बड़ा भाई मानकर चल रही थी, लेकिन इस बार सीटों के समीकरण को देखते हुए भाजपा का पलड़ा भारी है। आज भले ही नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं लेकिन सत्ता भाजपा के इर्द-गिर्द ही घूम रही है।

● विनोद बक्सरी

भोपाल विकास प्राधिकरण

आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्ति क्रय करने का सुनहरा अवसर

ऑफर खुलने का दिनांक 30 जनवरी 2021 4 बजे

आवेदन प्राप्ति दि. 15 जनवरी से 29 जनवरी 2021 तक

विज्ञापन क्रमांक 1736/राजस्व/भोविप्रा/21 — भोपाल, दिनांक 13/01/21

व्यावसायिक संपत्ति

ऑफर के माध्यम से विक्रय की जाने वाली सम्पत्तियां

अधिकतम ऑफर मूल्य ही स्वीकार किये जायेंगे

केवल ऑफ लाईन

योजना का नाम	प्रकोष्ठ/दुकान/भवन	रिक्त सम्पत्तियों की संख्या	कारपेट क्षेत्रफल वर्गमीटर/वर्गफिट में	कोने अनारक्षित	[illegible]	रजिस्ट्रेशन राशि (ऑफसेट राशि) रुपये	वार्षिक भू भाटक
कटारा हिल्स सेक्टर-ए एवं	दुकानें	27	9.45 वर्गमीटर 101.68 वर्गफिट से प्रारंभ	अनारक्षित	8,57,834/- से प्रारंभ	85,710/-	1543/-
सेक्टर-सी	दुकान क्र. 1,3,5,11	04	18.92 वर्गमीटर 203.57 वर्गफिट से प्रारंभ	अनारक्षित	12,73,446/- से प्रारंभ	1,27,344/-	2292/-
आई.एस.बी.टी. योजना (प्लेटफार्म)	दुकान क्रमांक 27	01	8.47 वर्गमीटर 91.13 वर्गफिट	अनारक्षित	22,09,201/- से प्रारंभ	2,20,920/-	1370/-
गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर परिसर साकेत नगर, भोपाल	रिक्त दुकान संख्या 3	28	263.94 वर्गफिट	अनारक्षित	37,20,000/-	3,16,200/-	545/-
		29	263.94 वर्गफिट	अनारक्षित	37,20,000/-	3,16,200/-	545/-
		33	200.99 वर्गफिट	अनारक्षित	28,33,000/-	2,40,805/-	415/-
अन्नपूर्णा काम्पलेक्स	दुकान क्रमांक 23	01	26.99 वर्गमीटर 290.41 वर्गफिट	अनारक्षित	26,31,329/-	2,63,153/-	545/-
पंचशील नगर योजना	दु.क्र. 3,5,7,9, एवं 10	05	148.00 वर्गफिट से प्रारंभ	अनारक्षित	10,75,250/- से प्रारंभ	107,525/-	210/-
महर्षि पतंजलि कोहेफिजा	दुकानें	35	98.13 वर्गफिट 9.12 वर्गमीटर	अनारक्षित	4,78,800/- से प्रारंभ	47,880/-	1119/-
पंडित भीमसेन जोशी परिसर साकेत नगर	दुकान क्रमांक 05, 10, 12	03	282.66 वर्गफिट	अनारक्षित	22,07,000/-	2,20,700/-	583/-
			336.57 वर्गफिट	अनारक्षित	26,28,000/-	2,62,800/-	693/-
			220.90 वर्गफिट	अनारक्षित	17,25,000/-	1,72,500/-	455/-
माता मंदिर योजना	दुकानें	07	5.61 वर्गमीटर 60.36 वर्गफिट	अनारक्षित	7,37,298/- से प्रारंभ	73,756/-	1057/-
आमेर काम्पलेक्स (नाले के ऊपर) एम.पी.नगर जोन 2	दुकान क्रमांक 15 व्यावसायिक	01	102.97 वर्गफिट 9.56 वर्गमीटर	अनारक्षित	18,08,730/-	1,80,873/-	212/-
बस स्टैंड नं.-7	दुकान क्रमांक 316	01	9.30 वर्गमीटर 100.6 वर्गफिट	अनारक्षित	11,00,000/-	1,10,000/-	1095/-

आवासीय सम्पत्ति

योजना का नाम	प्रकोष्ठ/दुकान/भवन	रिक्त सम्पत्तियों की संख्या	कारपेट क्षेत्रफल वर्गमीटर/वर्गफिट में	कोने अनारक्षित	[illegible]	रजिस्ट्रेशन राशि (ऑफसेट राशि) रुपये	वार्षिक भू भाटक
अन्नपूर्णा काम्पलेक्स	आवासीय प्रकोष्ठ क्र. ई. 109	01	110.61 वर्गमीटर 1185.32 वर्गफिट	अनारक्षित	38,66,788/-	3,86,680/-	505/-
माता मंदिर	आवासीय प्रकोष्ठ क्र. एम 26	01	75.00 वर्गमीटर 807.00 वर्गफिट	अनारक्षित	24,02,250/-	2,40,250/-	2430/-
सोनिया गांधी	आवासीय प्रकोष्ठ LIG बी 2/5	01	23.16 वर्गमीटर 249.41 वर्गफिट	अनारक्षित	7,66,278/-	76,628/-	349/-
गीतांजली काम्पलेक्स	आवासीय प्रकोष्ठ LIG बेसमेंट ब्लॉक 9	01	71.68 वर्गमीटर 771.27 वर्गफिट	अनारक्षित	22,28,025/-	2,28,805/-	113/-
विद्या नगर	MIG प्रकोष्ठ 9/13, चतुर्थ तल	01	86.71 वर्गमीटर 932.99 वर्गफिट	अनारक्षित	27,00,148/-	2,70,015/-	378/-
एम.डी. रुसिया नगर, पीपलनेर	एचआईजी थ्री-टाइप डुप्लेक्स क्र. 145,146,147 एवं 150	04	94.48 वर्गमीटर 1016.60 वर्गफिट	अनारक्षित	37,70,300/-	3,77,000/-	16855/-
अजंता काम्पलेक्स	परिवर्तित MIG प्रकोष्ठ 5/1	01	46.46 वर्गमीटर 499.90 वर्गफिट	अनारक्षित	10,92,844/-	1,09,284/-	179/-
	परिवर्तित LIG प्रकोष्ठ 3/66	01	23.51 वर्गमीटर 252.96 वर्गफिट	अनारक्षित	5,19,728/-	51,972/-	89/-
अमरावद खुर्द बिना ऑफर के	LIG डुप्लेक्स 1 से 3, 6 से 12, 20, 23 से 26 तक 31, 35, 38, 40, 41 एवं 42	22	40.50 वर्गमीटर 435.78 वर्गफिट	अनारक्षित	13,43,000/-	1,34,300/-	70/-
महर्षि पतंजली परिसर योजना (निश्चित मूल्य पर)	2 बी.एच.के. प्रकोष्ठ चतुर्थ तल	22	41.75 वर्गमीटर 449.23 वर्गफिट	अनारक्षित	10,00,000/-	1,00,000/-	197/-
विज्ञापन क्रमांक 1768/राजस्व/भोविप्रा/21 — भोपाल, दिनांक 13/01/21							
कटारा हिल्स प्रकोष्ठ	एम.आई.जी. एवं जूनियर एम.आई.जी	46	56.43 वर्गमीटर 607.18 वर्गफिट	अनारक्षित	15,76,000/- से प्रारंभ	1,57,600/-	3643/-
विज्ञापन क्रमांक 1736/राजस्व/भोविप्रा/21 — भोपाल, दिनांक 13/01/21							
शहीद भगत सिंह नगर कोहेफिजा	2 बी.एच.के. प्रकोष्ठ	74 द्वितीय तल-22 तृतीय तल-52	41.75 वर्गमीटर 449.23 वर्गफिट	अनारक्षित	10,97,000/- 10,90,000/-	1,09,700/- 1,09,00/-	198/- 198/-

नोट - 1. निविदा प्रपत्र की शर्तें आवेदन पत्र के साथ संलग्न रहेंगी।
2. दुकान का आवंटन यथा स्थिति में किया जायेगा।
3. [illegible]
आवेदन पत्र मुख्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण से कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकते है।

नोट- 1. कटारा हिल्स प्रकोष्ठों का चयन लॉटरी पद्धति द्वारा। 2. शहीद भगत सिंह नगर कोहेफिजा/कटारा हिल्स के प्रकोष्ठ/अमरावद खुर्द योजना के एल.आई.जी. डुप्लेक्स बिना ऑफर के विक्रय किये जायेंगे।

संपदा अधिकारी
भोपाल विकास प्राधिकरण
भोपाल

ऑफर फार्म का मूल्य 500/-

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें-
प्रगति भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल 462011 (म.प्र.)
दूरभाष : 0755-2701836/37/38, 2557273 / 2557276 website : www.bda.org.in, Email : info@bda.org.in

पाक में अस्थिरता

अपनी स्थापना के 8 दशक पूर्ण करने की ओर अग्रसर पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकारों का गठन और असमय पतन नियति-सी बन गई है और इसी कारण यह दक्षिण एशियाई देश राजनीतिक स्थिरता से कोसों दूर नजर आता है। इस समय विपक्षी पार्टियां इमरान खान सरकार के खिलाफ लामबंद होकर देशभर में रैलियां कर रही हैं। इन पार्टियों ने सत्ताधारी इमरान खान की सरकार से किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया है। विपक्षी पार्टियों के नेता सेना और आईएसआई को लेकर बेहद मुखर होकर विरोध कर रहे हैं। दरअसल, देश की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है। सेना बलूचिस्तान सहित कई इलाकों में आम जनता, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बना रही है।

इमरान खान कूटनीतिक मोर्चे पर भी लगातार नाकाम रहे हैं। पाकिस्तान की इस्लामिक देशों के नेतृत्व की कूटनीति बेदम होने लगी है। तुर्की और ईरान के साथ लामबंद होकर उसने अपने परंपरागत मित्र सऊदी अरब को नाराज कर दिया

है। इसलिए सऊदी अरब पाकिस्तान से अपना अरबों का बकाया कर्ज मांग रहा है। संयुक्त अरब अमीरात ने भी पाकिस्तान के लोगों को कामकाजी वीजा देना बंद कर दिया है। इन देशों में पाकिस्तान के लाखों नागरिक काम करते हैं और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहतर रखने में इसका बड़ा योगदान रहता है। इसके मुकाबले इन देशों से भारत के संबंध बेहद मजबूत हुए हैं। पिछले दिनों भारत के सेना प्रमुख ने सऊदी अरब और अमीरात का दौरा भी किया था। इसे पाकिस्तान की नाकामी माना जा रहा है और इसे लेकर विपक्षी दल इमरान खान सरकार पर हमलावर हैं।

दरअसल, न्यायालय के फैसले को आधार बनाकर देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल मुस्लिम लीग (नवाज) के नेता नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया गया। चुनाव परिणाम के पहले ही इमरान खान को मीडिया ने जीत का सेहरा बांध दिया। सेना, आतंकियों, आईएसआई और धार्मिक समूहों ने उनका भरपूर समर्थन किया और इमरान खान को लोकतांत्रिक ढंग से चुने जाने की हर संभव परिस्थितियां उपलब्ध कराई गईं। चुनाव आयोग ने सेना के इशारे पर अभूतपूर्व कदम उठाते हुए पहली बार मतदान केंद्रों के अंदर सेना तैनात करने का फैसला किया, जबकि इसके पहले सुरक्षाकर्मियों को सिर्फ अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों के बाहर ही तैनात किया जाता था। आम चुनाव के दौरान तीन लाख इकहत्तर हजार से अधिक जवानों को तैनात किया गया था, जो इसके पहले 2013 में हुए आम चुनाव से तीन गुना से अधिक थे।

72वें गणतंत्र दिवस
की शुभकामनाओं सहित...
अपील
- सही तौल एवं समय पर भुगतान प्राप्त करें।
- किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
- नीलामी के समय किसान भाई अपनी कृषि उपज पर उपस्थित रहें।
- मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय अपनी कृषि उपज आवश्यक रूप से दर्ज कराएं।
26 JANUARY
REPUBLIC DAY OF INDIA
कृषि उपज मंडी समिति, देवास
सचिव • भार साधक अधिकारी

72वें
गणतंत्र दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएं
अपील
- सही तौल एवं समय पर भुगतान प्राप्त करें।
- किसान अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
- नीलामी के समय किसान भाई अपनी कृषि उपज पर उपस्थित रहें।
26 January
कृषि उपज मंडी समिति, उज्जैन
सचिव • भार साधक अधिकारी

अमेरिका शर्मसार

दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश अमेरिका अपने सबसे खराब समय में जा पहुंचा है। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही अमेरिका में वर्तमान राष्ट्रपति और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के समर्थक आपस में उलझे पड़े हैं। वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के कुछ दिन ही रह गए हैं लेकिन वह नतीजे आने के दो महीने बाद भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं हैं। राष्ट्रपति चुनाव के दो महीने के बाद वाशिंगटन डीसी स्थित कैपिटल हिल में इलेक्टोरल कॉलेज की गिनती की प्रक्रिया चल रही थी, इसी गिनती के बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति की जीत पर मुहर लगनी थी। पूरी प्रक्रिया चल ही रही थी कि हजारों की संख्या में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने एक रैली निकाल दंगाईयों की भांति कैपिटल हिल के अंदर धावा बोल दिया। कैपिटल हिल की सुरक्षा एजेंसियां इतनी बड़ी भीड़ को रोकने में नाकाम साबित हुई और कुछ ट्रंप समर्थक चेयर की कुर्सी तक जा बैठे। माइक में तोड़फोड़ की और तमाम तरह के उपद्रव मचाए। यहां पर ये जानना जरूरी हो जाता है कि संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा था कि चुनाव में धांधली हुई है, और धांधली वाले चुनाव का नतीजा स्वीकार नहीं करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के इसी भाषण के बाद से ही वाशिंगटन डीसी का माहौल खराब हो गया जो बाद में हिंसा के रूप में बदल गया। जो बाइडन समेत सभी बड़े नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप को ही इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया है।

डोनाल्ड ट्रंप कितने अकेले हैं ये बात आप कुछ यूं समझ लीजिए कि उनके अपने ही साथी और ट्रंप सरकार में उपराष्ट्रपति माइक पेंस भी इस घटना को कलंक करार देते हैं। सियासी खींचतान के बीच अमेरिका में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है, डीसी में अभी इमरजेंसी लगी रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कई राज्यों में केस दर्ज किया था जिसमें अधिकतर जगह उनकी याचिका खारिज ही हो गई है जिससे डोनाल्ड ट्रंप आगबबूला हो बैठे हैं।

डोनाल्ड ट्रंप हिंसा होने के बावजूद टस से मस नहीं हुए और चुनावी नतीजे को खारिज करते हुए चुनाव में धांधली के आरोप लगाए, उन्होंने ट्वीट भी किया और फेसबुक पर भी पोस्ट किया। इन दोनों ही कंपनियों ने डोनाल्ड ट्रंप के इस पोस्ट को डिलीट करते हुए ट्रंप का अकाउंट ही ब्लाक कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को किसी का भी साथ मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। अमेरिका के घटनाक्रम पर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की ही किरकिरी हो रही है।

दुनियाभर के तमाम बड़े नेता इस पूरे घटना की निंदा कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गैरकानूनी विरोध-प्रदर्शन के माध्यम से प्रभावित नहीं होने दिया जा सकता है। इसके साथ ही ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा सहित अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी इस पूरी घटना की निंदा की है। अमेरिका के धुर विरोधी चीन ने इस पूरी घटना का मजाक उड़ाया है और अमेरिका के लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को 20 जनवरी तक व्हाइट हाउस को खाली कर देना है। 20 जनवरी 2021 को ही नए राष्ट्रपति जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ भी लेंगे। अब अगर तब तक वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस खाली नहीं किया तो एक अलग ही तरह का संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा और अमेरिका पर एक और काला धब्बा लग जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप कब और कैसे अपनी हार मानेंगे इसका पता तो खुद डोनाल्ड ट्रंप को ही नहीं है क्योंकि कभी तो वह नतीजे को अपना लेते हैं तो कभी इसको खारिज कर देते हैं।

● कुमार विनोद

PRISM®
CEMENT

प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.

Toll free: 1800-3000-1444
Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

दूर की सोच®

फूलों की बात

साधना के कमरे से शास्त्रीय संगीत की स्वर लहरियां वातावरण को आनन्दमय बना रही थीं। मैं उसमें डूबकर मानों किसी अन्य ही लोक में विचरण कर रही थी। अचानक आवाज बंद हो गई, इस व्यवधान ने मेरी तंद्रा भंग कर दी। साधना बहुत उदास लग रही थी, मुझे देखते ही बोल पड़ी, इस लाकडाउन ने सारी जिंदगी अस्त-व्यस्त कर दी है। बच्चे शास्त्रीय संगीत सीखने और कुछ गहन अध्ययन करने हेतु अभ्यास करने आते थे। सारा दिन घर में संगीतमय वातावरण रहता था अब मैं एक घंटा अभ्यास करने के बाद बंद कर देती हूं। वैसे भी संगीत साधकों और कलाकारों के लिए बहुत कठिन समय है। बच्चे आगे सीख नहीं पाते और कलाकारों को इस मंहगाई के जमाने में परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है उनको कहीं से पारिश्रमिक भी नहीं मिलता। साधना ने व्यथित होकर कहा।

इस बगिया के फूल हर रोज दिनभर शास्त्रीय संगीत सुनते हैं यही उनकी खाद है और इसी लिए यह मुस्कुराते हैं। यह तो संगीत का प्रभाव है।

साधना की उदासी और अवसाद बढ़ता जा

रहा था। उसका ध्यान बंटवाने के लिए मैंने कहा- साधना, क्या तुम भूल गई, उस दिन तुम्हारे फूलों को देखकर विनोदजी ने कहा था 'साधना तुम अपने फूलों को कौन-सी खाद देती हो जो यह इतने खूबसूरत और मुस्कुराते हुए लग रहे हैं, प्रभा भी तो नर्सरी से तुम्हारे साथ ही तो एक जैसे पौधे लाए थे। उसके फूल तो ऐसे मुस्कुराते हुए नहीं हैं।' जी, मेरी टैरेस और इस बगिया के फूल हर रोज दिनभर शास्त्रीय संगीत सुनते हैं यही उनकी खाद है और इसी लिए यह मुस्कुराते हैं। यह तो संगीत का प्रभाव है। यह सुनते ही साधना मुस्कुराते हुए अपनी बगिया में चली गई उसकी उदासी और अवसाद फूलों की खुशनुमा महक में धुल चुका था।

- डॉ. मनोरमा शर्मा

दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की हाल ही में जारी टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा है। पिछले दिनों भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को आईसीसी द्वारा दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर भी चुना गया। उन्हें दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार से नवाजा गया है। दशक के सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर की दौड़ में विराट कोहली के अलावा श्रीलंका के लसिथ मलिंगा और कुमार संगाकारा, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क, दक्षिण अफ्रीका के एबी डीविलियर्स, रोहित शर्मा तथा

महेंद्र सिंह धोनी शामिल थे। दशक के आईसीसी पुरस्कारों में पिछले 10 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों को चुना गया, जिसमें पहली बार प्रशंसकों को भी मत देने का अधिकार दिया गया था और दुनियाभर से 15 लाख से भी अधिक प्रशंसकों ने 53 लाख मत डाले। विराट कोहली चार पुरस्कारों की दौड़ में शामिल थे, जिनमें आईसीसी का दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के अलावा दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट, वनडे और टी-20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर शामिल थे। विराट कोहली को जहां दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के अलावा दशक का सर्वश्रेष्ठ वन-डे पुरुष क्रिकेटर भी चुना गया, वहीं ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट और अफगानी स्पिनर राशिद खान को सर्वश्रेष्ठ टी-20 खिलाड़ी चुना गया। आईसीसी द्वारा दशक की टेस्ट, वनडे और टी-20 की जिन टीमों का चयन किया गया, स्टार बल्लेबाज कोहली इन तीनों ही फॉर्मेट में शामिल होने वाले भी एकमात्र क्रिकेटर रहे। विराट कोहली को दशक की टेस्ट टीम का कप्तान भी बनाया गया।

पिछले 10 वर्षों में विराट कोहली ने 20 हजार से भी ज्यादा रन बनाए हैं और इस दौरान 66 अंतर्राष्ट्रीय शतक तथा 94 अर्धशतक भी जड़े हैं। 70 से अधिक पारी खेलते हुए उनका सर्वाधिक औसत 56.97 का रिकॉर्ड भी रहा। वन-डे में उन्होंने एक दशक में 39 शतक और 48 अर्धशतक जड़े तथा 112 कैच लपके। 10 वर्षों की अवधि में उन्होंने टेस्ट, टी-20 तथा वनडे में 56.97 के औसत से कुल 20,396 रन बनाए और इस दशक में वनडे में 10 हजार से ज्यादा रन बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी भी बने, जो उन्होंने 61.83 के औसत से बनाए। वनडे मैचों में कोहली ने 12,040 रन, टेस्ट क्रिकेट में 7,318 रन और टी-20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में इन 10 वर्षों में 2,928 रन बनाए और सभी प्रारूपों में मिलाकर उनका औसत 50 से अधिक का रहा।

विराट ने अपने कैरियर का पहला रन धोनी की कप्तानी में बनाया और अपना 10 हजारवां रन भी उन्होंने धोनी की मौजूदगी में ही बनाया था। जब विराट के कैरियर की शुरुआत हुई थी, उस समय क्रिकेट में धोनी और सहवाग की तूती बोलती थी लेकिन विराट ने कुछ ही समय में अपने प्रदर्शन से हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया किंतु तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन यही विराट अपने नाम के ही अनुरूप क्रिकेट में विराट कीर्तिमान स्थापित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का इतना बड़ा सितारा बन जाएगा और रिकॉर्डों के मामले में क्रिकेट के भगवान माने जाते रहे सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ देगा। अंडर-19 क्रिकेट टीम हो या सीनियर टीम, विराट ने हर जगह अपने बल्ले से ऐसे जलवे दिखाए हैं कि खेलप्रेमी उनके दीवाने हो गए। कहना गलत नहीं होगा कि अपने जोश, जुनून, तेज गति से रन बनाने की भूख और कड़ी मेहनत के बलबूते पर विराट आज जिस पायदान पर खड़े हैं, वहां विराट ने तमाम भारतीय खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है।

● आशीष नेमा

26 JANUARY
गणतंत्र दिवस
की शुभकामनाओं सहित...
• नीलामी के समय किसान भाई अपनी कृषि उपज पर उपस्थित रहें।
• किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
कृषि उपज मंडी समिति, पिपल्या, जिला-मंदसौर
सचिव • भार साधक अधिकारी

26 JANUARY
गणतंत्र दिवस
की शुभकामनाओं सहित...
• नीलामी के समय किसान भाई अपनी कृषि उपज पर उपस्थित रहें।
• किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
कृषि उपज मंडी समिति, दलौदा, जिला-मंदसौर
सचिव • भार साधक अधिकारी

गणतंत्र दिवस
की शुभकामनाओं सहित...
• नीलामी के समय किसान भाई अपनी कृषि उपज पर उपस्थित रहें।
• किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
कृषि उपज मंडी समिति, मंदसौर
सचिव • भार साधक अधिकारी

गणतंत्र दिवस
की शुभकामनाओं सहित...
• मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय अपनी कृषि उपज दर्ज कराएं।
• किसान भाई सही तौल एवं समय पर भुगतान प्राप्त करें।
कृषि उपज मंडी समिति, बड़नगर, जिला-उज्जैन
सचिव • भार साधक अधिकारी

26 JANUARY
गणतंत्र दिवस
की शुभकामनाओं सहित...
• नीलामी के समय किसान भाई अपनी कृषि उपज पर उपस्थित रहें।
• किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
कृषि उपज मंडी समिति, महिदपुर, जिला-उज्जैन
सचिव • भार साधक अधिकारी

राम के रोल के लिए रिजेक्ट कर दिए गए थे अरुण गोविल

90 के दशक में जब रामानंद सागर की रामायण शुरू हुई थी तो इसमें विभिन्न भगवानों का किरदार निभाने वाले कलाकार घर-घर में प्रसिद्ध हो गए थे। अरुण गोविल भी ऐसे ही कलाकारों में से एक हैं। अरुण गोविल ने रामानंद सागर की रामायण में राम का किरदार निभाया है। आज भी जब हम कहीं भगवान राम का नाम लेते हैं तो एक बार अरुण गोविल की तस्वीर जरूर में दिमाग में आ जाती है और इसका सीधा सा कारण छोटे पर्दे पर प्रसारित होने वाली रामायण है। पुरानी पीढ़ी के लोग तो इन्हें टीवी पर देखते ही हाथ जोड़ने लगते थे और सार्वजनिक जगह पर देखते ही पैर छूने लगते थे। वैसे, अरुण पहले राम के किरदार के लिए रिजेक्ट कर दिए थे। वजह थी कि रामानंद सागर को उनकी स्मोकिंग की लत बिलकुल पसंद नहीं आई थी। उनका मानना था कि ऐसी बुरी आदतों वाले व्यक्ति को वह राम कैसे बना सकते हैं लेकिन अरुण ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह इस आदत को छोड़ देंगे। तब भी बात नहीं बनी तो अरुण ने लुक टेस्ट में अपनी मुस्कान का इस्तेमाल किया जो कि काम कर गई और रामानंद सागर उन्हें राम के रोल में साइन करने के लिए मजबूर हो गए।

शादी के बाद बच्चे नहीं चाहती थीं अभिनेत्री आएशा जुल्का

अभिनेत्री आएशा जुल्का ने खिलाड़ी, जो जीता वही सिकंदर, हिम्मतवाला, वक्त हमारा है और चाची 420 जैसी फिल्मों में काम किया और काफी लोकप्रियता हासिल की। वह 2010 में आई फिल्म अदा...ए वे ऑफ लाइफ में दिखीं और उसके बाद लंबे समय तक फिल्मों से दूरी बना ली। आएशा को आखिरी बार फिल्म जीनियस में देखा गया था जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। अब एक इंटरव्यू में आएशा ने अपने फिल्मी कैरियर और शादी कर बॉलीवुड से दूरी बनाने जैसे फैसलों पर खुलकर बात की है।

शादी के बाद बच्चे ना होने के सवाल पर आएशा बोलीं, मेरे बच्चे नहीं हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती थी। मैं अपना समय और एनर्जी कई कामों और सोशल कॉज में लगाती हूं। मुझे खुशी है कि मेरे फैसले से मेरा पूरा परिवार सहमत रहा। मेरे पति समीर ने भी मुझ पर कभी किसी चीज का दबाव नहीं बनाया। इसके अलावा आएशा ने बताया कि बॉलीवुड छोड़ने के बाद वह जैकी श्रॉफ से टच में हैं क्योंकि वो भी उनकी तरह कई सोशल कॉज से जुड़े हुए हैं।

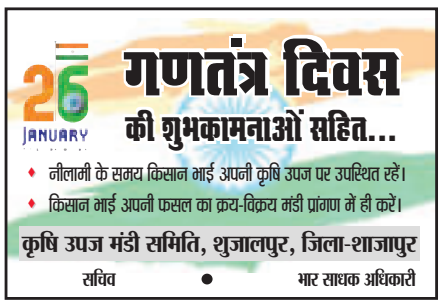

क्या हो रा' है का खटराग!

क्या हो रा' है, यह प्राय: 'पूर्ण प्रश्नवाचक' नहीं होता, इस व्यंग्य में भी इसीलिए व्यंग्यकार ने कहीं भी इस वाक्य के संग प्रश्नचिन्ह प्रयुक्त नहीं किया। बात दरअसल यह है कि क्या हो रा' है बोलने वाला प्राय:, जो हो रहा होता है, उसे स्वयं भी देख-समझ रहा होता ही है, परंतु जब तक उस होते हुए पर दो-चार से झक ना मार ले, संतुष्टि कहां! यह क्या हो रा' है, कई बार बड़े अटपटे रूप से बैमौके ही 'जपतु' के श्रीमुख से निकल जाता है- एक कवि मित्र के पिताजी के देहांत का समाचार मिला। हम मित्र लोग जब उसके घर पहुंचे, तो अर्थी उठाने की तैयारी चल रही थी। वह मित्र भी अर्थी के पास ही खड़ा था कि तभी उसके एक रिश्तेदार आए और वही क्या हो रा' है दाग दिया। मन हुआ कहा जाए, जो हो रहा था, वह तो पूर्ण हुआ, अब तेरी तैयारी है, फिर लगा, जो भीतर कहीं, कब का मर चुका हो, वो किसी की मृत्यु से उपजी संवेदना भला कहां समझेगा! फोन पर क्या हो रा' है, यह संभवत: सबसे अधिक बोले-सुने जाने वाला खोखला वाक्य है! घोर स्वार्थी लोग इस वाक्य से बात शुरू करते हैं, जिसका अंत मतलब की बात से होता है। हमारे क्या हो रा' है से अधिक उसे अपना क्या हो रहा है, बताने की हुड़क होती है, वह हुड़क निकले, तो फिर उसे ध्यान आता है कि यार कॉल लम्बी हो गई और फिर अच्छा फिर करते हैं बात कहकर कॉल काट दी जाती है। बस क्या हो रा' है, इतने तक ही सीमित होता है।

लोग अस्पताल में मरीज देखने जाते हैं, मरीज को तीन-चार दिन वहीं भर्ती रहना है, फिर भी क्या हो रा' है बोला जाता है! जिससे बोला गया, वह क्या कहे-हाथ में ग्लूकोज लगा है; इंजेक्शन से दर्द है; दवा से मुंह कड़वा है; अस्पताल में घुटन है और तुझ गधे को लात मारकर कमरे से बाहर निकालने का मन है आदि, आखिर क्या बताया जाए, लेकिन क्या हो रा' है, के जपतु को सब जानना है, यह उसे तुष्टि देता है! अस्पताल आए मरीज देखने और सब ना जाना, तो फिर आने का फायदा क्या हुआ भला, इसलिए क्या हो रा' है हमेशा फायदे का सौदा भी है!

क्या हो रा' है, इस वाक्य में ही जिसे यह कहा जा रहा है, उससे दूरी प्रकट होती है! जो हमारा है या जिसके निकट हैं हम, उसका क्या-क्या हो रहा है, हमें पता ही होता है, परंतु जब हमें निकटता का दिखावा करना होता है, तो इस क्या हो रा' है का सहारा लिया जाता है! बहुधा इस वाक्य को बोलने वाले को थोड़ा या सारा पता भी होता है कि जिससे यह बोल रहा हूं, उसके जीवन में यह हो रहा है, परंतु सामने जब भोक्ता है, तो क्या हो रा' है कहना ही बनता है। अब यदि सामने वाला निर्लिप्तता से बोल दे कि कुछ खास नहीं, तो प्राय: क्या हो रा' है का जपतु पलटकर कहता है- लेकिन हमने तो सुना था तो इससे जाहिर होता है कि क्या हो रा' है का जपतु, जो हो रहा है, उससे यत्किंचित पूर्व परिचित होता ही है!

सूचना के संजाल ने क्या हो रा' है को त्वरित बनाया है, इससे धैर्य और उसके संबद्ध सभी सकारात्मक, धराशायी हो चुका है। बहू द्वारा, ससुराल में जो हो रहा है, उसकी सूचना से लेकर समाचार माध्यम तक क्या हो रहा है, उसे तत्काल प्रसारित करते हैं, इसका शायद ही कभी सुफल रहा हो! हम नहीं जानते कि अनेक बार कुछ पता चलने से अधिक अच्छा, ना पता चलना ही है। अभी सुबह कोई इमारत गिरी, अभी मीडिया ने दिखाना शुरू किया; उम्मीद जताई कि इमारत के सब लोग दबकर मर गए। जिन-जिन के अपने उस इमारत में थे, उनके दिल की सोचिए! सोच-सोचकर कई को दिल का दौरा पड़ा और कई के प्राण ही पखेरू हो गए। अब शाम को मीडिया ने बताया कि अमुक-अमुक जीवित हैं! सुबह जिनके मरने की सुनकर कोई मर गया, वे शाम को जीवित निकले, यह क्या हो रा' है के तत्काल प्रसारण और उस प्रसारण को तत्काल सच मानने का दुष्फल है! हाल ही में एक नशेड़ी अभिनेता की आत्महत्या को हत्या बताकर उसकी लिवइन गुमनाम लुटेरी अभिनेत्री को प्रसार माध्यम हत्यारी बनाने पर तुले थे; प्रतिदिन क्या हो रहा है को नेशनल न्यूज बनाकर प्रसारित किया जा रहा था, सारा देश क्या हो रा' है के नशे में डूबा था कि प्रमुख जांच एजेंसी ने घोषणा कर दी- अभिनेताजी ने आत्महत्या ही की थी! कितना समय और ऊर्जा क्या हो रा' है पर बर्बाद की गई, शायद ही किसी ने विचारा हो! कोरोना के लॉकडाउन में यदि हॉस्टल में रह रहा विद्यार्थी सुदूर अपने घर अपनी हड्डी टूटने या साधारण बुखार की भी सूचना दे, तो अंदाजा लगाया जा सकता है, माता-पिता का क्या हाल होगा! ऐसे में क्या हो रा' है को ना बताना धर्म है! अपने एक सर्विस संबद्ध केस के सिलसिले में मेरा दूसरे शहर के एक न्यायालय में जाना होता था। आजकल कोर्ट का केस नंबर डिस्प्ले बोर्ड पर लोग देखते ही रहते हैं। इधर केस में सुनवाई हुई, उधर मेरे मोबाइल का वाइब्रेट होना शुरू, अनंत ज्ञात-अज्ञात लोग क्या हो रा' है जानना चाहते थे। मुझे वकील से बात करनी होती थी, फिर स्टेशन तक की भागदौड़, परंतु क्या हो रा' है के जिज्ञासु लगातार फोन करते रहते थे। ये सभी वे लोग थे, जिन्हें सिर्फ सूचना चाहिए थी और यहीं तक मैं उनका 'अपना' था, जबकि मेरे अपने पिताजी और सच्चे शुभचिंतक मित्र मेरे फोन का इंतजार करते थे। जीवन में सुख-दु:ख, दोनों हैं! हम यदि किसी को उसके कष्ट में सहयोग नहीं कर सकते, तो उसके जीवन में क्या हो रहा है, यह जानने का हमें कोई अधिकार नहीं है! अब, यह बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, परंतु जब तक यह सृष्टि रहेगी, तब तक क्या हो रा' है के जिज्ञासु भी इस धरा पर रहेंगे ही, इसमें दो मत नहीं है। सो क्या हो रा' है ही वो मंत्र है, जो तिल का ताड़ बना, वह भी बना सकता है और प्राय: बनाता ही है, जो या जितना होता नहीं है, बस यही ध्यान रखने की बात है! वैसे, सुनिए, नाराज ना होइए, बस जाते-जाते, आप तो कहिए-क्या हो रा' है!!

● डॉ. सम्राट् सुधा

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

Science House Medicals Pvt.Ltd.

17/1, Sector-1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal (M.P.) INDIA-462023

GST. No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbpl@rediffmail.com

PH. : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

RK GROUP

"जो कल था...
वही कल भी रहेगा,
यह मैं नहीं वक़्त कहेगा"

SHURUAAT KARO KUCH *Smart* KARO

WONDER
CEMENT
EK PERFECT SHURUAAT

Toll-free No.: 1800 31 31 31 | www.wondercement.com